

2020-21 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने महामारी से उत्पन्न व्यवधान के बावजूद अपनी आस्ति गुणवत्ता, पूंजी बफर और लाभप्रदता में प्रत्यक्ष सुधार रिपोर्ट किया। हालांकि ऋण मांग सुस्त रही, देयता पक्ष में उच्च जमाराशि वृद्धि और आस्ति पक्ष में निवेश में वृद्धि एक समान थे। बहरहाल, प्रारम्भिक दबाव उच्चतर पुनर्गठित अग्रिमों के रूप में बना हुआ है। नीति समर्थन के समाप्त होने पर बैंकों को संभावित दबाव को अवशोषित करने के साथ-साथ ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा।

1. भूमिका

IV.1 वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र ने महामारी और आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न व्यवधान का रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों से प्राप्त समर्थन के कारण लचीलेपन के साथ सामना किया। आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ जो कि आंशिक रूप से आस्ति वर्गीकरण में रोक लगाने के परिणामस्वरूप है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पाँच वर्षों के अंतराल के बाद निवल लाभ दर्ज किया। सामान्य रूप से बैंकों की पूंजी स्थिति में सरकार द्वारा पुनर्पूजीकरण और बाज़ार से निधि जुटाने से मिली आंशिक सहायता के चलते सुधार हुआ। बहरहाल, पुनर्गठित अग्रिमों के बढ़े हुए हिस्से और महामारी से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से उत्पन्न उच्च रिसाव के रूप में प्रारम्भिक दबाव बने हुए हैं। तथापि, 2020-21 की पहली छमाही में बहाली के संकेत के पुनः उभरने के कारण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को और भी मजबूत बनाएँ।

IV.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2020-21 तथा 2021-22 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन और प्रदर्शन संबंधी चर्चा की गई है। खंड 2 में तुलन-पत्र गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है जिसके बाद उनके वित्तीय प्रदर्शन और सुदृढ़ता संकेतक का मूल्यांकन क्रमशः खंड 3 एवं 4 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 5 से खंड 12 में ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन, बैंकिंग स्टॉक का प्रदर्शन,

स्वामित्व के स्वरूप, कॉर्पोरेट अभिशासन एवं क्षतिपूर्ति प्रथाएँ, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन, भुगतान प्रणाली की गतिविधियाँ, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन से संबन्धित विशिष्ट विषयों को दर्शाया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) तथा भुगतान बैंक (पीबी) से संबन्धित गतिविधियों का विश्लेषण अलग से खंड 13 से खंड 16 में किया गया है। अध्याय के अंत में विश्लेषण के प्रमुख मुद्दों और प्रगामी दृष्टिकोण को एक साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. तुलन-पत्र विश्लेषण

IV.3 महामारी और वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों में संकुचन के बावजूद 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन-पत्र में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जमाराशि वृद्धि आस्ति पक्ष में निवेश के समान रही; हालांकि ऋण मांग सुस्त रही (सारणी IV.1 और चार्ट IV.1)। पर्यवेक्षी आंकड़ें दर्शाते हैं कि हालांकि ऋण वृद्धि में सुधार के प्रारंभिक चिह्न दृश्य हैं, 2021-22 में अब तक जमाराशि वृद्धि धीमी रही।

IV.4 वर्ष 2010-11 से कुल अग्रिमों और जमाराशियों में पीएसबी की हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. पूंजी	72,040	59,328	26,866	30,641	85,710	91,465	5,151	5,375	1,035	1,300	1,90,802	1,88,109
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	5,80,886	6,49,142	5,81,749	7,07,345	1,08,987	1,24,706	11,047	14,800	-461	-704	12,82,208	14,95,289
3. जमाराशियां	90,48,420	99,00,766	41,59,044	48,00,646	6,84,239	7,77,173	82,488	1,09,472	855	2,543	1,39,75,045	1,55,90,600
3.1. मांग जमाराशियां	5,71,383	6,84,451	5,47,521	6,82,095	2,17,825	2,37,412	2,381	3,964	8	19	13,39,118	16,07,941
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	30,41,902	34,62,923	11,72,739	14,56,019	70,007	87,032	10,284	22,198	847	2,524	42,95,779	50,30,696
3.3. मीयादी जमाराशियां	54,35,134	57,53,392	24,38,784	26,62,532	3,96,408	4,52,729	69,823	83,310	-	-	83,40,149	89,51,963
4. उधारियाँ	7,09,780	7,18,850	8,27,575	6,25,683	1,28,761	1,02,331	30,004	27,828	-	198	16,96,120	14,74,890
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	3,71,706	4,03,292	2,36,890	2,66,732	2,57,381	1,68,893	4,057	6,076	216	737	8,70,250	8,45,729
कुल देयताएँ आस्तियां	1,07,82,831	1,17,31,378	58,32,123	64,31,048	12,65,079	12,64,567	1,32,747	1,63,552	1,645	4,072	1,80,14,425	1,95,94,617
	(59.9)	(59.9)	(32.4)	(32.8)	(7.0)	(6.5)	(0.7)	(0.8)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(100.0)
1. आरबीआई में धारित नकदी और जमाशेष	4,36,774	5,39,149	2,72,616	2,92,019	51,238	59,163	5,058	6,921	33	174	7,65,720	8,97,426
2. बैंकों में धारित जमाशेष और मांग तथा अल्पकाल में देय मुद्रा	4,66,615	5,93,721	2,12,324	2,73,711	99,468	1,51,549	8,701	12,309	455	812	7,87,563	10,32,102
3. निवेश	29,40,636	34,00,895	12,93,031	15,12,480	4,31,277	4,73,418	24,203	30,660	694	2,413	46,89,842	54,19,866
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	24,09,182	27,89,985	10,66,313	12,57,222	3,84,102	4,30,779	20,748	27,142	694	2,412	38,81,039	45,07,541
क) भारत में	23,71,783	27,52,716	10,57,074	12,36,747	3,62,540	3,90,195	20,748	27,142	694	2,412	38,12,839	44,09,212
ख) भारत से बाहर	37,399	37,270	9,240	20,476	21,562	40,584	-	-	-	-	68,201	98,329
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	102	12	-	-	-	-	-	-	-	-	102	12
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में	5,31,352	6,10,898	2,26,718	2,55,258	47,175	42,639	3,455	3,518	-	1	8,08,700	9,12,313
4. ऋण और अग्रिम	61,58,112	63,48,758	36,25,154	39,39,292	4,28,076	4,23,546	90,554	1,08,613	-	0.1	1,03,01,897	1,08,20,208
4.1 खरीदे और भुनाये गए बिल	1,60,977	1,45,894	1,25,111	1,19,295	59,273	60,380	37	124	-	-	3,45,398	3,25,694
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	24,16,408	24,91,776	9,70,317	10,11,497	2,07,717	1,75,337	6,872	8,861	-	-	36,01,314	36,87,471
4.3 मीयादी ऋण	35,80,727	37,11,087	25,29,726	28,08,501	1,61,085	1,87,828	83,646	99,628	-	0.1	63,55,184	68,07,043
5. अचल आस्तियां	1,06,507	1,06,826	38,268	39,713	4,129	4,457	1,671	1,676	200	222	1,50,775	1,52,894
6. अन्य आस्तियां	6,74,187	7,42,030	3,90,729	3,73,832	2,50,891	1,52,434	2,559	3,373	263	452	13,18,629	12,72,121

टिप्पणियां: 1. शून्य / नगण्य

2. संख्याओं को करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण घटकों का जोड़ उनसे संबन्धित जोड़ से भिन्न हो सकता है।

3. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा का मिलान किया जाता है और भारत में बैंकों से संबन्धित सांख्यिकीय सारणियों में प्रकाशित की जाती है। यह <https://www.dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध है।

4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों में विभिन्न बैंक समूहों की कुल आस्तियां/देयताओं का हिस्सा हैं।

स्रोत: संबन्धित बैंकों का वार्षिक लेखा

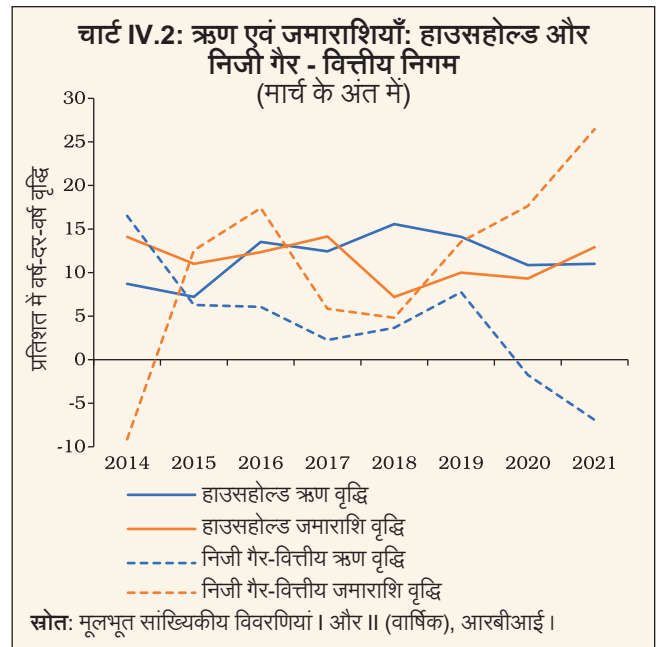
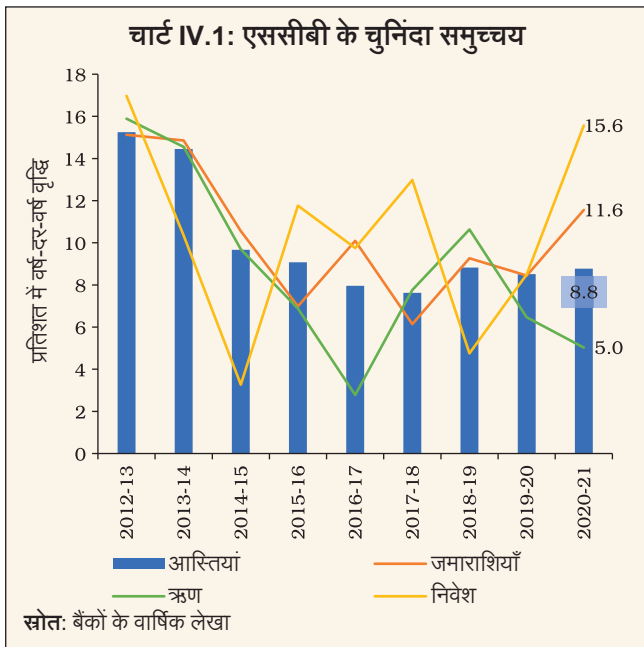
2.1 देयताएँ

IV.5 वर्ष 2020-21 के दौरान, एससीबी के द्वारा जमाराशि का संग्रहण इन 7 वर्षों में सर्वाधिक रहा जिसमें निम्न लागत वाले चालू एवं बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों का प्रमुख योगदान रहा (चार्ट IV.4)। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में आर्थिक

गतिविधियों में सामान्यीकरण और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ जमाराशि वृद्धि में कमी आई।

IV.6 पिछले तीन वर्षों में, निजी गैर- वित्तीय निगम एससीबी के साथ अपनी जमाराशि नियत रूप से बढ़ाने के कारण निवल बचतकर्ता रहे हैं, जबकि उनकी ऋण मांग में कम वृद्धि रही। इसके अलावा, हाउसहोल्ड क्षेत्र की जमाराशि-जो कि मार्च

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2020-21

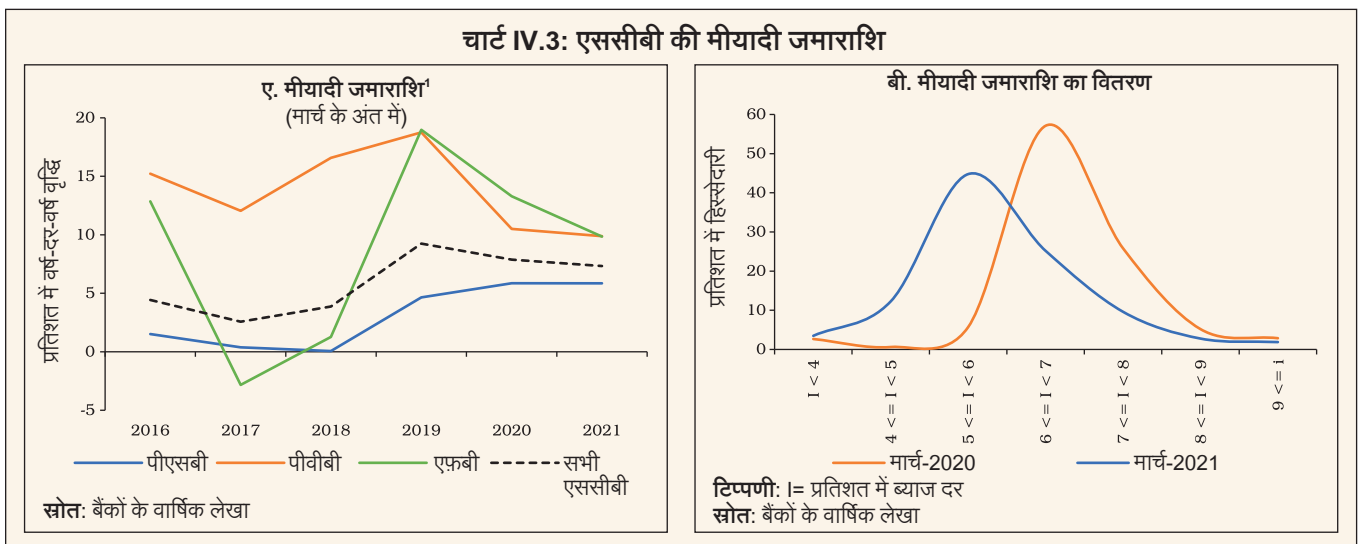


2021 के अंत में कुल की 64 प्रतिशत थी- ने भी गति पकड़ी (चार्ट IV.2)।

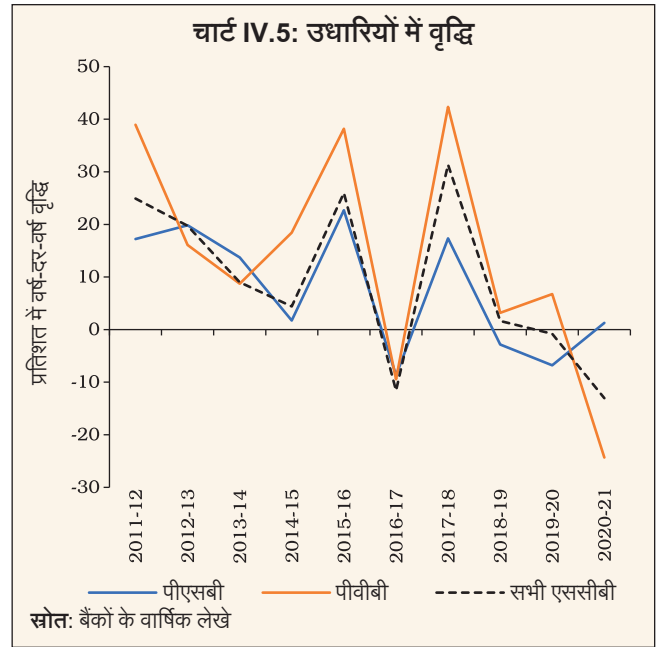
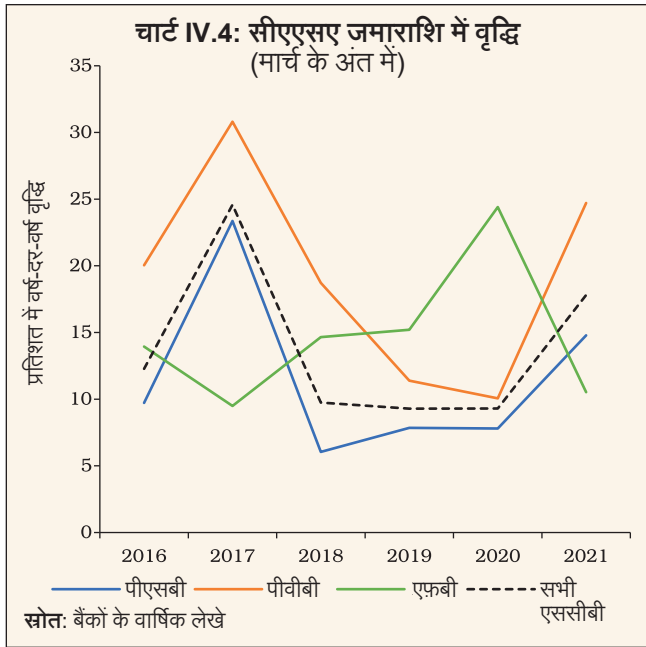
IV.7 सभी क्षेत्रों में मीयादी जमाराशि की दरों में गिरावट के कारण 2020-21 के दौरान उनकी वृद्धि मंद रही (चार्ट IV.3ए)। तदनुसार, मॉडल क्लास के रूप में उभरने वाली 5-6 प्रतिशत

ब्याज दर के साथ सभी ब्याज दरों में उनका वितरण बाईं ओर शिफ्ट हो गया।

IV.8 ऐतिहासिक रूप से पीवीबी ने अपनी जमाराशि को समर्थन देने के लिए और ऋण वृद्धि को बढ़ाने के लिए उधारों पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, पीएसबी ने अपने



¹ बैंक-समूह वार वृद्धि दर प्रदर्शित करने वाले चार्ट के लिए, निम्नलिखित समायोजन किए गए हैं: i) 21 जनवरी 2019 से प्रभावी से आईडीबीआई बैंक लि. के पुनर्वर्गीकरण के बाद इसे पीएसबी समूह से हटाकर पीवीबी समूह में शामिल किया गया है। मार्च 2019 से दिसम्बर 2019 तक बैंक-समूह वार वृद्धि दर पर डेटा समायोजित बैंक- समूह जोड़ पर आधारित है। ii) 27 नवम्बर 2020 से प्रभावी लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया के साथ समामेलन के बाद निजी एवं विदेशी बैंक- समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक- समूह जोड़ पर आधारित है।



उधारों को पोषित करने के लिए अपने विस्तृत जमाराशि आधार और निम्न लागत वाली सीएएसए जमाराशि की उपलब्धता का लाभ उठाया। 2020-21 में पीवीबी के उधार में 2016-17 के बाद पहली बार संकुचन आया, जबकि लगातार दो वर्षों के संकुचन के बाद पीएसबी के उधार राशि में वृद्धि हुई। सीएएसए जमाराशि में ठोस वृद्धि के बावजूद, पीएसबी ने पिछले वर्ष की तुलना में उधार के माध्यम से अधिक संसाधनों को जुटाया

क्योंकि उनकी ऋण वृद्धि वर्ष के प्रथम तीन तिमाहियों में बढ़ी (चार्ट IV.5)।

2.2 आस्तियां

IV.9 एससीबी के ऋण वृद्धि में पिछले दो वर्षों में कमी आई जो कि मुख्य रूप से कम मांग की स्थिति और जोखिम का विरोध दिखाता है (बॉक्स IV.1)। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बहाली के संकेत दिखाई देने लगे।

बॉक्स IV.1: ऋण वृद्धि में कमी : मांग या आपूर्ति द्वारा संचालित

पिछले कुछ वर्षों में ऋण वृद्धि में निरंतर कमी ने इसके अंतर्निहित कारणों पर नीति-निर्माताओं और विश्लेषकों के बीच गहन विवाद उत्पन्न किया।

असमान सूचना की उपस्थिति में, ऋण के ब्याज दरों की स्थिरता के कारण मूल्य समायोजन में देरी होती है। अन्तरिम रूप से, जब भी मौजूदा ब्याज दर पर आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाती तब असंतुलन हो सकता है (स्टिगलिट्ज़ एंड विस्स, 1981)। संप्रेक्षित ऋण $सि_{t}^{अ}$ को ऋण के अनुमानित मांग ($सि_{t}^{अ}$) और ऋण की अनुमानित आपूर्ति ($सि_{t}^{अ}$) का न्यूनतम मान लिया जाता है।

$$सि_{t}^{अ} = \min(सि_{t}^{अ}, सि_{t}^{अ})$$

असंतुलन मॉडल का अनुमान मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड (एमएलई) द्वारा किया जाता है। यह मॉडल संभावनाओं के निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है जिसके साथ प्रत्येक प्रेक्षण या तो मांग या आपूर्ति समीकरण (मदाला और नेल्सन, 1974) से संबंधित है।

अप्रैल 2001 से मार्च 2020 की अवधि के मासिक डेटा का प्रयोग करते हुए भारत के लिए असंतुलन मॉडल का निर्धारण किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) को बाजार समाशोधन ब्याज दर के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया है जबकि ऋण का लघुगणक आश्रित चर के रूप में लिया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि ऋण में कमी सिजर इफेक्ट को प्रतिबिम्बित करते हैं। औद्योगिक गतिविधि (आईआईपी) और निवेश (जीएफसीएफ) ने ऋण के मांग को कम किया जबकि बैंकों के दबावग्रस्त तुलन पत्रों² ने ऋण की आपूर्ति को सीमित किया (सारणी 1)। इसलिए, ऐसी नीतियां जिनका लक्ष्य सकल मांग को बढ़ाना है उन्हें बैंक के तुलन पत्रों को मजबूत करके समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि ऋण वृद्धि के सतत विकास पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके।

(Contd...)

² दबावग्रस्त आस्तित्व अनुपात (एसएआर) के लैंगड वैल्यू से अनुमानित (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए और पुनर्गठित मानक अग्रिम)।

सारणी 1 : अनुमान के परिणाम

व्याख्यात्मक चर/आश्रित चर	लॉग ऋण (Model 1)	लॉग ऋण (Model 2)	Explanatory variables/ Dependent variables	लॉग ऋण (Model 1)	लॉग ऋण (Model 2)
ऋण मांग			ऋण आपूर्ति		
कॉस्टेंट	0.1339*** (0.0114)	5.6117*** (0.036)	कॉस्टेंट	0.0008 (0.0083)	-2.5247*** (0.0063)
बीपीएलआर_लैग 1	0.6222*** (0.0114)	2.8388*** (0.037)	टाइम ट्रेंड	-0.00004 (0.00002)	-0.0013*** (0.00005)
टाइम ट्रेंड	0.0021 (0.0022)	-0.0004 (0.001)	एसएआर_लैग 1	-0.0006 (0.0009)	-0.0062** (0.0029)
जीएफसीएफ_लैग 1		0.0253** (0.0129)	सीआरएआर_लैग 2	0.0006 (0.0011)	
आईआईपी_लैग 1	0.1488*** (0.0014)		लॉग_डिपॉजिट_लैग 1		1.4017*** (0.0124)
आईआईपी_लैग 2		0.0151 (0.019)	निधि लागत_लैग 1	0.0009 (0.0009)	
सेसेक्स वृद्धि	0.0287 (0.0177)		बीपीएलआर_लैग 1	0.0008 (0.0009)	-0.1051 (0.0807)
सीपीआई मुद्रास्फीति_लैग 1	0.9217*** (0.0003)		एक्यूआर डमी	0.0020 (0.0023)	-0.0249*** (0.0077)
बीपीएलआर_लैग 2	-0.5351*** (0.0114)	-1.4109*** (0.0373)	मांग समीकरण त्रुटि का मानक विचलन	1.1380*** (0.0005)	0.6042*** (0.0405)
एक्यूआर डमी		0.6648*** (0.0065)	मांग समीकरण त्रुटि का मानक विचलन	0.0073*** (0.00001)	0.0256*** (0.0001)
जीएफसी डमी	-0.2900*** (0.0002)		लॉग- लाइकलीहुड	1114.16	-658.63

टिप्पणी: 1. एक्यूआर: आस्तित्व गुणवत्ता समीक्षा; जीएफसी: वैश्विक वित्तीय संकट; स्ट्रेस: जीएनपीए और सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में पुनर्रचित मानक अग्रिम।
 2. लैग 1: एक अवधि से पीछे/ लैग; लैग 2: दो अवधि से पीछे/ लैग
 3. ***, **, और * क्रमशः महत्व के 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर को दर्शाते हैं।
 4. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े मानक त्रुटियाँ हैं।

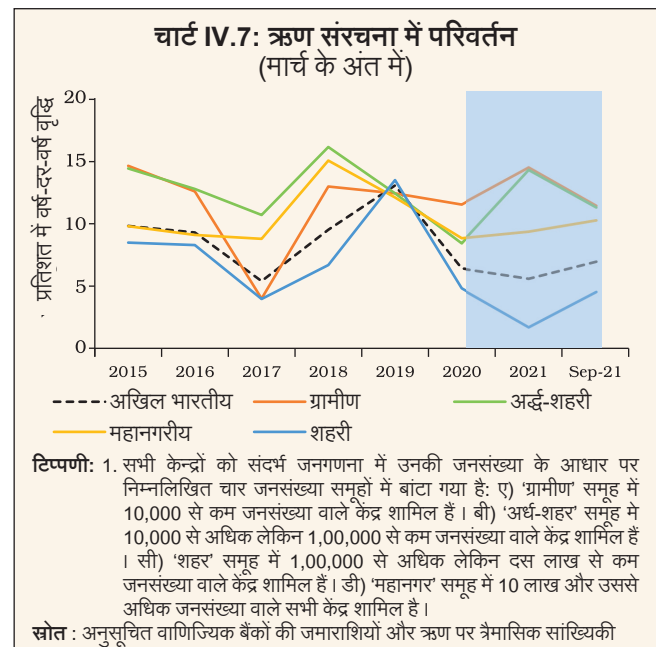
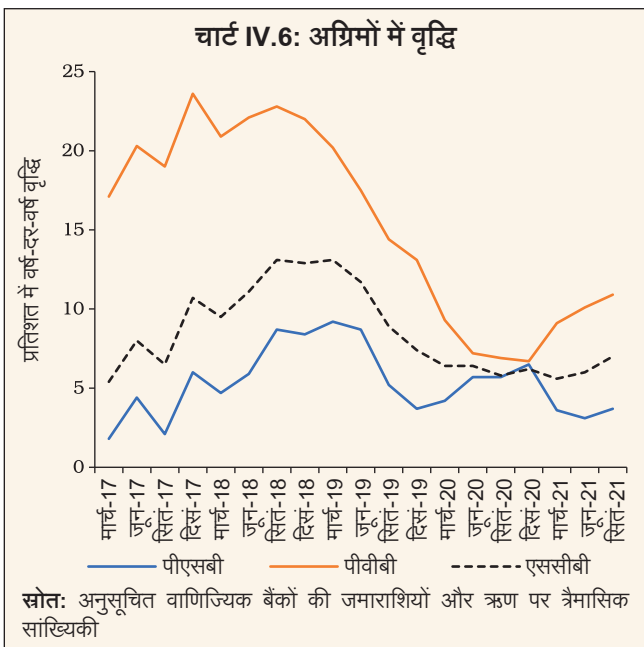
संदर्भ: मदाल्ला, जी.एस., और एफ. नेल्सन। 1974 मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड्स फॉर मॉडल्स ऑफ मार्केट्स इन डिसइक्विलिब्रियम। एकोनोमेट्रिका 42(6): 1013-1030।

स्टिग्लिट्ज, जोसेफ ई.; वीस, एंड्रयू (1981)। क्रेडिट रेशनिंग इन मार्केट्स विथ इम्पेरफेक्ट इन्फॉर्मेशन। द अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, 71 (3): 393-410।
 वर्मा, आर (2021)। स्लोडाउन इन क्रेडिट फ्लो इन इंडिया: सप्लाई ऑर डिमांड ड्रिवेन, मिमेओ।

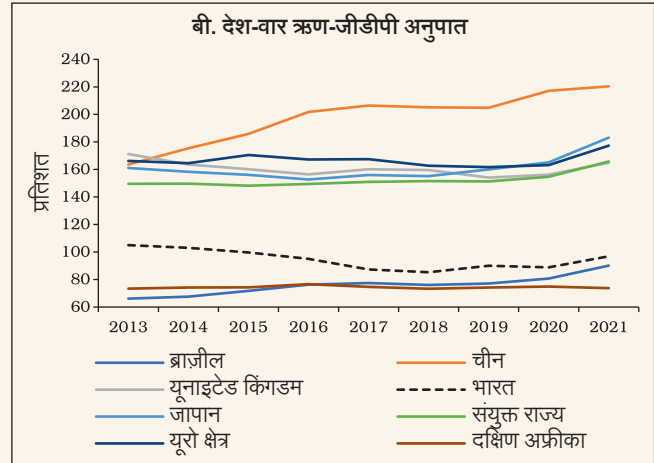
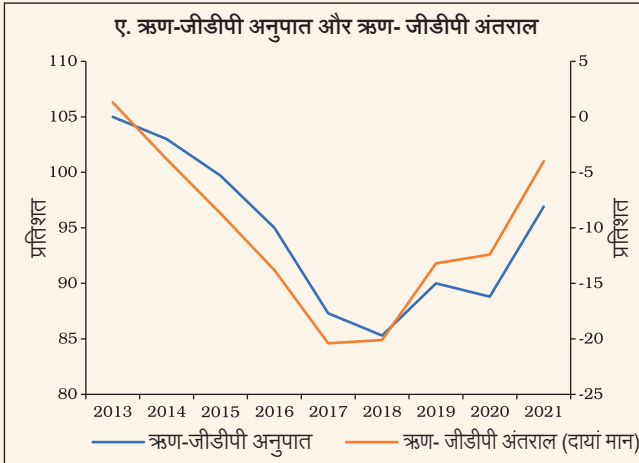
IV.10 वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही से 2020-21 की तीसरी तिमाही तक पीवीबी के ऋण वृद्धि में गिरावट आई क्योंकि महामारी ने भयावह रूप ले लिया था। हालांकि 2020-21 की

चौथी तिमाही से पीवीबी के ऋण पुनरुत्थान के संकेत दिखाई दिए (चार्ट IV.6)।

IV.11 जनसंख्या समूहों में, कोविड-19 के प्रकोप के बाद ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक ऋण वृद्धि एक



चार्ट IV.8: ऋण जीडीपी अनुपात



टिप्पणी: सभी स्रोतों से प्राप्त ऋण
स्रोत: बीआईएस

अच्छा संकेत है (चार्ट IV.7)। हालांकि पहुँच एवं सुगम्यता के कारण पीएसबी ग्रामीण उधार में मुख्य सहायक रहे, और साथ में पीवीबी की हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

IV.12 जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 5 वर्षों में सर्वाधिक रहा जिसके कारण ऋण- जीडीपी अंतराल में कमी आई (चार्ट IV.8ए)। जीडीपी की तुलना में भारत का ऋण अनुपात अभी भी जी 20 औसत की तुलना में स्पष्टतया कम है (चार्ट IV.8बी)।

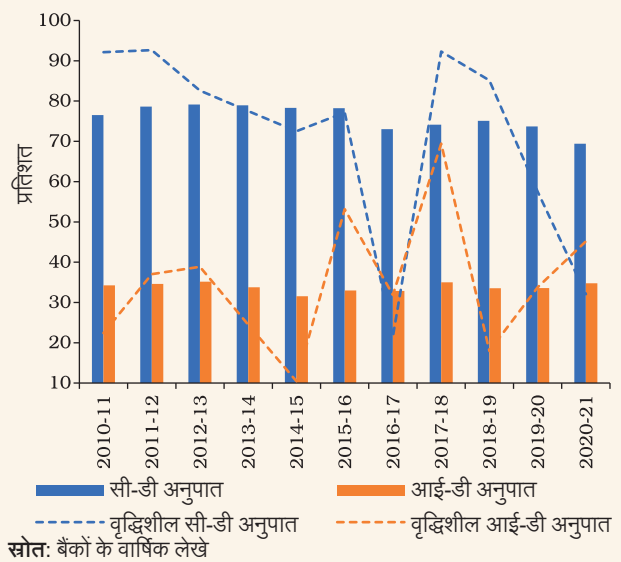
IV.13 एक तरफ जहाँ कुल आस्तियों में अग्रिमों की हिस्सेदारी कम हुई, जोखिम विरोध और सीमित लाभदायी उधार के अवसर के माहौल में निवेश की हिस्सेदारी बढ़ी। परिणामस्वरूप जमा की तुलना में ऋण (सी-डी) अनुपात में कमी आई और साथ ही निवेश की तुलना में ऋण (आई-डी) अनुपात में, विशेष तौर पर वृद्धिशील संदर्भों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.9)।

IV.14 वर्ष 2020-21 के दौरान पीएसबी और पीवीबी, दोनों ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को वरीयता दी जो कि सुरक्षित निवेशों में उनकी पसंद दर्शाता है। परिणामस्वरूप, पीएसबी की कुल पोर्टफोलियो में अन्य ऋण प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी लगातार तीन वर्षों तक बढ़ने के बाद कम हुई (चार्ट IV.10)।

2.3 आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

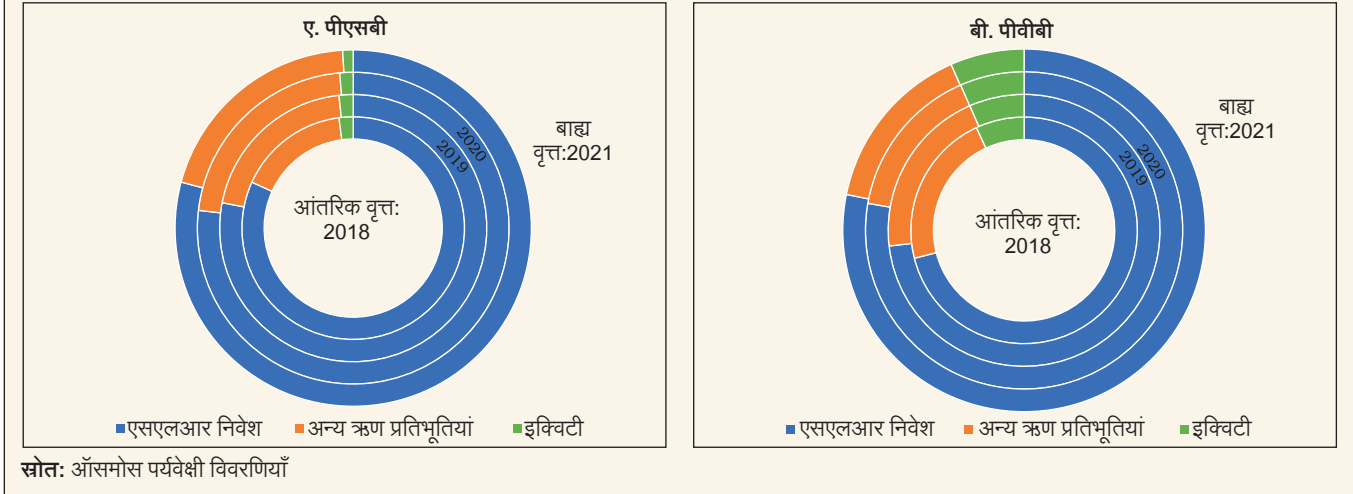
IV.15 आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता में असमानता बैंकिंग व्यवसाय में अन्तर्भूत हैं लेकिन उनका प्रभाव चलनिधि, लाभप्रदता और जोखिम एक्सपोजर पर पड़ता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, जहां एक वर्ष की परिपक्वता बकेट में नकारात्मक

चार्ट IV.9: ऋण- जमाराशि और निवेश- जमाराशि अनुपात



स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे

चार्ट IV.10 : निवेश पोर्टफोलियो
(मार्च अंत में)



अंतराल में कमी आई, वहीं दूसरी ओर पाँच वर्ष से अधिक की परिपक्वता बकेट के सकारात्मक अंतराल नकारात्मक हो गए क्योंकि बैंकों द्वारा अल्पावधि सीएएसए जमाराशियों को अधिक और दीर्घावधि जमाराशियों को कम स्वीकारा गया (चार्ट IV.11)।

IV.16 उधार के मामलों में पीएसबी और पीवीबी ने व्यापक रूप से विपरीत पैटर्न प्रदर्शित किया। पीएसबी के मामले में

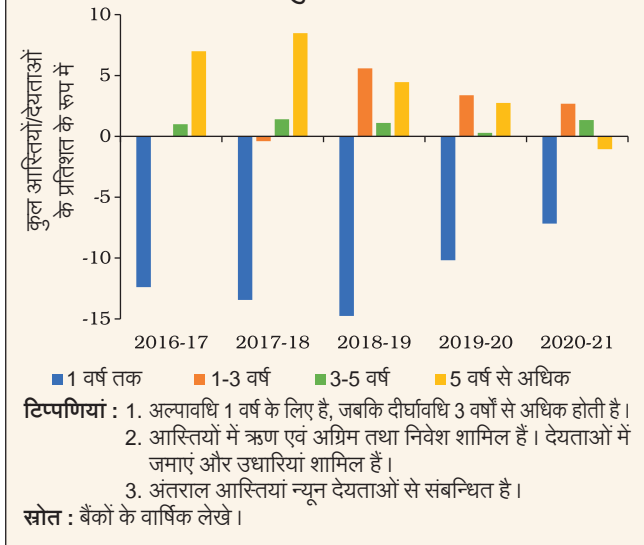
अल्पावधि एवं दीर्घावधि उधारों की हिस्सेदारी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जबकि पीवीबी एक से पाँच वर्षों के बीच के परिपक्वता वाले उधारों पर अधिक निर्भर रहे (सारणी IV.2)।

2.4 अंतर्राष्ट्रीय आस्तियाँ और देयताएँ

IV.17 वर्ष 2020-21 में भारत में स्थित बैंकों की कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के द्वारा धारित रुपये मूल्यवर्ग की जमाराशि और इक्विटी के कारण वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.9)। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों में बड़ी वृद्धि उनके ऋण और कर्ज प्रतिभूतियों के कारण थी (परिशिष्ट सारणी IV.10)। हालांकि, भारत में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियाँ उनकी अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में केवल 42 प्रतिशत ही थी (चार्ट IV.12ए)।

IV.18 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय बैंकों (उनके देशी और विदेशी शाखाओं सहित) के दावे की हिस्सेदारी गैर-वित्तीय निजी संस्थाओं से शिफ्ट होकर अन्य बैंकों के पक्ष में गई (परिशिष्ट सारणी IV.11 और चार्ट IV.12बी)। अंतर्राष्ट्रीय दावों की देशी संरचना शीर्ष छः देशों में से पाँच देशों, जिनके पास भारतीय बैंकों के दावों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी, की हिस्सेदारी और अधिक बढ़ने के साथ स्थिर रही (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

चार्ट IV.11: विभिन्न परिपक्वता बकेट में आस्तियों और देयताओं के अनुपात के बीच अंतराल



सारणी IV.2: चुनिन्दा देयताओं/ आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/ देयताएं	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		एससीबी	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	40.4	36.2	38.1	34.3	63.9	62.4	59.6	53.6	10.0	13.0	40.9	37.0
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	22.8	21.9	28.1	28.9	28.3	30.8	37.5	42.1	90.0	87.0	24.8	24.7
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	10.2	11.3	8.5	9.2	7.7	6.7	0.7	1.7	-	-	9.5	10.3
डी) 5 वर्षों से अधिक	26.6	30.6	25.3	27.7	0.0	0.0	2.2	2.6	-	-	24.7	28.0
II. उधारियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	49.2	54.5	51.7	41.4	83.4	83.8	41.1	46.9	-	100.0	52.9	50.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	27.5	21.0	24.2	34.0	10.3	11.8	44.0	37.3	-	-	24.9	26.2
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	13.0	12.8	11.3	13.9	2.2	2.0	11.3	13.8	-	-	11.3	12.5
डी) 5 वर्षों से अधिक	10.2	11.7	12.8	10.6	4.2	2.4	3.6	2.1	-	-	10.9	10.4
III. ऋण एवं अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	25.1	24.8	32.3	32.2	61.4	55.4	38.1	41.8	-	100.0	29.3	28.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	40.9	36.9	33.6	34.1	19.3	22.7	42.4	34.0	-	-	37.4	35.3
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	10.9	14.9	12.7	12.8	7.1	9.1	9.0	11.0	-	-	11.4	13.8
डी) 5 वर्षों से अधिक	23.1	23.5	21.4	20.9	12.1	12.8	10.4	13.2	-	-	21.9	22.0
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	23.7	23.7	54.2	50.6	83.4	85.1	59.0	58.1	100.0	97.4	37.8	36.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	13.1	16.6	15.1	20.7	11.0	10.3	26.3	25.4	-	1.9	13.5	17.3
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	10.6	13.2	6.8	6.5	2.0	2.2	3.1	2.9	-	0.4	8.7	10.3
डी) 5 वर्षों से अधिक	52.7	46.4	23.8	22.2	3.6	2.4	11.6	13.6	-	0.2	40.0	35.6

टिप्पणियाँ: 1. शून्य/ नगण्य

2. पूर्णांकन किए जाने के कारण घटकों का योग 100 से भिन्न हो सकता है।

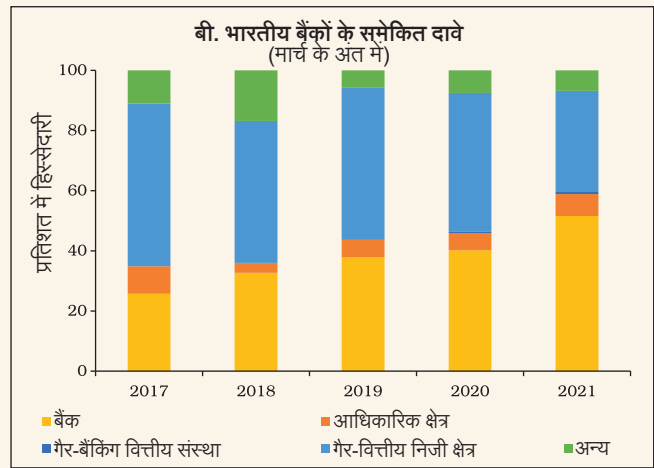
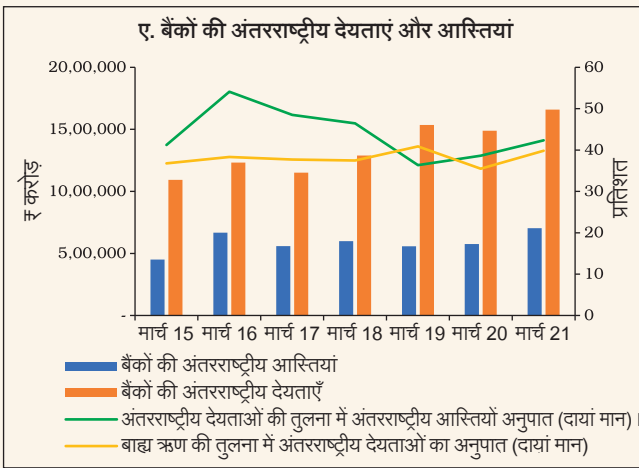
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे

2.5 तुलन-पत्रेतर परिचालन

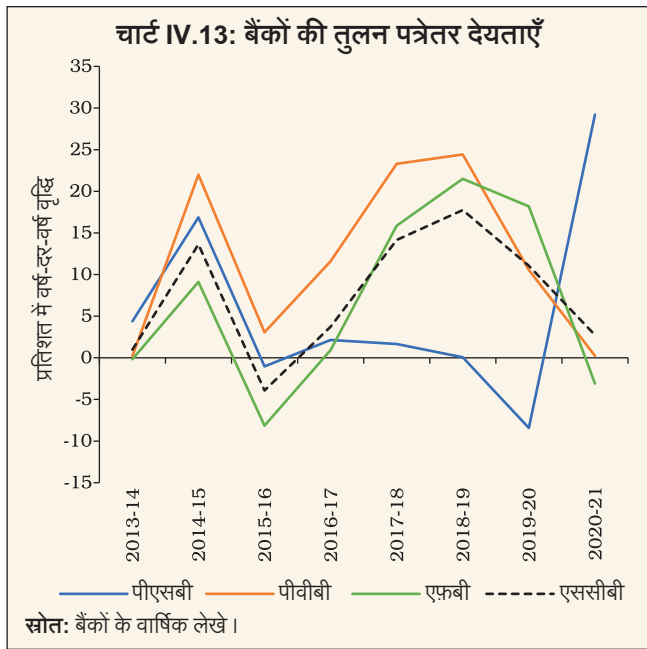
IV.19 पिछले वर्ष में बढ़ने के बाद, 2020-21 में सभी एससीबी की आकस्मिक देयताओं के आकार में उनके तुलन-पत्र के एक्सपोज़र के अपेक्षाकृत कमी आई। हालांकि पीएसबी की

हिस्सेदारी में बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि वायदा विनिमय संविदा (फॉरवर्ड एक्सचेंज कांट्रैक्ट) में, जिसमें सभी स्वीकार्य डेरिवेटिव उत्पाद शामिल हैं, 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि एफबी के लिए तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र में कमी आई, वे

चार्ट IV.12: भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां



Source: Annual accounts of banks and DBIE.



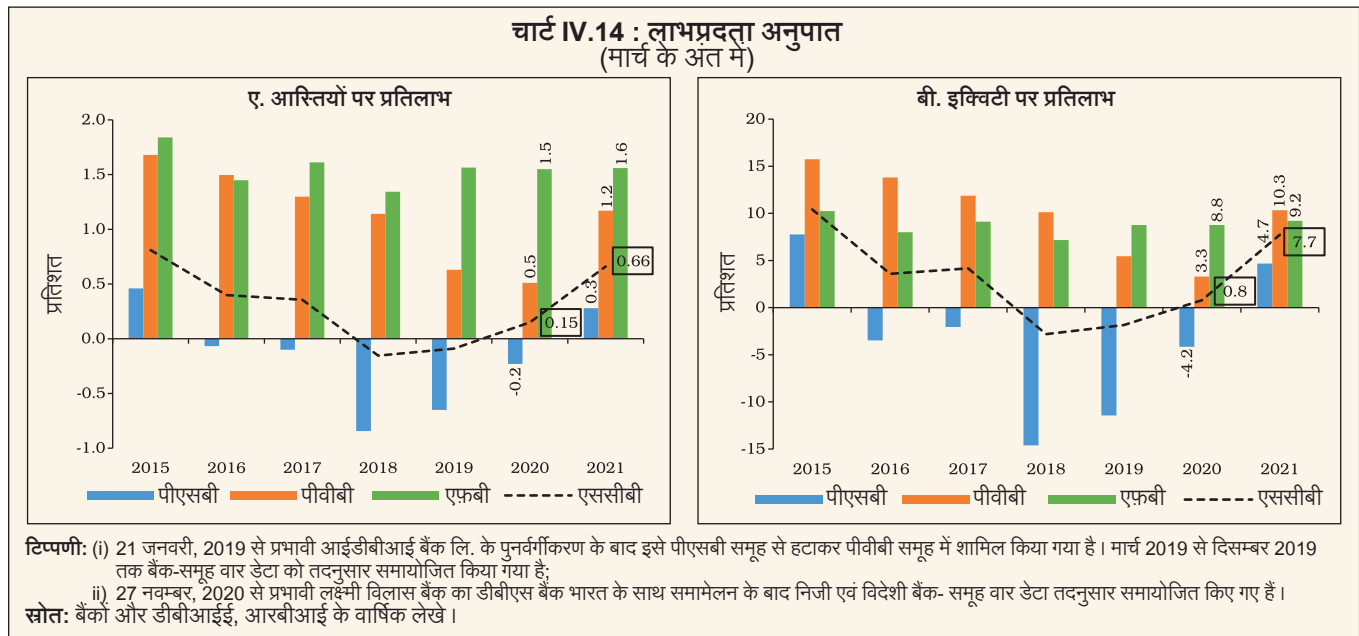
उनकी कुल देयताओं से नौ गुना अधिक रहे (चार्ट IV.13)। बैंकों की आकस्मिक देयताओं में समग्र गिरावट विदेशी मुद्रा लेनदेनों में गिरावट के अनुरूप बैंकों के वायदा विनिमय संविदाओं में नगण्य वृद्धि के कारण हुई (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.20 वर्ष 2020-21 के दौरान एससीबी का वित्तीय प्रदर्शन लाभप्रदता में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी से चिह्नित है क्योंकि उनकी आय स्थिर बनी रही लेकिन व्यय में गिरावट आई। यह पिछले 5 वर्षों की तुलना में बिल्कुल विपरीत था जिसके दौरान पीएसबी ने नुकसान दर्ज किया और पीवीबी की लाभप्रदता में कमी आ रही थी (चार्ट IV.14)।

IV.21 ऋण की मांग में कमी और न्यून ब्याज दरों द्वारा अभिलक्षित माहौल में ब्याज से होने वाली आय जैसे बृहद घटकों में मामूली गिरावट के बावजूद बैंकों की कुल आय स्थिर बनी रही (सारणी IV.3)। इस गिरावट को निवेशों से होने वाली आय में व्यापक बढ़ोतरी से सहायता प्राप्त हुई। व्यापार से होने वाली आय में भी वृद्धि हुई क्योंकि बैंकों को जी-सेक प्रतिफल में गिरावट के कारण लाभ हुआ।

IV.22 ब्याज दरों में कमी और कुल उधारों में संकुचन के कारण जमाराशियों पर दिये जाने वाले और उधार पर लिए जाने वाले ब्याज में गिरावट की वजह से एससीबी के व्यय में संकुचन हुआ। बैंक समूहों में, नीति दरों में परिवर्तन का मीयादी जमाराशि



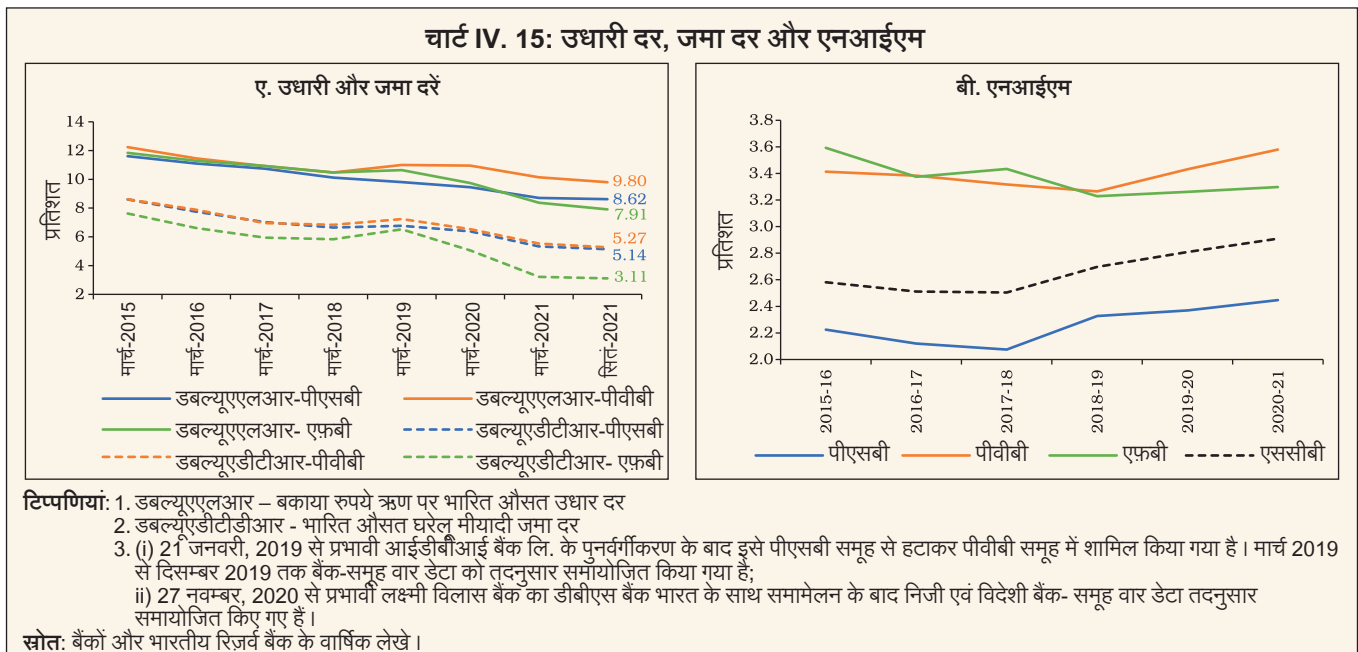
सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय में प्रवृत्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

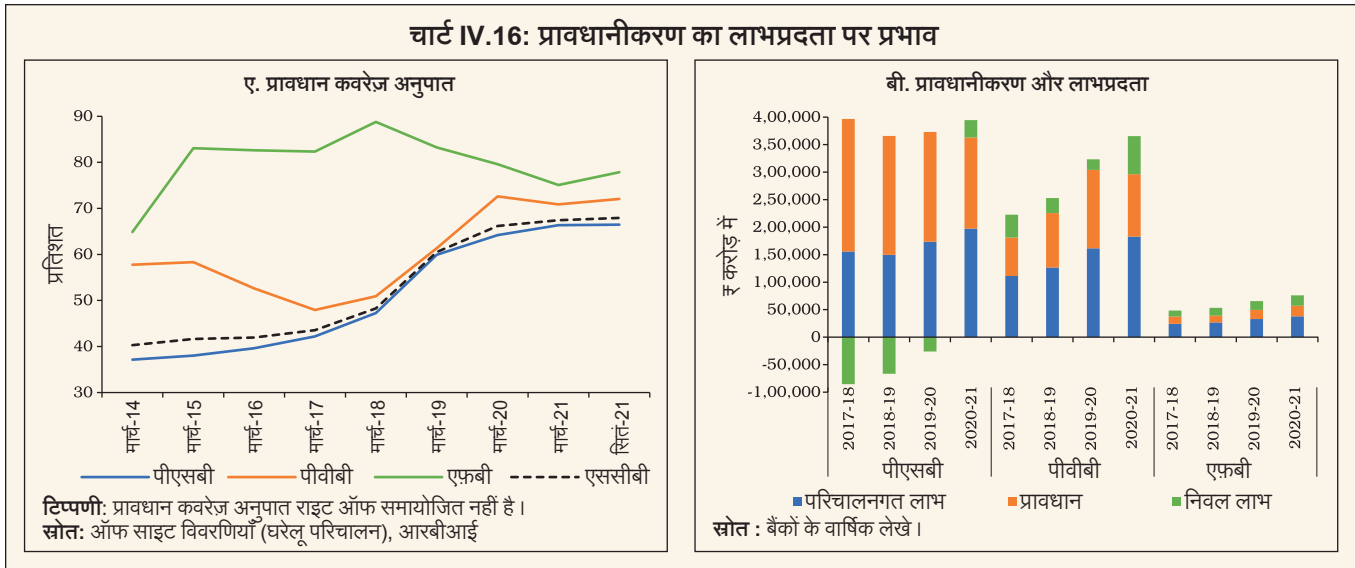
मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक#		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1. आय	8,34,320	8,31,882	5,46,347	5,45,833	83,223	82,081	19,219	22,500	55	1,004	14,83,164	14,83,301
ए) ब्याज से होने वाली आय	(7.6)	(-0.3)	(17.0)	(0.4)	(19.1)	(-4.3)	(76.4)	(17.1)	-	(1733.7)	(12.1)	(0.01)
बी) अन्य आय	7,16,203	7,07,092	4,49,006	4,51,617	66,673	63,888	16,948	19,523	46	101	12,48,876	12,42,222
बी) अन्य आय	(5.1)	(-1.3)	(14.1)	(1.1)	(20.0)	(-7.2)	(75.0)	(15.2)	-	(120.1)	(9.5)	(-0.5)
2. व्यय	1,18,117	1,24,790	97,341	94,216	16,550	18,193	2,271	2,976	9	903	2,34,288	2,41,079
ए) व्यय किया गया ब्याज	(26.0)	(5.6)	(32.6)	(-2.9)	(15.5)	(7.6)	(86.7)	(31.1)	-	(9932.3)	(28.2)	(2.9)
बी) परिचालनगत व्यय	8,60,335	8,00,064	5,27,236	4,76,357	67,043	63,116	17,251	20,462	389	1,304	14,72,253	13,61,303
ए) व्यय किया गया ब्याज	(2.2)	(-7.0)	(20.0)	(-9.1)	(21.0)	(-10.4)	(75.7)	(18.6)	-	(235.5)	(9.3)	(-7.5)
बी) परिचालनगत व्यय	4,68,005	4,31,627	2,58,038	2,32,555	28,810	21,769	7,928	9,122	14	55	7,62,794	6,95,128
जिसमें से: मजदूरी बिल	(3.9)	(-7.8)	(11.6)	(-9.3)	(17.7)	(-28.8)	(74.8)	(15.1)	-	(307.7)	(7.3)	(-8.9)
सी) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	1,92,720	2,02,879	1,26,663	1,30,456	21,584	22,318	7,152	7,549	488	1,251	3,48,607	3,64,453
जिसमें से: मजदूरी बिल	(10.1)	(5.3)	(15.9)	(3.6)	(15.4)	(-0.3)	(70.3)	(5.6)	-	(156.6)	(13.4)	(4.5)
सी) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	1,15,839	1,23,378	47,357	50,274	7,878	7,888	3,811	4,302	264	398	1,75,149	1,86,239
जिसमें से: मजदूरी बिल	(14.1)	(6.5)	(20.8)	(6.9)	(17.2)	(-4.0)	(79.2)	(12.9)	-	(50.6)	(17.1)	(6.3)
3. परिचालनगत लाभ	1,99,609	1,65,558	1,42,535	1,13,346	16,648	19,029	2,171	3,791	-112	-2	3,60,852	3,01,722
ए) परिचालनगत लाभ	(-7.7)	(-17.1)	(44.1)	(-20.0)	(36.2)	(8.9)	(100.8)	(74.6)	-	-	(9.9)	(-16.4)
4. निवल लाभ	1,73,594	1,97,376	1,61,646	1,82,823	32,829	37,994	4,139	5,829	-446	-302	3,71,763	4,23,720
ए) परिचालनगत लाभ	(16.0)	(13.7)	(27.8)	(13.1)	(22.8)	(15.8)	(91.4)	(40.8)	-	-	(21.9)	(14.0)
5. ब्याज से होने वाली निवल आय (एनआईआई)	-26,015	31,818	19,111	69,477	16,180	18,965	1,968	2,038	-334	-300	10,911	1,21,998
ए) परिचालनगत लाभ	(-30.8)	(248.3)	(11.5)	(23.6)	(81.9)	(3.5)	-	-	-	-	-	(1018.1)
5. ब्याज से होने वाली निवल आय (एनआईआई)	2,48,198	2,75,465	1,90,968	2,19,063	37,863	42,119	9,020	10,401	32	45	4,86,082	5,47,094
ए) परिचालनगत लाभ	(7.5)	(11.0)	(17.6)	(15.0)	(21.8)	(10.0)	(75.3)	(15.3)	-	(40.7)	(13.2)	(12.6)
6. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.37	2.45	3.43	3.58	3.26	3.30	8.34	7.02	1.95	1.58	2.81	2.91

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों को पिछले वर्ष के प्रतिशत घट-बढ़ के रूप में संदर्भित किया गया है।
 2. 27 नवम्बर 2020 से प्रभावी लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक भारत के साथ समायोजन के बाद निजी एवं विदेशी बैंक- समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक- समूह जोड़ पर आधारित है।
 3. निरपेक्ष संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है।
 4. एनआईएम को औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईआई के तौर पर परिभाषित किया गया है।
स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

दरों में संचरण एफबी के लिए सर्वाधिक था (चार्ट IV.15ए)। और इसलिए ब्याज से होने वाली निवल आय (एनआईएम) में वृद्धि हुई (चार्ट IV.15 बी)।



चार्ट IV.16: प्रावधानीकरण का लाभप्रदता पर प्रभाव



IV.23 बैंकों से अपेक्षित था कि वे अधिस्थगन राशि पर कम से कम 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान को बनाए रखें जिसे दो तिमाहियों अर्थात् 2019-20 की चौथी तिमाही और 2020-21 की पहली तिमाही तक बनाने की अनुमति दी गयी थी। अधिकतर बैंकों ने, विशेष तौर पर पीवीबी ने, अपेक्षित प्रावधानों की व्यवस्था मार्च 2020 तिमाही में ही कर दी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई। गिरावट में कमी के साथ इसने 2020-21 के दौरान प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को

कम किया जिससे बैंकों को लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई (चार्ट IV.16)।

IV.24 बैंकों की लाभप्रदता जो निधियों के प्रतिफल और निधियों की लागत के बीच मापे गए स्प्रेड के अनुसार है, जिसमें लागत में कमी के कारण प्रतिफल में सुधार हुआ जो पूर्व की तुलना में अधिक था। विशेष रूप से पीएसबी में सुधार प्रत्यक्ष था जबकि एसएफबी और पीबी श्रेणी में विशिष्ट बैंक स्प्रेड को बना कर नहीं रख पाए (सारणी IV.4)।

सारणी IV.4: निधियों की लागत और निधियों का प्रतिफल

बैंक समूह/ चर	वर्ष	जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों का प्रतिफल	निवेश का प्रतिफल	निधियों का प्रतिफल	दायरा
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5)
पीएसबी	2019-20	5.0	4.6	4.9	8.2	6.9	7.8	2.8
	2020-21	4.2	4.3	4.2	7.5	6.6	7.2	3.0
पीवीबी	2019-20	5.3	6.2	5.4	10.1	6.6	9.2	3.8
	2020-21	4.3	5.5	4.5	9.1	6.2	8.3	3.9
एफबी	2019-20	3.7	4.1	3.7	8.5	6.7	7.6	3.9
	2020-21	2.4	3.4	2.5	7.1	6.1	6.5	4.0
एसएफबी	2019-20	8.2	9.8	8.7	19.9	7.5	17.3	8.7
	2020-21	6.8	8.8	7.3	17.1	6.8	14.9	7.6
पीबी	2019-20	1.6	-	1.6	-	3.5	3.5	1.9
	2020-21	3.0	5.3	3.1	9.3	4.0	4.0	0.9
एससीबी	2019-20	5.0	5.4	5.0	8.9	6.8	8.3	3.2
	2020-21	4.2	4.9	4.2	8.1	6.4	7.6	3.3

टिप्पणियाँ: 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/ वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमाराशियों का ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्ष की उधारियों का औसत
3. निधियों की लागत = व्ययकृत ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष का औसत (जमाराशियाँ + उधारियाँ)
4. अग्रिमों का प्रतिफल = अग्रिमों से अर्जित ब्याज/ वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत
5. निवेश के प्रतिफल = निवेश से अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेश का औसत
6. निधियों पर प्रतिफल = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्ष का औसत (अग्रिम + निवेश)।
7. 27 नवंबर, 2020 से प्रभावी डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के समामेलन के बाद, निजी और विदेशी बैंक-समूह वार डेटा का तदनुसार समायोजन किया जाता है।

स्रोत: संबन्धित बैंकों के तुलन-पत्रों से परिकलित।

4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.25 वर्ष 2020-21 के दौरान, एससीबी ने अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत किया, और महामारी के बावजूद अपनी आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि और लीवरेज अनुपात में भी सुधार किया। रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत बैंकों की संख्या मार्च 2020 के अंत में चार से कम होकर सितंबर 2021 के अंत में एक हो गई, जो बैंक-स्तर के साथ-साथ एससीबी के सुदृढ़ता संकेतकों में समग्र सुधार दर्शाती है।

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.26 मार्च 2020 के अंत से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में प्रत्येक तिमाही में क्रमिक रूप से सुधार होते हुए सितंबर 2021 के अंत तक वह 16.6 प्रतिशत हुआ (सारणी IV.5)। यह अनिवार्य रूप से बैंक समूहों में मुख्य पूंजी में वृद्धि, उच्च प्रतिधारित आय, सरकार द्वारा पीएसबी के पुनर्पूजीकरण और बाजार से पूंजी जुटाने के कारण प्रेरित था। पीएसबी और एफबी दोनों के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के संचय में कमी ने उनके पूंजी अनुपात को बढ़ावा देने में मदद की।

IV.27 सीआरएआर (पूंजी संरक्षण बफर सहित) (10.875 प्रतिशत) की विनियामक न्यूनतम अपेक्षा का उल्लंघन करने वाले बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के तीन से घटकर 2020-21 के दौरान एक हो गई। 2019 की तुलना में मार्च 2021 के अंत में,

संवितरण में फैटर राईट टेल का तात्पर्य है कि बैंकों के एक बड़े हिस्से ने उच्च सीआरएआर और सीईटी-1 अनुपात बनाए रखा, जो न्यूनतम अपेक्षा से 2.5 से 5 प्रतिशत के बीच अधिक है (चार्ट IV.17)³। हालांकि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया था, बैंकों ने आसन्न संक्रमण की तैयारी में और अधिक पूंजी जुटाई।

IV.28 वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक और अधिकार निर्गम के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने में तेजी से वृद्धि हुई, जो अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीवीबी द्वारा इक्विटी पूंजी के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) को दर्शाता है (सारणी IV.6)।

IV.29 सितंबर 2020 में, संसद ने पीएसबी में ₹20,000 करोड़ की पूंजी लगाने को मंजूरी दी, जिसे 1 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से संवितरित कर दिया गया था। 2014 से, सरकार ने पीएसबी में ₹3.43 लाख करोड़ पूंजी लगायी है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने पीएसबी में ₹ 20,000 करोड़ की एक और किश्त देने का प्रस्ताव किया है, जो उनकी पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगा।

IV.30 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निजी स्थानन के माध्यम से जुटाए गए संसाधन 2020-21 के दौरान लगभग दोगुने हो गए। 2021-22 में अब तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पीवीबी

सारणी IV.5: एससीबी की घटकवार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

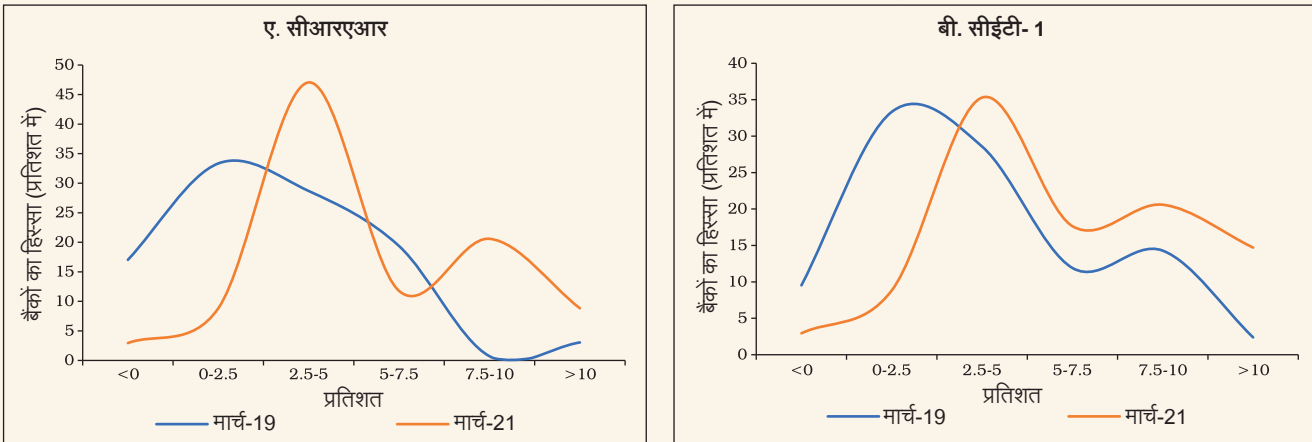
(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एससीबी	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. पूंजीगत निधि	6,99,872	7,93,971	6,54,772	7,72,389	1,88,665	2,04,433	15,56,686	17,90,330
i) टिआर I पूंजी	5,65,830	6,49,082	5,80,718	7,01,622	1,72,887	1,86,369	13,30,816	15,54,796
ii) टिआर II पूंजी	1,34,042	1,44,889	74,054	70,767	15,777	18,064	2,25,870	2,35,535
2. जोखिम भारित आस्तियां	54,46,253	56,56,060	39,56,956	41,92,303	10,65,889	10,49,878	1,05,35,311	1,09,86,622
3. सीआरएआर (1% के रूप में 2)	12.9	14.0	16.5	18.4	17.7	19.5	14.8	16.3
जिनमें से: टिआर I	10.4	11.5	14.7	16.7	16.2	17.8	12.6	14.2
टिआर II	2.5	2.6	1.9	1.7	1.5	1.7	2.1	2.1

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां, आरबीआई।

³ अपने सीआरएआर और सीईटी-1 लक्ष्यों को लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने वाले बैंकों के संवितरण में विषमता क्रमशः 2018-19 के 0.65 और 1.01 से क्रमिक रूप से घटकर क्रमशः 2019-20 में 0.23 और 0.52 तथा 2020-21 में (-)1.48 और (-) 0.35 हो गई।

चार्ट IV.17: न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं से दूरी



टिप्पणी: डेटा पीएसबी और पीवीबी से संबंधित है।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां, आरबीआई

दोनों ने पूंजी जुटाने के लिए इस मार्ग का सहारा लिया है (सारणी IV.8)।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.31 लीवरेज अनुपात (एलआर), जिसे टिअर-1 पूंजी के कुल एक्सपोजर के अनुपात के रूप में परिकलित किया जाता है, बैंकों द्वारा लीवरेज निर्माण को बाधित करता है। अक्टूबर 2019 में विनियामकीय गिरावट के बावजूद प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों और अन्य बैंकों के लिए पूर्व के 4.5 प्रतिशत के अनुपात की तुलना में क्रमशः 4 और 3.5 प्रतिशत अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा से, एससीबी का एलआर 2020-21 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा। जबकि सुधार सभी बैंक समूहों में फैला हुआ था, इसकी शुरुआत पीवीबी की टिअर -1 पूंजी में तेज सुधार से हुआ था (चार्ट IV.18 ए)।

सारणी IV.6: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक और अधिकार निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसबी		पीवीबी		कुल		कुल जोड़
	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8= (6+7)
2019-20	-	-	410	-	410	-	410
2020-21	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000
2021-22*	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियां: 1. *:नवंबर 2021 तक
2. -: शून्य/नगण्य

स्रोत: सेबी

IV.32 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - बैंकों को अल्पावधि में चलनिधि दबावों का सामना करने में मदद करने के लिए बनाया गया है - बैंकों से अपेक्षा है कि दबावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के निवल व्यय को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता चलनिधि आरिस्ट (एचक्यूएलए) बनाए रखें। मार्च 2020 में, बैंकों को तीन महीने के लिए उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त एक प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के नीचे सीमांत स्थायी सुविधा के तहत धन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को उनकी एलसीआर अपेक्षाओं को पूरा करने और उनकी चलनिधि आवश्यकताओं को पर्याप्त रखने के लिए इस छूट को क्रमिक रूप से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, एससीबी के लिए एलसीआर

सारणी IV.7: निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

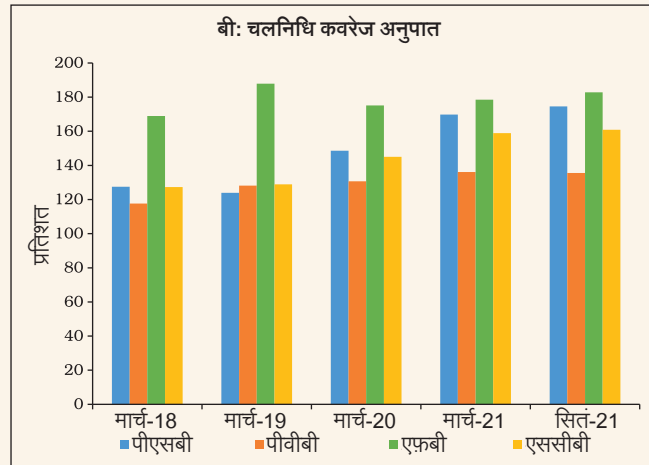
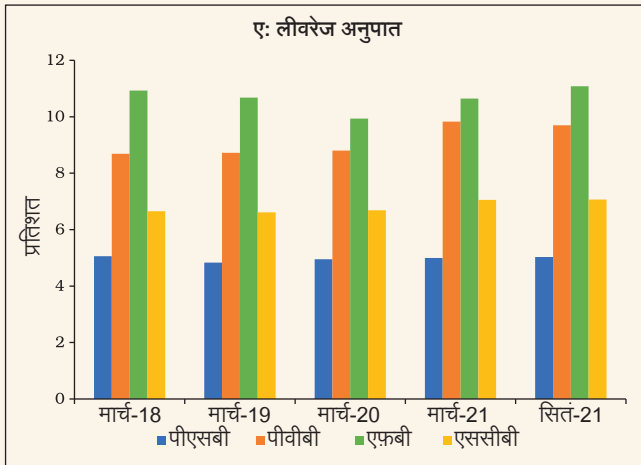
(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20		2020-21		2021-22 (नवंबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
पीएसबी	20	29,573	36	58,697	16	32,567
पीवीबी	8	23,121	4	33,878	5	17,222

टिप्पणी: इसमें कर्ज का निजी स्थानन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन शामिल है। 2021-22 का डेटा अनंतिम है।

स्रोत: बीएसई, एनएसई और मर्चेन्ट बैंकर्स

चार्ट IV.18: लीवरेज और चलनिधि



Source: Off-site returns (global operations), RBI.

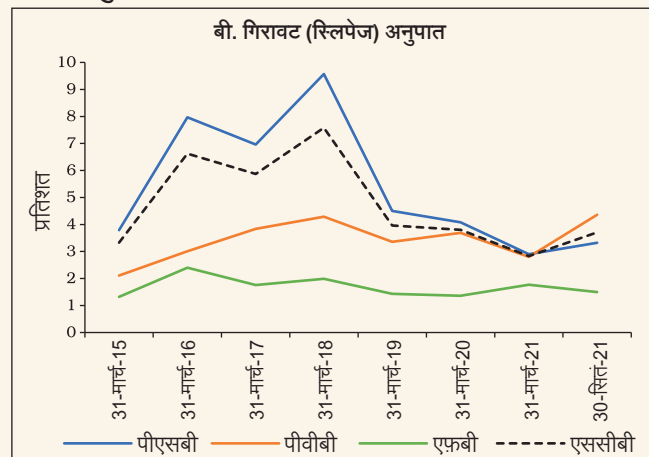
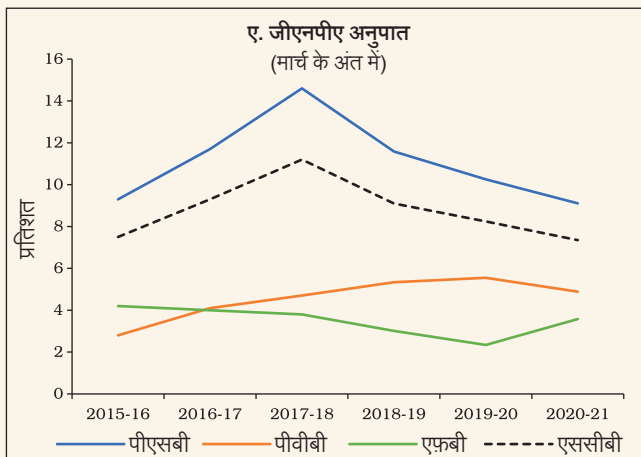
अपेक्षाओं को अप्रैल 2020 में 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था और धीरे-धीरे 1 अप्रैल 2021 तक दो चरणों में पूर्ववत कर दिया गया था। विनियामक छूट के बावजूद, बैंकों ने एलसीआर को 100 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखना जारी रखा: मार्च 2020 के अंत में यह अनुपात 145 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 158.9 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत तक 160.9 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.18 बी)।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.33 वर्ष 2019-20 से प्रारंभ बैंकों के जीएनपीए अनुपात में गिरावट समीक्षाधीन अवधि में जारी रही, जो मार्च 2021 के अंत

में 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गयी। अनंतिम पर्यवेक्षी डेटा के अनुसार अनुपात में और गिरावट हुई तथा सितंबर 2021 के अंत में वह 6.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, यह सुधार, आंशिक रूप से आस्ति वर्गीकरण पर रोक लगने से कम गिरावट के कारण हुआ। चूक आस्तियों में गिरावट के कारण, उनकी प्रावधान आवश्यकताओं में भी कमी आई और पीएसबी और पीवीबी का निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष से कम हो गया। इसके विपरीत, एफबी के साथ एक संकटग्रस्त पीवीबी के समामेलन के कारण एफबी के एनपीए में वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट हुई (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.19: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता



टिप्पणी: जीएनपीए अनुपात की गणना बैंकों के वार्षिक लेखों और ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन) का उपयोग करके की जाती है।
 स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ साइट विवरणियां

सारणी IV.8: अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी	पीवीबी	एफबी	एसएफबी	सभी एससीबी
सकल एनपीए					
2019-20 के लिए अंतिम शेष	6,78,317	2,09,568	10,208	1,709	8,99,803
2020-21 के लिए प्रारंभिक शेष	5,46,590	2,05,335	10,208	1,709	7,63,842
वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़ोतरी	2,78,711	1,03,625	12,840	5,470	4,00,646
वर्ष 2020-21 के दौरान कमी	74,685	38,824	4,698	377	1,18,584
वर्ष 2020-21 के दौरान बड़े खाते डाले गए#	1,34,000	69,995	3,307	832	2,08,134
वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम शेष	6,16,616	2,00,141	15,044	5,971	8,37,771
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए **					
2019-20	10.3	5.5	2.3	1.9	8.2
2020-21	9.1	4.9	3.6	5.4	7.3
निवल एनपीए					
2019-20 के लिए अंतिम शेष	2,30,918	55,683	2,005	765	2,89,370
2020-21 के लिए अंतिम शेष	1,96,451	55,809	2,987	2,981	2,58,228
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2019-20	3.7	1.5	0.5	0.8	2.8
2020-21	3.1	1.4	0.7	2.7	2.4

टिप्पणियां : 1. #: विवेकसम्मत के साथ-साथ वास्तविक राइट-ऑफ भी शामिल हैं।

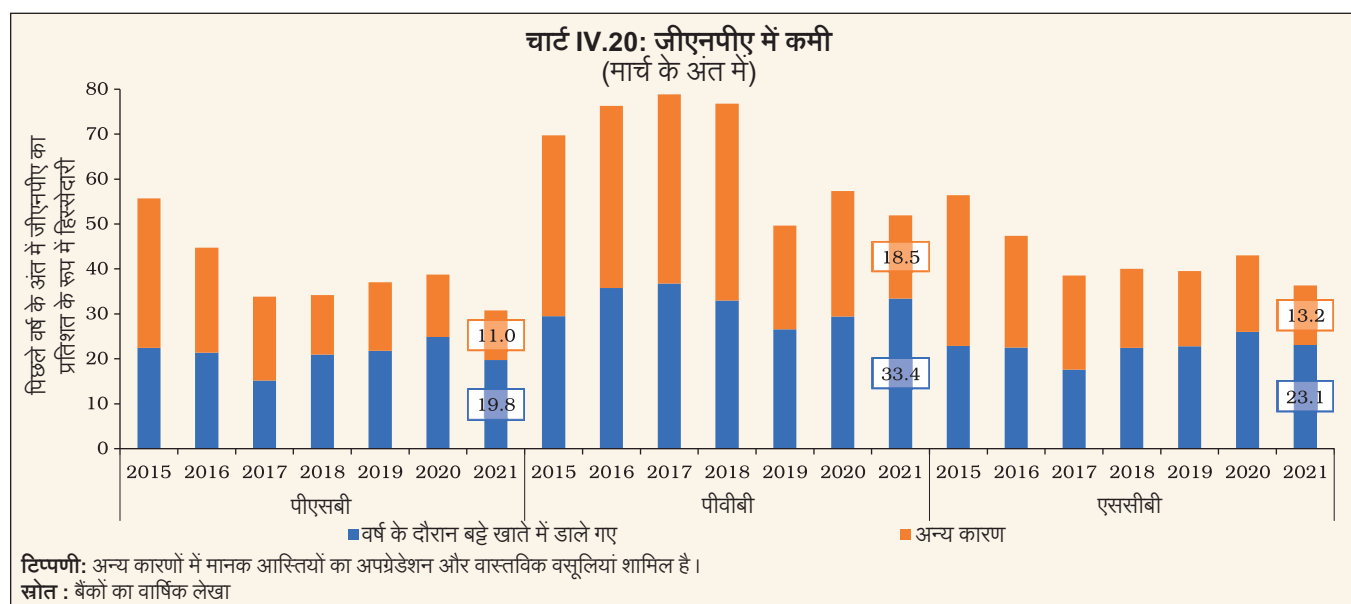
2. वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम शेष तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभिक शेष बैंकों के समामेलन के कारण मेल नहीं खाते हैं। समामेलित बैंकों का जीएनपीए “ वर्ष के दौरान योग “ के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है।

3. *: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा से सकल एनपीए और ऑफ साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन) से सकल अग्रिमों की गणना करते हुए।

स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखे और ऑफ साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई

IV.34 वर्ष 2018 से जैसे देखने को मिला है, 2020-21 में भी जीएनपीए को कम करने के लिए बड़े खाते में डालना प्रमुख उपाय था (सारणी IV.8 और चार्ट IV.20)। एफबी के मामले में, उन्नयन के योगदान में काफी सुधार हुआ, लेकिन यह नयी गिरावट को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

IV.35 आस्ति गुणवत्ता में सुधार के अनुरूप, एससीबी के कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात 2020-21 में बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण पीवीबी का बेहतर प्रदर्शन है (सारणी IV.9)। मानक आस्तियों में, पुनर्चित मानक अग्रिमों (आरएसए) की हिस्सेदारी मार्च 2020 के अंत में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 0.8 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से अगस्त



सारणी IV.9: बैंक समूहों द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च के अंत में	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
पीएसबी	2020	53,27,903	89.2	1,32,530	2.2	4,04,724	6.8	1,07,163	1.8
	2021	55,87,450	90.6	1,03,744	1.7	3,51,014	5.7	1,22,217	2.0
पीवीबी	2020	34,14,554	94.9	56,588	1.6	92,396	2.6	34,986	1.0
	2021	37,57,240	95.3	65,363	1.7	90,228	2.3	31,350	0.8
एफबी	2020	4,25,857	97.7	3,273	0.8	5,775	1.3	1,161	0.3
	2021	4,10,418	97.6	3,648	0.9	5,566	1.3	986	0.2
एसएफबी **	2020	89,800	98.1	1,023	1.1	648	0.7	39	0.0
	2021	1,05,619	94.6	4,965	4.4	841	0.8	165	0.1
सभी एससीबी	2020	92,58,114	91.7	1,93,413	1.9	5,03,543	5.0	1,43,349	1.4
	2021	98,60,726	92.7	1,77,720	1.7	4,47,648	4.2	1,54,717	1.5

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण घटक मर्दों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

2. *: सकल अग्रियों के प्रतिशत के रूप में

3. **: अनुसूचित एसएफबी के संदर्भ में।

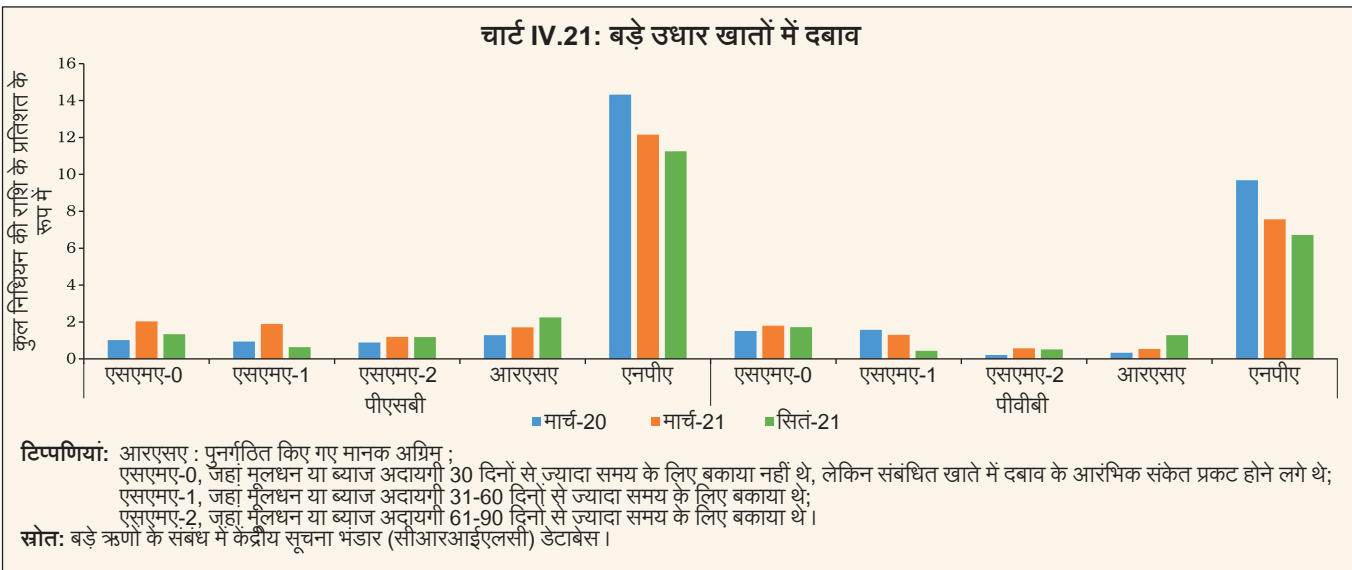
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई

2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित मानक अग्रियों के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना के कारण है। खुदरा और एमएसएमई के लिए पुनर्गठन योजना 2.0 के कारण सितंबर 2021 के अंत में आरएसए बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया, जिसमें आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड शामिल नहीं है।

IV.36 कुल अग्रियों में बड़े उधार खातों (₹5 करोड़ या अधिक का एक्सपोजर) की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में घटकर 51

प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 54.2 प्रतिशत थी। कुल एनपीए में उनका योगदान भी इसी अवधि के दौरान 75.4 प्रतिशत से घटकर 66.2 प्रतिशत हो गया। विशेष उल्लेखनीय खाता -2 (एसएमए -2) अनुपात, जो आसन्न दबाव का संकेत देता है, महामारी के प्रकोप के बाद से बैंक समूहों में बढ़ गया है। इसी अवधि के दौरान आरएसए अनुपात में भी वृद्धि हुई है, जो आंशिक रूप से 1.0 और 2.0 समाधान फ्रेमवर्क (आरएफ) के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट IV.21)।

चार्ट IV.21: बड़े उधार खातों में दबाव



4.4 वसूलियां

IV.37 वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी वसूली चैनलों, विशेष रूप से लोक अदालतों में, समाधान के लिए आए मामलों में काफी गिरावट देखी गई (सारणी IV.10)। यहां तक की भारत के दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत नई दिवाला कार्यवाही की शुरुआत पर मार्च 2021 तक एक साल के लिए रोक लगाई गई थी और कोविड-19 से संबंधित कर्ज को चूक की परिभाषा से बाहर रखा गया था, वसूल की गई राशि के अनुसार यह वसूली का एक प्रमुख माध्यम रहा। एमएसएमई के लिए प्री-पैक रिजॉल्यूशन विंडो की अनुमति से एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामलों का बढ़ता दबाव कम होने, मार्जिन कम होने और घटती वसूली दरों में सुधार की उम्मीद है।⁴

IV.38 बैंकों, विशेष रूप से पीवीबी के लिए आस्ति समाधान का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को मार्जिन लेकर एनपीए बेचना। हालांकि, हाल के वर्षों में, बैंकों की प्राथमिकता वैकल्पिक तरीकों में स्थानांतरित

हो गई है, बैंक समूहों में बकाया जीएनपीए के अनुपात के रूप में आस्ति की बिक्री में गिरावट आई है। यह आंशिक रूप से आस्ति के बहि मूल्य की तुलना में एआरसी की बिगड़ती अधिग्रहण लागत के कारण था, जो उनकी अधिग्रहित आस्ति के संबंध में उच्च मार्जिन और कम वसूली योग्य मूल्यों को दर्शाता है (चार्ट IV.22)।

IV.39 एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की वसूली उनके प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2018 से, रिजर्व बैंक बढ़े हुए प्रावधानों के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री के लेनदेन मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक एसआर रखने से बैंकों को हतोत्साहित कर रहा है।⁵ परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा अभिदत्त एसआर की हिस्सेदारी में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, हालांकि 2019-20 तथा 2020-21 में उनका हिस्सा 58 प्रतिशत के आसपास बना रहा।⁶ एसआर धारिता में एआरसी की हिस्सेदारी में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य अर्हता-प्राप्त खरीदारों की

सारणी IV.10: विभिन्न माध्यमों से वसूल किए गए एससीबी के एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली का माध्यम	2019-20				2020-21 (पी)			
	संदर्भित किए गए मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूल की गई राशि *	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित किए गए मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूल की गई राशि *	कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में कॉलम(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालत	59,86,790	67,801	4,211	6.2	19,49,249	28,084	1,119	4.0
डीआरटी	33,139	2,05,032	9,986	4.9	28,182	2,25,361	8,113	3.6
सरफेसी अधिनियम	1,05,523	1,96,582	34,283	17.4	57,331	67,510	27,686	41.0
आईबीसी @	1,986	2,24,935	1,04,117	46.3	537	1,35,139	27,311	20.2
कुल	61,27,438	6,94,350	1,52,597	22.0	20,35,299	4,56,094	64,228	14.1

टिप्पणियां : 1. पी : अनंतिम

2. *: निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि के संदर्भ में जो निर्दिष्ट वर्ष के दौरान, साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के विषय में हो सकते हैं।

3. डीआरटी: ऋण वसूली न्यायाधिकरण

4. @: आईबीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वीकार किए गए मामले।

5. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के रिजॉल्यूशन प्लान को 2018-19 में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, 2019-20 में लेनदारों के बीच बंटवारे का निपटारा किया गया था, वसूली बाद के वर्ष के आंकड़ों में परिलक्षित होती है।

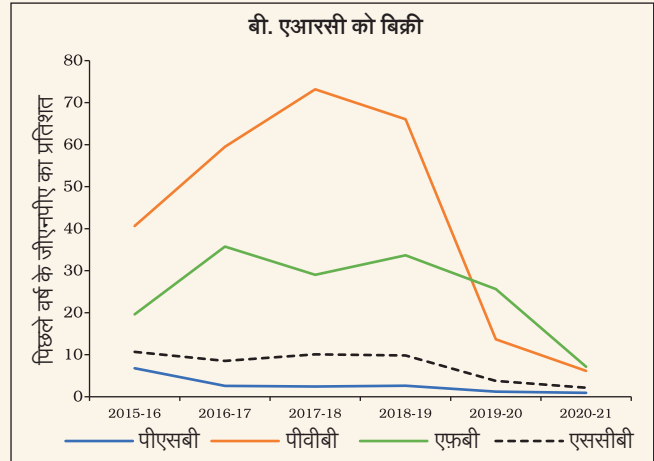
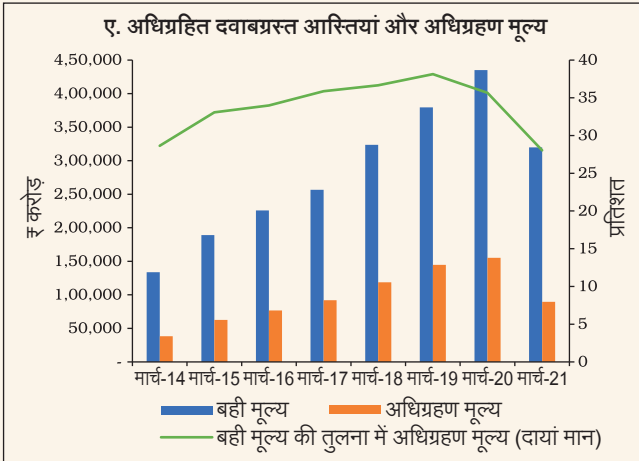
स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां, आरबीआई और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

⁴ निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गयी राशि वसूली दर है।

⁵ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा आस्ति की वास्तविक बिक्री हो, 1 अप्रैल, 2017 से अतिरिक्त प्रावधान के लिए उनकी बेची गई आस्तियों के समर्थन में एसआर रखने वाले बैंकों के लिए 50 प्रतिशत सीमा निर्धारित की गई थी और बाद में 1 अप्रैल 2018 से इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था।

⁶ जैसा कि एआरसी द्वारा रिपोर्ट किया गया है जिसका डेटा उपलब्ध है।

चार्ट IV.22: एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री



स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां और ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

बढ़ती हिस्सेदारी के साथ निवेशक आधार धीरे-धीरे विविधकृत हो गया है (सारणी IV.11)।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.40 ग्राहकों के विश्वास को कम करने के साथ-साथ, धोखाधड़ी वित्तीय प्रणाली के लिए प्रतिष्ठा जोखिम, परिचालन जोखिम और व्यावसायिक जोखिम के रूप में कई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। 2020-21 के दौरान, धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की गई संख्या में गिरावट आई (सारणी IV.12)। निहित राशि के अनुसार अधिकतर मामले पहले घटित थे लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट किए गए थे (सारणी IV.13)।

IV.41 परिचालन क्षेत्र के संदर्भ में, वर्ष 2020-21 के दौरान अग्रिमों से संबंधित संख्या और निहित राशि के अत्यधिक मामलों रिपोर्ट किए गए, जबकि कार्ड या इंटरनेट लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी मामलों की संख्या का हिस्सा 34.6 प्रतिशत रहा।

IV.42 वर्ष 2020-21 में, पीवीबी से संबंधित धोखाधड़ी में संख्या के साथ-साथ निहित राशि दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ति:2021-22 के दौरान, धोखाधड़ी के मामलों की संख्या का आधा हिस्सा पीवीबी का था (सारणी IV.23 ए)। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में, पीएसबी का हिस्सा अधिक था, जो उच्च मूल्य

सारणी IV.11: एआरसी द्वारा प्रतिभूत की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च -19	मार्च -20	मार्च -21
रिपोर्टिंग एआरसी	18	23	21
1. बैंक/ एआरसी द्वारा अर्जित की गई आस्तियों का बही मूल्य	1,86,770	2,95,097	3,19,838
रिपोर्टिंग एआरसी	12	11	11
2. जारी की गई प्रतिभूति रसीद की राशि	14,691	59,347	69,995
3. के द्वारा सौंपी गई प्रतिभूति रसीद			
(ए) विक्रेता बैंक / वित्तीय संस्था	10,659	34,147	41,076
(बी) आस्तित पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)	3,663	12,421	13,942
(सी) एफआईआई	151	8,750	9,861
(डी) अन्य (अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता)	219	4,028	5,116
4. पूरी तरह से विमोचित की गई प्रतिभूति रसीद की राशि	558	9,062	13,283
5. बकाया प्रतिभूति रसीद	13,087	39,618	42,266

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां

सारणी IV.12: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2020-21 (अप्रैल-सितंबर)		2021-22 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	3,603	64,539	4,608	1,81,942	3,501	1,37,023	1,669	63,529	1,802	35,060
तुलन- पत्रेतर	33	5,538	34	2,445	23	535	14	439	10	612
विदेशी मुद्रा में लेन-देन	13	695	8	54	4	129	1	0	1	0
कार्ड/इंटरनेट	1,866	71	2,677	129	2,545	119	1,247	49	1,532	60
जमाराशि	593	148	530	616	504	434	245	149	208	362
अंतर-शाखा खाते	3	0	2	0	2	0	2	0	0	0
नकद	274	56	371	63	329	39	132	22	245	51
चेक/डीडी, आदि	189	34	201	39	163	85	77	48	107	149
समाशोधन खाते	24	209	22	7	14	4	4	1	9	1
अन्य	200	244	250	173	278	54	108	25	157	47
कुल	6,798	71,534	8,703	1,85,468	7,363	1,38,422	3,499	64,261	4,071	36,342

टिप्पणियां : 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संदर्भ में।
 2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन हैं।
 3. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
 4. निहित राशि रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं और हानि की राशि को प्रदर्शित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाई गई हानि में कमी आ सकती है। साथ ही, यह आवश्यक नहीं है कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि का विचलन किया गया हो।

स्रोत : आरबीआई

की धोखाधड़ी की प्रबलता दर्शाता है (सारणी IV.23 बी)। जबकि ऋण से संबंधित मामलों का बड़ा हिस्सा पीएसबी से

संबंधित था, अधिकांश कार्ड/इंटरनेट और नकदी से संबंधित मामले पीवीबी से संबंधित थे (चार्ट IV.23 सी)।

सारणी IV.13: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

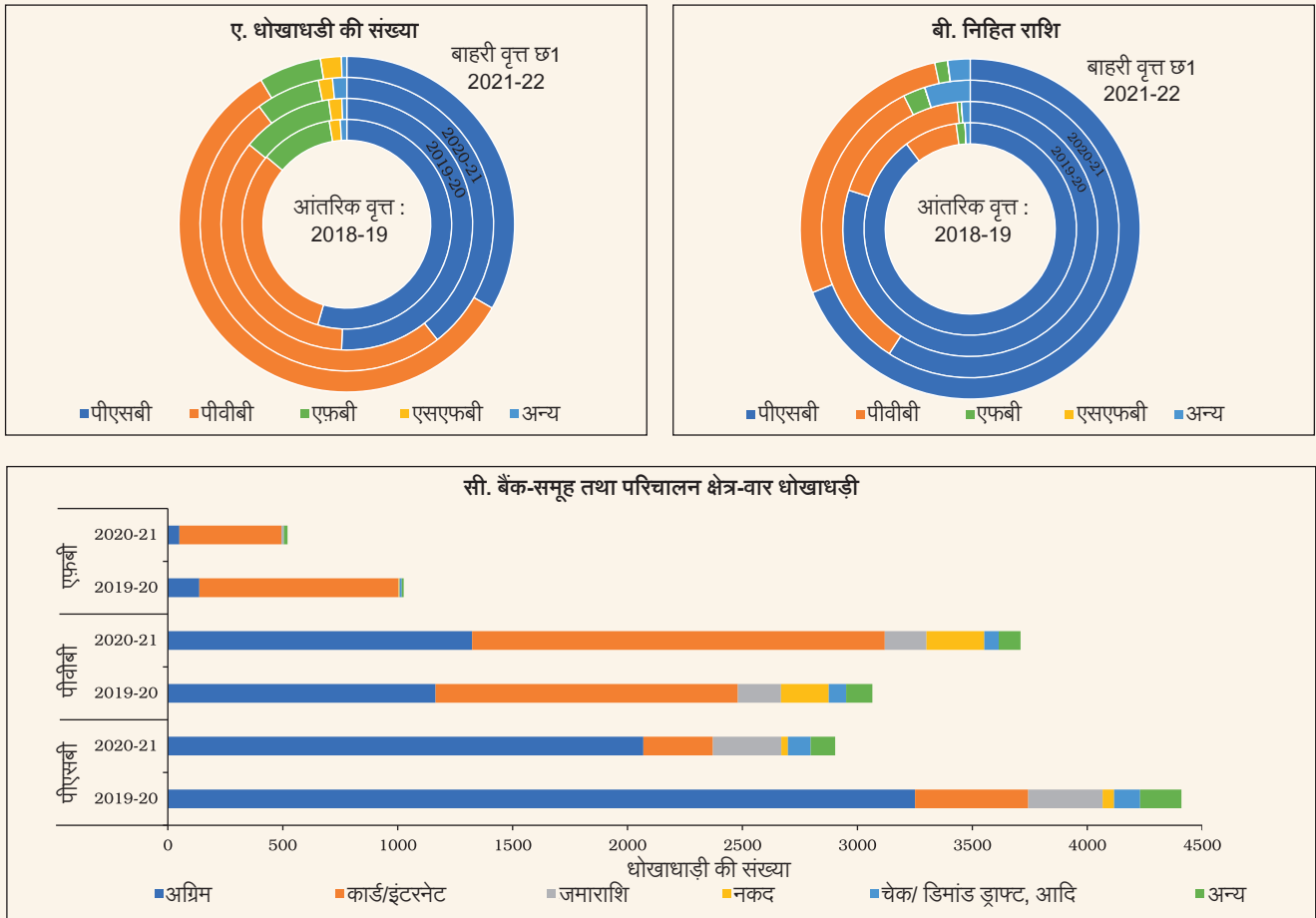
(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2018-19 से पहले		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	8,752	3,33,362	2,129	40,516	1,525	31,074	903	13,373	205	237
तुलन पत्रेतर	71	5,817	19	2,927	5	371	5	12	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	11	597	5	145	7	135	3	1	0	0
कार्ड/इंटरनेट	485	31	2,090	83	2,645	130	2,296	104	1,104	32
जमाराशि	475	606	550	163	438	338	306	421	66	32
अंतर- शाखा खातें	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0
नकद	95	40	275	64	381	37	336	45	132	21
चेक/डीडी आदि	109	34	165	28	201	69	144	163	41	12
समाशोधन खातें, आदि	17	9	26	206	13	2	9	3	4	0
अन्य	289	277	201	58	144	132	206	35	45	18
कुल	10,307	3,40,773	5,463	44,191	5,359	32,290	4,209	14,158	1,597	353

टिप्पणियां : 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संदर्भ में।
 2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़ों उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
 3. 'घटना की तारीख' के आधार पर समयवधि के लिए डेटा बदल सकता है क्योंकि धोखाधड़ी पहले घटित हुई थी लेकिन देर से रिपोर्ट की गई थी जो जोड़ दिया जाएगा।
 4. सारणी के आंकड़ों 2018-19 से 30 सितंबर, 2021 तक सूचित मामलों से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.23: बैंक-समूह वार धोखाधड़ी



स्रोत: आरबीआई

4.6 प्रवर्तन कार्रवाई

IV.43 पर्यवेक्षी प्रक्रिया से प्रवर्तन कार्रवाई को अलग करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, रिज़र्व बैंक में 2017 में प्रवर्तन विभाग बनाया गया। विभाग को विनियमों के प्रवर्तन में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने और विनियमित संस्थाओं (आरई) में अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। 2020-21 में 11 अनुसूचित सहकारी बैंकों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने के साथ, दंड लगाने के मामलों की संख्या में कमी आई है। धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग, एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड, एमएसएमई को जमा और उधार पर ब्याज दर आदि पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन

न करना या उल्लंघन के लिए मौद्रिक दंड लगाया गया था (सारणी IV.14)।

सारणी IV.14: प्रवर्तन कार्रवाई

विनियमित संस्था	अप्रैल 2019 से मार्च 2020		अप्रैल 2020 से मार्च 2021	
	दंड लगाने के मामले	कुल दंड राशि (₹ करोड़)	दंड लगाने के मामले	कुल दंड राशि (₹ करोड़)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	29	35.1	4	9.5
निजी क्षेत्र के बैंक	11	11.5	3	5.9
सहकारी बैंक	9	7.4	43	3.9
विदेशी बैंक	1	1.0	3	8.0
भुगतान बैंक	-	-	1	1.0
लघु वित्त बैंक	-	-	-	-
एनबीएफसी	2	0.1	7	3.1
कुल	52	55	61	31

स्रोत: आरबीआई।

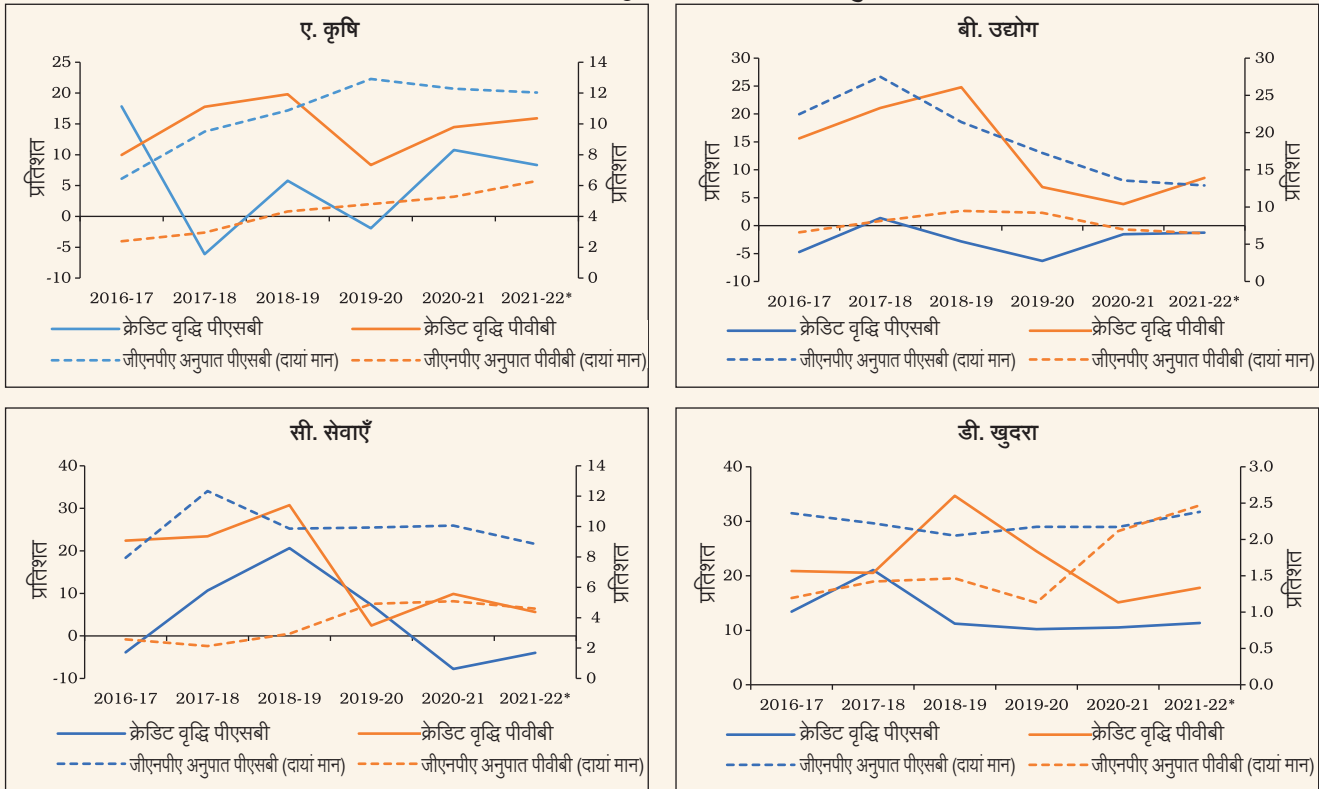
5. क्षेत्रवार बैंक ऋण: वितरण और एनपीए

IV.44 हेडलाइन क्रेडिट वृद्धि 2020-21 के दौरान कमजोर रही, हालांकि क्षेत्रवार कुछ अच्छे संकेत दिखाई दिए: कृषि ऋण पिछले वर्ष की तेज गिरावट से उभरा; पीवीबी ने सेवा क्षेत्र के लिए उधार को बढ़ाया; और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आंशिक रूप से कुल खुदरा ऋण वृद्धि की गिरावट को कम किया। दूसरी ओर, बढ़ते एनपीए अनुपात की स्थिति में पीएसबी द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए और पीवीबी द्वारा खुदरा क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि धीमी हो गई (चार्ट IV.24)।

IV.45 डेटा ड्रिल डाउन से पता चलता है कि हालांकि बड़े उद्योगों को क्रेडिट संकुचित हुआ, उनके मध्यम आकार के

समकक्षों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के माध्यम से तेजी से अधिकतम क्रेडिट प्रवाह प्राप्त हुआ।⁷ मार्च 2021 के अंत में बड़े औद्योगिक उधारकर्ताओं के उच्च एनपीए की तुलना में मध्यम उद्यमों की बेहतर आस्ति गुणवत्ता भी एक उत्प्रेरक हो सकते हैं। सेवाओं में, व्यापार के लिए ऋण वृद्धि ने 2020-21 में अपनी पूर्व महामारी वृद्धि दर को पार कर लिया। उल्लेखनीय रूप से, सेवा क्षेत्र के ऋण में इसकी हिस्सेदारी भी 2020-21 में तेजी से बढ़ी। आईएल एंड एफएस घटना के बाद, एनबीएफसी-विशेष रूप से कम रेटिंग वाले एनबीएफसी के लिए बाजार से संसाधन जुटाना मुश्किल पाया और बैंकों की ओर रुख किया। एससीबी का एनबीएफसी को

चार्ट IV.24: क्षेत्रवार वृद्धि और जीएनपीए अनुपात



टिप्पणी: क्रेडिट वृद्धि दर सितंबर 2020 की तुलना में सितंबर 2021 के है। जीएनपीए अनुपात सितंबर 2021 के अंत का है।
 स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

⁷ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा मई 2020 में एमएसएमई को ₹3 लाख करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। कामथ समिति द्वारा चिन्हित अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बाद में योजना के दायरे को बढ़ाया गया।

सारणी IV.15: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम मद सं	बकाया				प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)			
	मार्च -19	मार्च -20	मार्च -21	सितं-21	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सितंबर तक)*
1 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	12,17,594	12,39,575	13,84,815	14,30,480	10.0	1.8	11.7	10.7
2 उद्योग, जिसमें से	32,93,638	32,52,801	32,53,636	32,34,613	5.2	-1.2	0.03	3.3
2.1 सूक्ष्म और लघु उद्योग	4,39,811	4,37,658	4,72,529	5,41,554	5.2	-0.5	8.0	16.8
2.2 मध्यम	1,23,843	1,12,367	1,87,599	2,06,151	-1.7	-9.3	67.0	47.0
2.3 बड़े	26,11,567	26,11,377	24,76,702	23,59,112	6.1	-0.01	-5.2	-3.4
3 सेवाएं, जिसमें से	26,02,287	27,54,823	27,45,324	27,24,810	25.1	5.9	-0.3	1.3
3.1 व्यापार	5,83,930	6,28,142	7,14,210	6,75,820	12.4	7.6	13.7	3.7
3.2 व्यावसायिक स्थावर संपदा	2,43,122	2,66,357	2,52,696	2,76,980	18.9	9.6	-5.1	8.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	56,194	60,039	62,722	61,027	7.9	6.8	4.5	-2.1
3.4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	22,236	24,404	23,742	21,570	-0.3	9.8	-2.7	-4.4
3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6,27,089	7,36,447	7,98,241	8,24,189	38.4	17.4	8.4	14.8
4 खुदरा ऋण, जिसमें से	23,04,313	26,59,249	29,86,461	31,10,368	18.6	15.4	12.3	14.0
4.1 आवास ऋण	12,04,362	13,96,444	15,61,913	15,99,395	19.5	15.9	11.8	11.2
4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	9,195	11,154	21,569	28,409	-51.7	21.3	93.4	69.2
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्ति	1,11,361	1,32,076	1,38,560	1,43,937	34.5	18.6	4.9	2.2
4.4 वाहन/ऑटो ऋण	2,69,677	2,89,366	3,29,522	3,61,849	12.9	7.3	13.9	21.2
4.5 शिक्षा ऋण	76,233	79,056	78,823	82,433	1.8	3.7	-0.3	2.9
4.6 मीयादी जमाओं पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी) सहित, आदि)	77,135	80,753	74,013	72,718	-0.1	4.7	-8.3	1.7
4.7 शेयरों, बांडों आदि पर व्यक्तियों को अग्रिम	9,339	5,619	5,619	6,092	46.3	-39.8	0	-12.7
4.8 अन्य खुदरा ऋण	5,47,010	6,64,781	7,76,441	8,15,535	25.6	21.5	16.8	20.8
5 खाद्येतर ऋण	95,26,932	1,00,98,420	1,06,40,811	1,07,52,479	13.4	6.0	5.4	6.8

टिप्पणियां : 1. सारणी के आंकड़े, बैंकों को शामिल किए जाने में अंतर के कारण आरबीआई द्वारा प्रत्येक माह में जारी किए जानेवाले 'बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन' आंकड़ों से नहीं मेल खान सकते हैं।
2. प्रतिशत में घट-बढ़ मार्च से मार्च तक है।
3. डेटा एससीबी से संबंधित हैं।
4. सितंबर 2020 से सितंबर 2021

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई

ऋण 2015-16 से 2019-20 के दौरान दोहरे अंकों में बढ़ा, लेकिन 2020-21 में अत्यधिक घटा (सारणी IV.15)।

IV.46 वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो ने अपने सेवा क्षेत्र के उधार को बढ़ा दिया, आवास ऋणों में तेजी से दोहरे अंकों की वृद्धि सहायक हुई - जो खुदरा ऋण का सबसे बड़ा घटक है। कंपनियों द्वारा ऑटोमोबाइल पर पर्याप्त छूट की घोषणा के बाद, वाहन ऋणों में गति प्राप्त हुई, जो उपभोक्ता की रुचि दर्शाता है।

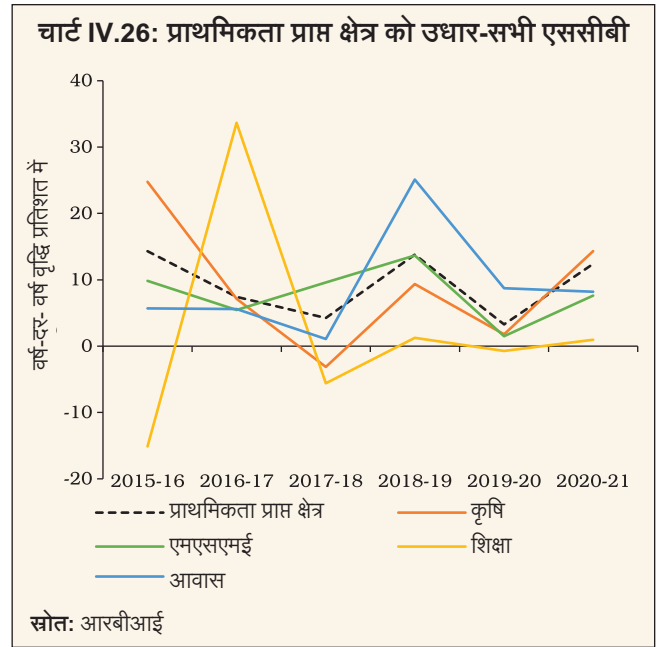
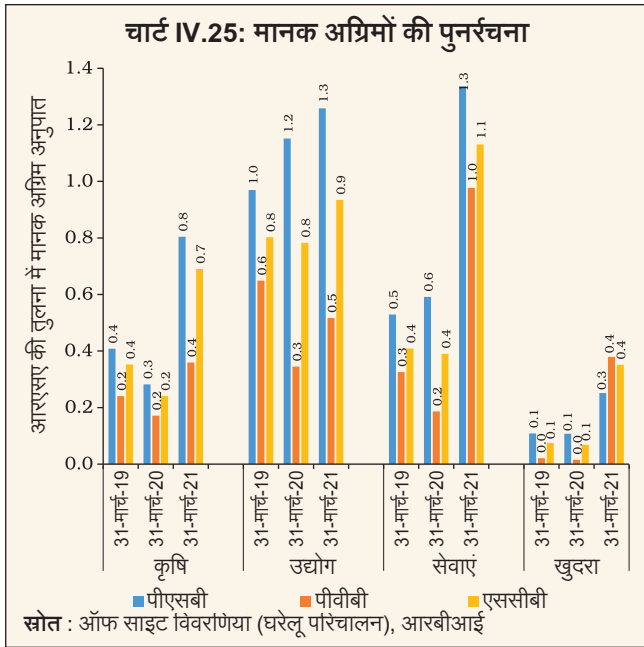
IV.47 आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के बाद बैंकों द्वारा बेहतर आस्ति गुणवत्ता निर्धारण के कारण एससीबी का आरएसए अनुपात 2015 से लगातार पांच वर्षों से घट रहा है। महामारी के चलते रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2020 में घोषित पुनर्चना योजना से, 2020-21 में आरएसए अनुपात, विशेष रूप से सेवाओं और

खुदरा ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई जिसमें संपर्क-गहन सेवाओं का योगदान प्रमुख रहा (चार्ट IV.25)।

5.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.48 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) 2020-21 में तेज हुआ, मुख्य रूप से कृषि के लिए ऋण में पुनरुत्थान द्वारा संचालित - विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण - और पीएसबी और पीवीबी दोनों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण (चार्ट IV.27 और परिशिष्ट सारणी IV.3)।

IV.49 पीएसएल उधार, जो आमतौर पर प्र-चक्रिय होता है, बैंक-विशिष्ट विशेषताओं से भी प्रभावित होता है जैसे पीएसएल की आस्ति गुणवत्ता की तुलना में गैर-पीएसएल ऋण, उधार देने वाले बैंक का आकार और उनकी शाखा नेटवर्क (बॉक्स IV.2)।



IV.50 वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी बैंक समूहों ने समग्र पीएसएल लक्ष्य प्राप्त किया। पीएसबी (सूक्ष्म उद्यम) और पीवीबी

(कृषि, लघु और सीमांत कृषक (एसएमएफ) और गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसानों द्वारा कुछ उप-लक्ष्य प्राप्ति में कमियां देखी गईं

बॉक्स IV.2: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के निर्धारक

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - भारत में 1969 में उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू हुआ जो ऋण की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। एससीबी⁸ को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अपने पिछले वर्ष के समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 40 प्रतिशत या तुलन पत्रेतर एक्सपोजर (सीईओबीई) के समकक्ष उधार, जो भी अधिक हो, देना आवश्यक है। एक समान विनियामक आवश्यकताओं के बावजूद, बैंकों और बैंक समूहों में कुछ अवधियों में बैंक विनियामक लक्ष्य से विचलित हो गए हैं। प्रत्यक्ष उधार में कमी की स्थिति में विनियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंकों के पास इंटर-बैंक प्रतिभागिता प्रमाण पत्र (आईबीपीसी), प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का प्रतिभूतिकरण, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) तथा अन्य निधि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड में अपर्याप्त राशि जमा जैसे कई रास्ते उपलब्ध हैं वर्ष 2016 में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

में व्यापार शुरू किया गया था, जो एक गेम चेंजर था क्योंकि इसने ऋण, नकदी प्रवाह या जोखिम के हस्तांतरण के बिना पीएसएल लक्ष्यों की कमी के लिए खरीद तथा अधिकता के लिए बिक्री की अनुमति दी थी। आनुभविक रूप से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार विभिन्न बैंक-विशिष्ट विशेषताओं जैसे स्वामित्व का स्वरूप, आकार के साथ-साथ प्रदर्शन पर निर्भर पाया जाता है (कुमार, बत्रा, और डिरिंग, 2016)। 59 बैंकों के तिमाही बैंक-वार डेटा का बैंकों द्वारा निर्भर चर के रूप में ऑरगेनिक पीएसएल के रूप में उपयोग करते हुए मार्च 2005 से दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए एक निश्चित प्रभाव पैरल प्रतिगमन यह दर्शाता है कि आर्स्टि की गुणवत्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आर्स्टि गुणवत्ता तनाव का सामना करने वाले बैंक इस क्षेत्र को कम उधार देने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जीडीपी, जो समष्टि आर्थिक कारकों के लिए एक नियंत्रण है, और बैंक आकार⁹ - एक बैंक-विशिष्ट नियंत्रण

(Contd...)

⁸ 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 75 प्रतिशत उधार देना आवश्यक है।

⁹ Bank बैंक आकार = अग्रिम + जमा।

सारणी 1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के निर्धारक

चर	आश्रित चर		
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एमएसई अग्रिम
आश्रित चर (-1)	0.477*** (0.111)	0.564*** (0.0947)	0.746*** (0.0313)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात	-0.0161*** (0.00314)		
अनुपात गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात	0.00495** (0.00192)		0.00492*** (0.00171)
कृषि जीएनपीए अनुपात		-0.00606*** (0.000868)	
एमएसई जीएनपीए अनुपात			-0.0154*** (0.00326)
मार्च डमी	0.0351*** (0.0103)	0.0616*** (0.0161)	0.0461*** (0.0156)
जीडीपी	0.0568** (0.0231)		0.0979** (0.0454)
कृषि जीडीपी		0.0896*** (0.0329)	
सीआरएआर		0.00230 (0.00332)	0.00329 (0.00231)
पीएसएलसी डमी	0.0597*** (0.0217)	0.0443** (0.0167)	-0.0204 (0.0225)
बैंक का आकार	0.480*** (0.106)	0.397*** (0.0962)	0.290*** (0.0515)
प्रति आस्ति शाखाएं	0.00240*** (0.000542)		
प्रति आस्ति ग्रामीण शाखाएं		0.00713*** (0.00173)	
प्रति आस्ति शहरी शाखाएं			0.00344*** (0.000623)
आरओई	0.00 (0.000)		
स्थिर	-1.307*** (0.338)	-1.990*** (0.495)	-2.581*** (0.371)
निष्कर्ष	2.765	2.769	2.749
आर वर्ग	0.970	0.938	0.948
बैंकों की संख्या	59	59	59

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियां दी गयी हैं।
2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

चर- का पीएसएल के साथ सकारात्मक संबंध है। मार्च तिमाही के लिए डमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण पाई गई, क्योंकि बैंकों ने अपने वार्षिक औसत में सुधार करने और विनियामक लक्ष्य हासिल करने के लिए पिछली तिमाही में अपने पीएसएल को बैकलोड करने की कोशिश की।¹⁰ शाखाओं का आस्ति अनुपात, बैंकों की पहुंच के लिए एक प्रॉक्सी, भी महत्वपूर्ण पाया गया है।¹¹

कृषि (18 प्रतिशत) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (7.5 प्रतिशत) को उधार देने पर उप-लक्ष्यों के लिए, क्रमशः ग्रामीण और शहरी शाखाओं के साथ आस्ति अनुपात के लिए समान मॉडल अनुमानित हैं। गुणांक महत्वपूर्ण और सकारात्मक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पारंपारिक शाखा वाले बैंक प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्र को उच्चतर उधार देते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में एमएसई को उधार देते हैं।

समग्र पीएसएल के साथ-साथ उप-लक्ष्यों के लिए एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण पीएसएलसी डमी से पता चलता है कि पीएसएलसी की शुरुआत ने बैंकों को पीएसएलसी में लाभप्रद व्यापार करने के अवसर के साथ-साथ विनियामक लक्ष्यों को पूरा किया है।

संदर्भ:

कुमार, एम., बत्रा, एन., और डिस्टिंग, एफ. (2016). डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग: इविडेंस फ्रॉम बैंक लेंडिंग पैटर्न इन इंडिया. दि इंटरनैशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड फिनांस रिसर्च.

(सारणी IV.16)। सितंबर 2020 में जारी संशोधित पीएसएल दिशा - निर्देशों के अनुसार एसएमएफ और कमजोर वर्गों के लिए पीएसएल लक्ष्यों में चरणबद्ध वृद्धि से इन क्षेत्रों में ऋण की पहुंच गहराने की उम्मीद है।¹²

IV.51 वर्ष 2020-21 के दौरान पीएसएलसी की कुल व्यापार मात्रा 26 प्रतिशत से बढ़कर ₹5,89,163 करोड़ हो गयी। चार पीएसएलसी श्रेणियों में, पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-

सूक्ष्म उद्यमों के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.27)।

IV.52 पीएसएलसी के लिए भारत औसत प्रीमियम (डब्ल्यूएपी) में 2020-21 में सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष 11 से 44 प्रतिशत आधार अंक की वृद्धि हुई है, जिसमें से पीएसएलसी-एसएमएफ और पीएसएलसी-ए श्रेणियां पीएसएलसी-जी और पीएसएलसी-एमई की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम हैं। 2021-22 की पहली छमाही में, एमएसएमई की परिभाषा में

¹⁰ भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य प्राप्ति की गणना करते समय, प्रत्येक तिमाही के लिए कम/अधिक उधार की निगरानी अलग से की जाती है। सभी तिमाहियों का एक साधारण औसत निकाला जाता है और वर्ष के अंत में समग्र कमी / अधिकता की गणना के लिए विचार में लिया जाता है।

¹¹ बैंक शाखाओं के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका से लिए गए हैं।

¹² एसएमएफ के लिए, उप-लक्ष्य बढ़कर 2021-22 तक 9 प्रतिशत, 2022-23 तक 9.5 प्रतिशत और 2023-24 तक 10 प्रतिशत हो जाएगा। कमजोर वर्ग के लिए लक्ष्य बढ़कर 2021-22 तक 11 प्रतिशत, 2022-23 तक 11.5 प्रतिशत और 2023-24 तक 12 प्रतिशत हो जाएगा।

सारणी IV.16: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(31 मार्च 2021 की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य /उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम जिसमें से	40/75*	24,16,750	41.06	14,33,674	40.62	1,99,969	41.02	59,055	86.00
कुल कृषि	18.0	10,68,112	18.15	5,29,637	15.01	45,457	18.97	19,239	28.02
छोटे और सीमांत कृषक	8.0	5,53,455	9.40	2,40,754	6.82	24,233	10.11	17,798	25.92
गैर-कॉर्पोरेट वैयक्तिक कृषक #	12.14	7,69,173	13.07	3,64,026	10.31	29,187	12.18	20,422	29.74
सूक्ष्म उद्यम	7.50	4,18,763	7.11	2,93,072	8.30	18,050	7.53	16,580	24.14
कमजोर वर्ग	10.0	7,27,794	12.37	3,58,002	10.14	28,037	11.70	36,377	52.97

टिप्पणियाँ : 1. वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए औसत उपलब्धि के आधार पर बकाया राशि और उपलब्धि का प्रतिशत
2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य 75 प्रतिशत है।
3. #: गैर-कॉर्पोरेट कृषकों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों के प्रणाली-व्यापक औसत पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रणाली-व्यापक औसत आंकड़ा 12.14 प्रतिशत है।
4. वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएँ हैं, के लिए कुल पीएसएल लक्ष्य का केवल 40 प्रतिशत लागू है।

स्रोत : आरबीआई

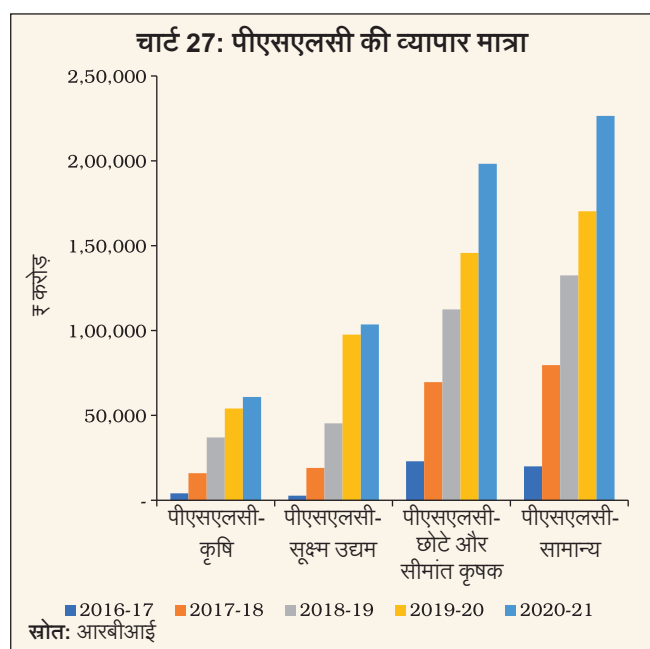
बदलाव के कारण पीएसएलसी-एमई पर डब्ल्यूएपी में भारी बढ़ोतरी हुई है। कोविड संबंधित तनाव के कारण अन्य श्रेणियों में डब्ल्यूएपी में वृद्धि हुई है (सारणी IV.17)।

IV.53 जबकि कुल बैंक उधार में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के खातों की हिस्सेदारी 2019-20 के 35 प्रतिशत से मामूली रूप

से बढ़कर 2020-21 में 36 प्रतिशत हो गई, कुल जीएनपीए में उनका हिस्सा कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्यम पीएसएल के अपचार के कारण उसी अवधि में 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 40.5 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.18)।

5.2 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.54 संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों का एक्सपोजर 2020-21 के दौरान कम हुआ। फिर भी, यह स्थावर संपदा क्षेत्र में, विशेष



सारणी IV.17: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

पीएसएलसी श्रेणी	(प्रतिशत)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रै-सित)	2021-22 (अप्रै-सित)
पीएसएलसी-ए	1.29	0.79	1.17	1.55	1.61	2.00
पीएसएलसी-एमई	0.61	0.57	0.44	0.88	0.54	2.03
पीएसएलसी-एसएमएफ	1.54	1.15	1.58	1.74	1.87	2.38
पीएसएलसी-जी	0.59	0.31	0.35	0.46	0.49	0.85

स्रोत : आरबीआई

सारणी IV.18: बैंकों का क्षेत्रवार जीएनपीए
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

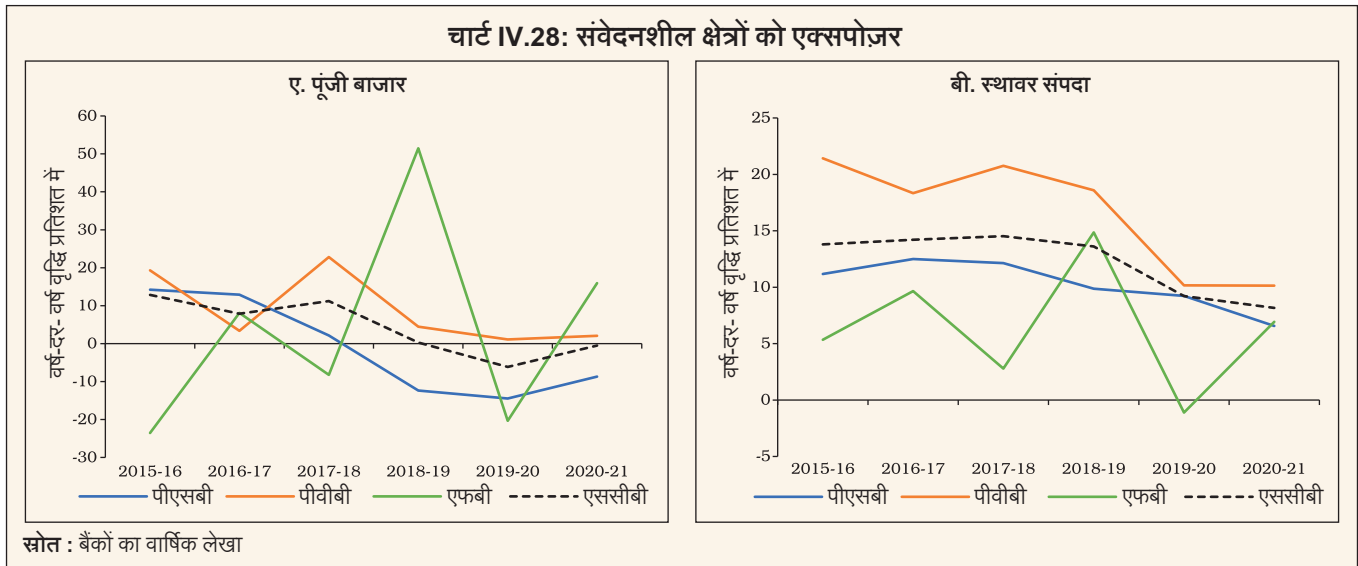
बैंक समूह	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से						गैर- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#
पीएसबी												
2020	2,36,212	36.66	1,11,571	17.31	90,769	14.09	33,872	5.26	4,08,205	63.34	6,44,417	100.00
2021	2,58,228	44.76	1,15,281	19.98	1,01,786	17.64	41,161	7.13	3,18,747	55.24	5,76,974	100.00
पीवीबी												
2020	36,219	19.69	14,462	7.86	16,111	8.76	5,646	3.07	1,47,751	80.31	1,83,970	100.00
2021	50,557	27.04	18,900	10.11	23,473	12.56	8,184	4.38	1,36,384	72.96	1,86,941	100.00
एफबी												
2020	1,692	16.57	376.07	3.68	1070.24	10.48	245.66	2.41	8,516	83.43	10,208	100.00
2021	1,802	17.67	328.97	3.23	1193.62	11.70	279.48	2.74	8,397	82.33	10,199	100.00
एसएफबी												
2020	1,376	80.51	255.77	14.96	753.88	44.10	366.59	21.45	333	19.49	1,709	100.00
2021	4,974	83.31	1509.6	25.28	2049.4	34.32	1415.23	23.70	996	16.69	5,971	100.00
सभी एससीबी												
2020	2,75,499	32.79	1,26,664	15.07	1,08,704	12.94	40,131	4.78	5,64,806	67.21	8,40,305	100.00
2021	3,15,561	40.45	1,36,019	17.44	1,28,502	16.47	51,039	6.54	4,64,524	59.55	7,80,085	100.00

टिप्पणियाँ : 1. राशि: - राशि; प्रतिशत : कुल एनपीए का प्रतिशत
2. पूर्णांकन के कारण घटक मदों का योग कुल से भिन्न हो सकता है।
3. # कुल एनपीए में हिस्सा
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई.

रूप से पीवीबी और एफबी के नेतृत्व में, समग्र ऋण वृद्धि की तुलना में उच्च गति से बढ़ा। बैंकों का पूंजी बाजार एक्सपोजर

लगातार दूसरे वर्ष कम हुआ (चार्ट IV.28 और परिशिष्ट सारणी IV.4)।

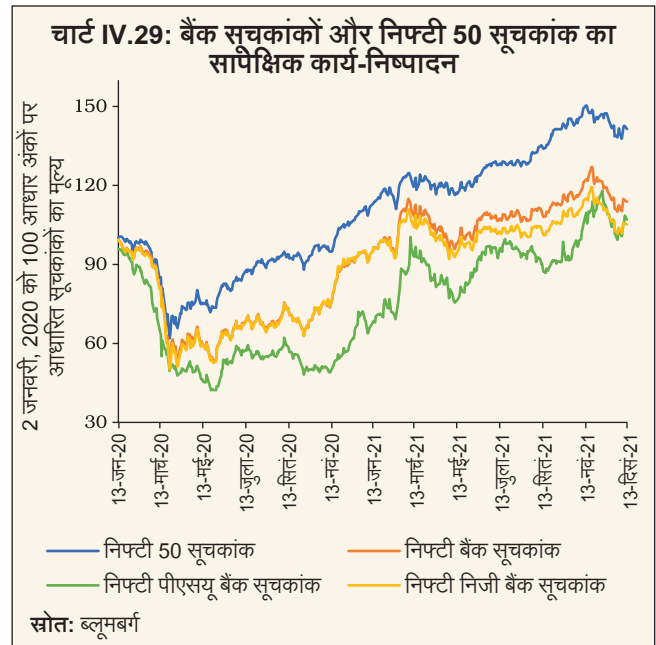
चार्ट IV.28: संवेदनशील क्षेत्रों को एक्सपोजर



6. बैंकिंग स्टॉक का प्रदर्शन

IV.55 वैश्विक संकेतों को देखते हुए, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत में इक्विटी बाजारों में तेजी से गिरावट आयी। बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक बुरी तरह से प्रभावित हुए, जो उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों की चिंताओं को दर्शाता है, हालांकि यह प्रभाव बैंकों और बैंक समूहों में समरूप नहीं था। तदन्तर, रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें बहाल हुईं (चार्ट IV.29)।

IV.56 अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि महामारी के प्रकोप के दौरान कमजोर तुलन-पत्र वाले बैंकों के स्टॉक पर निवेशकों द्वारा और अधिक गाज गिरी (बॉक्स IV.3)।



बॉक्स IV.3: बैंकिंग स्टॉक प्रदर्शन पर कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव

महामारी और लॉकडाउन के कारण हेडलाइन सूचकांक की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक का लगातार खराब प्रदर्शन रहा। संभावित चलनिधि जोखिमों पर बाजार की चिंता के कारण इन स्टॉक की बिकवाली हुई। इसके बाद, हालांकि, जैसे-जैसे नीति समर्थन उपायों की शुरुआत की गई, उलटफेर भी दिखाई देने लगे (आचार्य और अन्य, 2021; कुंट और अन्य, 2021)।

भारत में, भी 24 मार्च, 2020 से प्रभावी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने से बैंकिंग स्टॉक के संबंध में निवेशकों की चिंता बढ़ गई। इस घटना को अनुभवजन्य रूप से स्पष्ट करने के लिए, दो-चरणीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है।¹³ पहले चरण में, एक घटना का अध्ययन मॉडल (मैककिनले, 1997; माथुर और अन्य, 2021) को समीकरण (1) की गणना करने के लिए नियोजित किया गया था, जो कि घटना के दिन, अर्थात् लॉकडाउन लागू करने से 91 से 11 दिन पहले की अवधि में अनुमानित है।

$$R_{b,t} = \alpha + \beta \cdot R_t + \epsilon_{b,t} \quad (1)$$

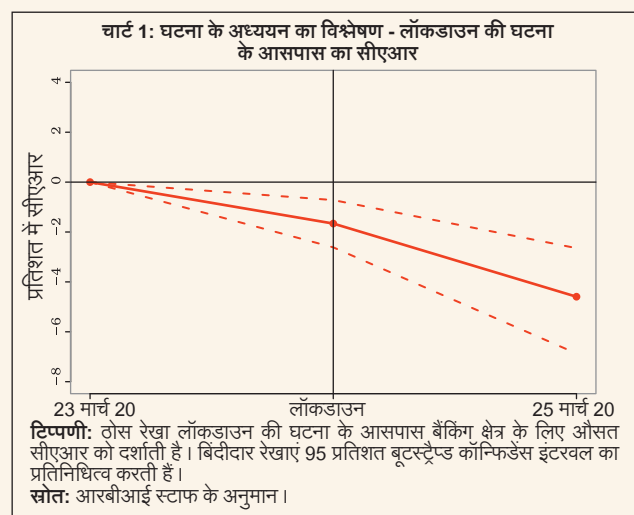
जहां, दिन पर बैंक के लिए दैनिक शेयर बाजार रिटर्न है, निफ्टी-50 सूचकांक पर दैनिक रिटर्न है और त्रुटि मान को दर्शाता है। तब (-1, +1) दिनों¹⁴ की अवधि में प्रत्येक बैंक के लिए असामान्य शेयर बाजार प्रतिफल (एआर) की निम्न रूप से गणना की जाती है:

$$AR_{b,T} = R_{b,T} - \hat{R}_{b,T} \quad \forall T \in (-1, 0, +1) \quad (2)$$

जहां T घटना की अवधि से संबंधित है। तुलना और आसान व्याख्या के लिए, एआर को दिन (-1) के लिए 0 पर सूचकांकित किया गया था और घटना की

अवधि में निर्दिष्ट बैंक के लिए संचयी असामान्य स्टॉक रिटर्न प्राप्त करने के लिए इसका योग कर दिया गया।

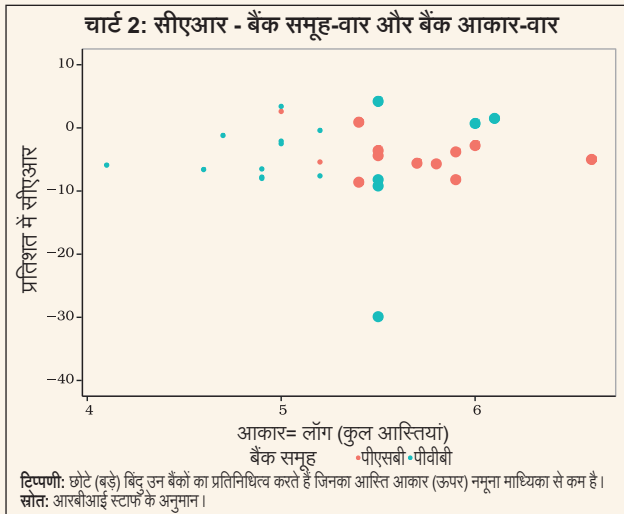
अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद एससीबी के लिए सीएआर में काफी गिरावट आयी (चार्ट 1)। इसके अलावा, बैंक के आकार और बैंक समूह से पृथक पूरे बोर्ड में प्रभाव महसूस किया गया (चार्ट 2)।



(Contd...)

¹³ 12 पीएसबी, 18 पीवीबी और निफ्टी-50 सूचकांक के दैनिक स्टॉक कीमतों को ब्लूमबर्ग से प्राप्त किया गया था।

¹⁴ उच्च-आवृत्ति आंकड़े और घटना की निर्धारित अवधि, संभावना प्रभाव और अन्य अव्यवस्था करने वाले कारकों को सुनिश्चित करती है।



दूसरे चरण में, एक क्रॉस-सेक्शनल रिग्रेशन मॉडल (समीकरण 3) का उपयोग सीएआर की व्याख्या करने में बैंक-स्तरीय विशेषताओं की भूमिका की जांच के लिए किया जाता है¹⁵:

$$CAR_b = \alpha + \beta \cdot size + \gamma \cdot bank\ group\ dummy + \theta \cdot X_b + \omega_b \quad (3)$$

जहां बैंक का आकार (कुल आस्तिक के लॉग द्वारा अनुमानित) और बैंक समूह के लिए एक दोहरे चर (पीवीबी के लिए 0 और पीएसबी के लिए 1) को नियंत्रण चर के रूप में उपयोग किया जाता है। तुलन-पत्र और वित्तीय चरों जैसे लाभप्रदता (आरओई), आस्तिक गुणवत्ता (जीएनपीए अनुपात और गिरावट अनुपात) और पूंजी पर्याप्तता (सीईटी-1 अनुपात) को द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिगमन विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि आकार और स्वामित्व को नियंत्रित करने के लिए ऐसे बैंकों, जिनके पास मजबूत तुलन-पत्र और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति— जैसे कि उच्च आरओई और सीईटी-1 अनुपात— थी, को महामारी-पूर्व की अवधि में कम हानि उठानी पड़ी। दूसरी ओर, जिन बैंकों का महामारी अवधि में उच्च जीएनपीए और गिरावट अनुपात रहा, उन्हें बाजार द्वारा मूल्य में तीव्र कमी का सामना करना पड़ा (सारणी 1)। ये निष्कर्ष

सारणी 1: प्रतिगमन परिणाम

संघर्ष	आश्रित चर: सीएआर (-1, +1)				
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4	मॉडल 5
आकार	0.050 (1.070)	0.070 (0.976)	0.127 (1.005)	-0.101 (0.997)	0.117 (0.782)
बैंक-समूह डमी	0.731 (2.625)	1.259 (2.404)	2.108 (2.667)	3.943 (2.814)	1.806 (1.931)
आरओई	-	0.100* (0.040)	-	-	-
सीईटी-1 अनुपात	-	-	0.724* (0.282)	-	-
जीएनपीए अनुपात	-	-	-	-0.414* (0.181)	-
गिरावट अनुपात (वार्षिकीकृत)	-	-	-	-	-1.180*** (0.238)
प्रेक्षणों की संख्या	30	30	30	30	30
प्रेक्षणों की संख्या	-0.07	0.11	0.09	0.08	0.43
बीआईसी	206.30	203.07	203.64	204.19	189.76

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. *** पी<0.001, **पी<0.01, * पी<0.5

बड़े समष्टि-आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए बैंकों के मजबूत तुलन-पत्र के महत्व को उजागर करते हैं।

संदर्भ

आचार्य, वीवी, एंगल III, आर.एफ., और स्टीफन, एस. (2021)। व्हाई डिड बैंक स्टॉक्स क्रैश ड्यूरिंग कोविड-19? (नंबर डब्ल्यू28559)। *नेशनल ब्यूरो इकोनॉमिक रिसर्च*।
डेमिगक-कुंट, ए. पेड्राजा, ए., एंड रुईज-ओर्टेगा, सी. (2021)। बैंकिंग सैक्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दि कोविड-19 क्राइसिस। *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस*, 106305।
माथुर, ए., सेनगुप्ता, आर., एंड प्रताप, बी. (2021)। सेव्ड बाई दि बेल? इक्विटी मार्केट रेस्पॉसेस टू सर्प्राइज कोविड-19 लॉकडाउन्स एंड सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन्स। (फोर्थकमिंग)
मैकिन्ले, ए.सी. (1997)। इवेंट स्टडीस इन इकोनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंस। *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर*, 35(1), 13-39.

7. वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप

IV.57 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी समामेलन, जिसमें 10 पीएसबी को 4 में समामेलित किया गया, के बाद केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

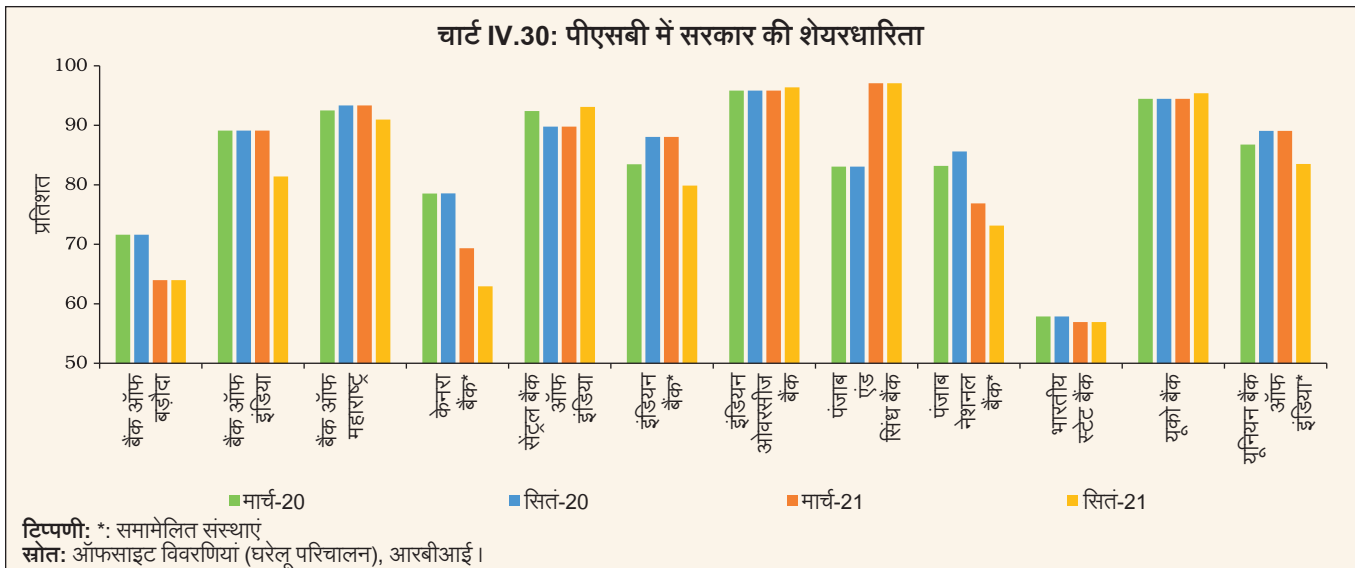
में सरकारी स्वामित्व काफी हद तक बढ़ गया।¹⁶ 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान, पंजाब एंड सिंध बैंक में पुनर्पूजीकरण¹⁷ के कारण सरकार की शेयरधारिता बढ़ी और निजी स्थानन के माध्यम से पूंजी जुटाने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की

¹⁵ दिसंबर 2019 के अंत की स्थिति में बैंक-वार तुलन-पत्र के आंकड़े आरबीआई डेटाबेस से प्राप्त किए गए थे।

¹⁶ सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ।

¹⁷ सितंबर 2020 में संसद ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पुनर्पूजीकरण के लिए ₹20,000 करोड़ के अनुदान की अनुपूरक मांग को अनुमोदित किया, जिसमें से नवंबर 2020 में पंजाब एंड सिंध बैंक में ₹5,500 करोड़ अंतर्वेशित किए गए थे।

चार्ट IV.30: पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता



शेयरधारिता में कमी आयी (चार्ट IV.30)। इसके अलावा सितंबर के अंत तक, बाजार से नई इक्विटी जुटाने के कारण बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी शेयरधारिता घट गई। 2021-22 के दौरान पीएसबी के लिए योजनाबद्ध पूंजी लगाने से उनके स्वामित्व के स्वरूप में और बदलाव आने की उम्मीद है¹⁸।

IV.58 वर्ष के दौरान एक निजी क्षेत्र के बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का एक विदेशी बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ 27 नवंबर 2020 से समामेलन हो गया। इसके साथ मार्च 2021 के अंत तक भारत में 21 परिचालनगत पीवीबी थे। विदेशी निवेश के संदर्भ में, पीवीबी सहित स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए अनिवासियों की शेयरधारिता 74 प्रतिशत और पीएसबी के लिए शेयरधारिता 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

8. कॉर्पोरेट अभिशासन

IV.59 बैंकों में प्रभावी अभिशासन और संतुलित क्षतिपूर्ति प्रथाएं जोखिम कम करने के महत्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि वे जमाकर्ता के भरोसे को बढ़ाते हैं और वित्तीय स्थिरता को भी

सुदृढ़ करते हैं। जून 2020 में जारी 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर चर्चा पत्र और उस पर प्राप्त प्रतिपुष्टि के बाद रिजर्व बैंक ने 26 अप्रैल, 2021 को कई परिचालनगत विषयों को संबोधित करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए।

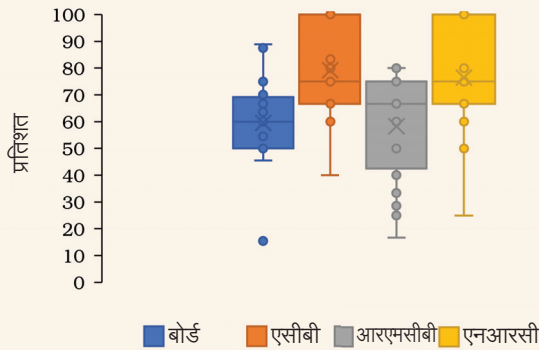
8.1 बोर्ड संरचना

IV.60 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सक्षमता, विविधता सुनिश्चित करने तथा योग्य और उपयुक्त मानदंड को पूरा करने के अलावा, बोर्ड की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में अधिकांश पीवीबी ने इसे भिन्न-भिन्न स्तर पर हासिल किया है, अपने बोर्ड के साथ-साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) सहित उनकी प्रमुख पर्यवेक्षी समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की प्रमुख उपस्थिति होती है (चार्ट IV.31)।

IV.61 कार्यात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड और प्रमुख पर्यवेक्षी समितियों में प्रबंधन की भूमिका को सीमित करना भी आवश्यक है। बोर्ड का अध्यक्ष इन समितियों का कोई सदस्य न हो, यह सुनिश्चित करने से भूमिका में मतभिन्नता को कम करने में मदद मिलती है। ऐसे पीवीबी, जहां अध्यक्ष एसीबी का सदस्य

¹⁸ केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में ₹20,000 करोड़ अंतर्वेशित करने का प्रस्ताव रखा।

चार्ट IV.31: पीवीबी में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी
(मार्च 2021 के अंत में)



टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट्स के विस्कर्स स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में अधिकतम और न्यूनतम हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। संगीन बॉक्स पहले क्वांटाइल और तीसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी को दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका को दर्शाती है जबकि 'एक्स' माध्य को दर्शाता है। बॉक्स के बाहर के बिंदु आउटलियर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

नहीं है, का हिस्सा मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 35 प्रतिशत था। हालांकि आरएमसीबी के मामले में शेयर 29 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।¹⁹

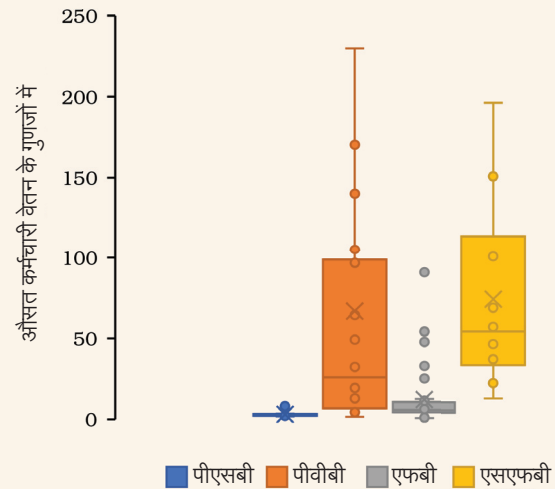
8.2 कार्यकारी पारिश्रमिक

IV.62 किसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को एक प्रतिनिधि बैंक कर्मचारी की तुलना में भुगतान किया गया पारिश्रमिक अलग-अलग बैंक समूहों में बहुत भिन्न होता है। पीएसबी के लिए, सीईओ औसतन सामान्य कर्मचारी²⁰ की तुलना में 3 गुना कमाते हैं, जबकि लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के मामले में यह 75 गुना और पीवीबी के मामले में 67 गुना जितना अधिक था। कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के अपेक्षाकृत

अधिक होने से एफबी के लिए तदनुसूची गुणज कम था। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान बैंक समूह में घट-बढ़ लगातार बनी रही (चार्ट IV.32)।

IV.63 पारिश्रमिक²¹ पर संशोधित दिशा-निर्देशों के लिए आवश्यक है कि सीईओ/ पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) के पारिश्रमिक को सभी प्रकार के जोखिम, उनके परिणामों और समय के दायरों के लिए समायोजित किया जाए। इसके अलावा, नकद, इक्विटी और भुगतान के अन्य रूपों का संयोजन जोखिम संरक्षण के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें परिवर्तनीय वेतन घटक को कुल वेतन के 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच होना चाहिए, जिसमें से आस्थगन व्यवस्था के तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत होना चाहिए

चार्ट IV.32: औसत कर्मचारी के वेतन की तुलना में सीईओ का वेतन
(मार्च 2020 के अंत में)

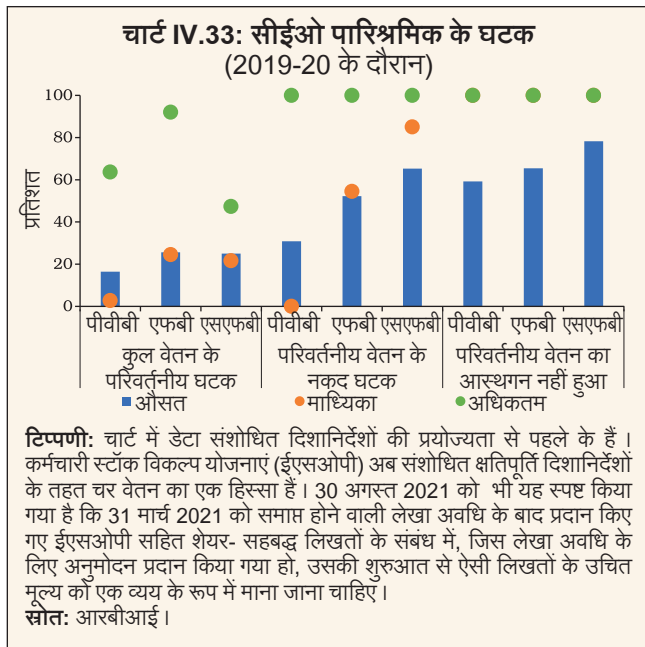


स्रोत: आरबीआई।

¹⁹ यहाँ दिए गए आंकड़े कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिनांक 26 अप्रैल 2021 के आरबीआई के परिपत्र जारी होने के पहले के हैं।

²⁰ औसत कर्मचारी वेतन की गणना कुल कर्मचारियों की संख्या के प्रति कुल स्टाफ लागत के अनुपात के रूप में की गई है।

²¹ रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2019 को पारिश्रमिक पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया और उन्हें एफएसबी मानदंडों के साथ अनुरूप बनाया। नए दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।



। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत परिवर्तनीय वेतन का नकद घटक भी 33 से 50 प्रतिशत²² के बीच सीमित है (चार्ट IV.33)।

9. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन

IV.64 वर्ष 2020-21 के दौरान देश में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों (एफबी) की संख्या एक साल पहले²³ की तुलना में कम हो गई, हालांकि 27 नवंबर, 2020 से प्रभावी लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक के साथ समामेलन के कारण एफबी की कुल शाखाओं में वृद्धि हुई (सारणी IV.19)। दूसरी ओर, पीएसबी अधिक लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए पिछले साढ़े तीन वर्षों से अपनी विदेशी उपस्थिति को कम कर रहे हैं। पीवीबी ने वर्ष के दौरान विदेशों में अपने कम लाभकर परिचालनों को भी बंद कर दिया (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

सारणी IV.19: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

	शाखाओं के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं	
मार्च-16	46	325	39
मार्च-17	44	295	39
मार्च-18	45	286	40
मार्च -19	45#	299*	37
मार्च -20	46#	308*	37
मार्च -21	45#	874*	36

टिप्पणियां: 1. #: इसमें दो विदेशी बैंक शामिल हैं, अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, जो पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) पद्धति के माध्यम से काम कर रहे हैं।
2. *: डब्ल्यूओएस पद्धति के माध्यम से संचालित एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार समामेलित संस्था अर्थात् लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाओं सहित) की शाखाएं शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

10. भुगतान प्रणाली और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.65 भारत में भुगतान प्रणाली परिदृश्य तेजी से प्रौद्योगिकीय उन्नति और नवोन्मेषों के कारण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो सहायक विनियामक नीतियों द्वारा समर्थित हैं। रिज़र्व बैंक की भुगतान और निपटान प्रणाली: विज़न 2019-2021 में ऐसी भुगतान प्रणालियों की परिकल्पना की गई है जो न केवल संरक्षित और सुरक्षित हैं, बल्कि प्रभावशाली, तेज़ और किफायती भी हैं। इसके अलावा, समाज के सभी तबकों द्वारा डिजिटल भुगतान सेवाओं को तेजी से अपनाने के लिए सरकार द्वारा अधिक जोर दिया गया है।

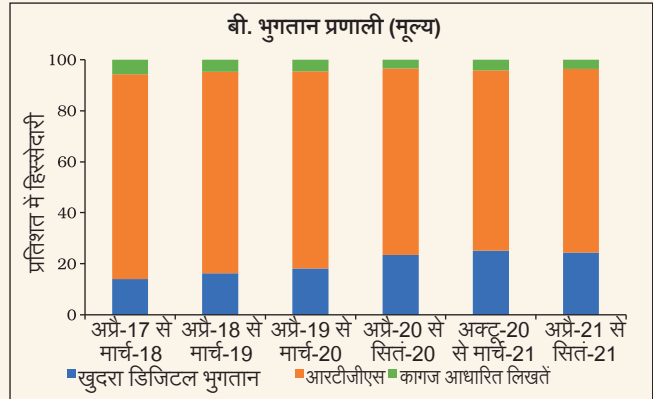
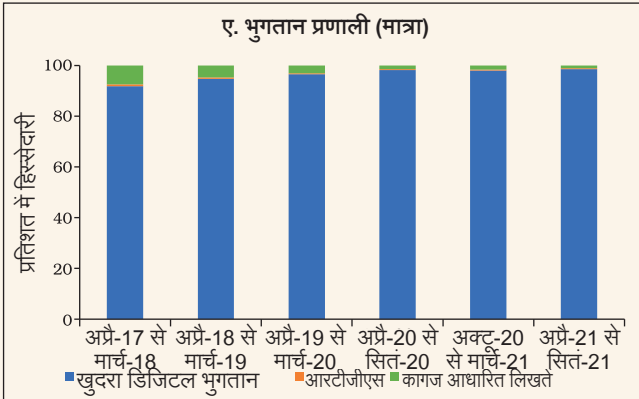
IV.66 भुगतान के डिजिटल तरीके पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक कागज-आधारित लिखतें जैसे चेक और मांग ड्राफ्ट अब इसका एक नगण्य हिस्सा हैं (चार्ट IV.34)

IV.67 कुल भुगतान की मात्रा में एक साल पहले की 43.7 प्रतिशत वृद्धि से 2020-21 के दौरान 26.7 प्रतिशत की कमी

²² यदि परिवर्तनीय वेतन नियत वेतन के 200 प्रतिशत तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत और यदि परिवर्तनीय वेतन 200 प्रतिशत से ऊपर है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 67 प्रतिशत गैर-नकद लिखतें होनी चाहिए।

²³ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दिनांक 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना डीओआर.आईबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के तहत वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन को रिज़र्व बैंक की दूसरी अनुसूची से हटाया गया था।

चार्ट IV.34: भुगतान प्रणाली के घटक



टिप्पणियां: 1. भुगतान के डिजिटल माध्यमों में आरटीजीएस और खुदरा डिजिटल भुगतान शामिल हैं।
2. खुदरा डिजिटल भुगतान में एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईसीएच, भीम आधार पे, ईपीएस फंड ट्रांसफर, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और पूर्वदत्त भुगतान लिखतें शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

आयी। मूल्य के संदर्भ में, कुल भुगतान में लगातार दूसरे वर्ष कमी आयी, जिसका मुख्य कारण आरटीजीएस और कागज-

आधारित लिखतों के माध्यम से होने वाले लेनदेनों के मूल्य में गिरावट थी (सारणी IV.20)।

सारणी IV.20: भुगतान प्रणाली के संकेतक

मद	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1. बड़ी राशि के क्रेडिट अंतरण – आरटीजीएस	1,366	1,507	1,592	13,56,88,187	13,11,56,475	10,55,99,849
2. क्रेडिट अंतरण	1,18,481	2,06,297	3,17,868	2,60,90,471	2,85,56,593	3,35,04,226
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण)	11	10	11	501	469	623
2.2 एपीबीएस	14,949	16,747	14,373	86,226	99,048	1,11,001
2.3 ईसीएस सीआर	54	18	-	13,235	5,146	-
2.4 आईएमपीएस	17,529	25,792	32,783	15,90,257	23,37,541	29,41,500
2.5 एनईसीएच सीआर	8,834	11,100	16,465	7,29,673	10,37,079	12,16,535
2.6 एनईएफटी	23,189	27,445	30,928	2,27,93,608	2,29,45,580	2,51,30,910
2.7 यूपीआई	53,915	1,25,186	2,23,307	8,76,971	21,31,730	41,03,658
3. नामे अंतरण और सीधे नामे डालना	4,914	6,027	10,457	5,24,556	6,05,939	8,65,520
3.1 भीम आधार पे	68	91	161	815	1,303	2,580
3.2 ईसीएस डीआर	9	1	-	1,260	39	-
3.3 एनईसीएच डीआर	4,830	5,842	9,646	5,22,461	6,04,397	8,62,027
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से सहबद्ध)	6	93	650	20	200	913
4. कार्ड भुगतान	61,769	72,384	57,787	11,96,888	14,34,813	12,91,799
4.1 क्रेडिट कार्ड	17,626	21,773	17,641	6,03,413	7,30,894	6,30,414
4.2 डेबिट कार्ड	44,143	50,611	40,146	5,93,475	7,03,920	6,61,385
5. पूर्वदत्त भुगतान लिखतें	46,072	53,811	49,743	2,13,323	2,15,558	1,97,696
6. कागज आधारित लिखतें	11,238	10,414	6,704	82,46,065	78,24,822	56,27,108
कुल - खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	2,42,473	3,48,933	4,42,557	3,62,71,304	3,86,37,726	4,14,86,348
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	2,32,602	3,40,026	4,37,445	16,37,13,425	16,19,69,379	14,14,59,089
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	2,43,839	3,50,440	4,44,149	17,19,59,490	16,97,94,201	14,70,86,197

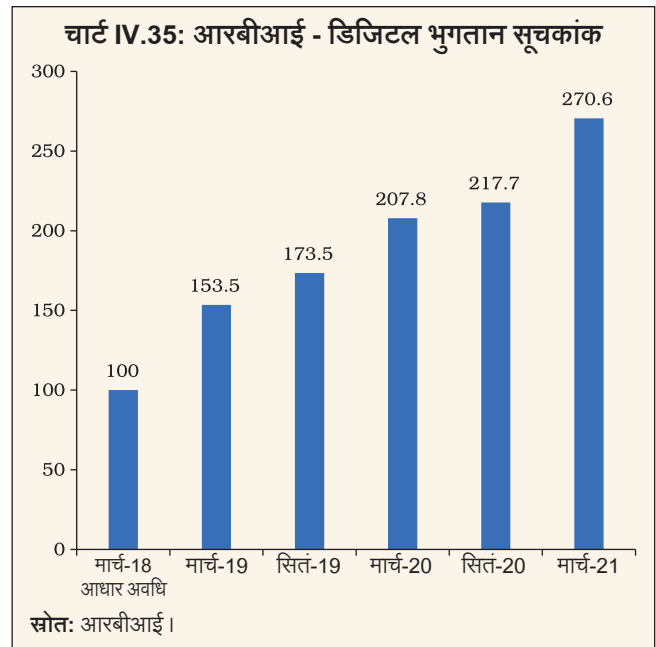
टिप्पणियां: 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. कार्ड के आंकड़े केवल बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल पर लेनदेन के लिए हैं, जिसमें ऑनलाइन भुगतान लेनदेन शामिल हैं।
3. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़ों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।
4. -:शून्य

स्रोत: आरबीआई।

10.1 डिजिटल भुगतान

IV.68 हालिया वर्षों में रिज़र्व बैंक भुगतान के डिजिटल तरीकों को व्यापक रूप से अपनाने और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। महामारी ने खुदरा डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने के लिए एक प्रोत्साहित किया। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) अर्थात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) की क्रमशः दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 से 24x7x365 उपलब्धता ने जोखिम को कम कर पूरे भुगतान परितंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाया है। जनवरी 2021, में परिचालित भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के वर्धन में सहायता की है, इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सीपीएस को गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता (पीएसपी)²⁴ का प्रत्यक्ष अभिगम प्रदान करने से सभी वर्गों के उपयोगकर्ताओं की डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच होगी।

IV.69 आरटीजीएस, जो वास्तविक समय के आधार पर उच्च मूल्य के लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, का मूल्य के संबंध में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र पर वर्चस्व है। दूसरी ओर, खुदरा क्षेत्र से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की लेनदेन की मात्रा में एक बड़ी हिस्सेदारी है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), भीम आधार पे और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) जैसी नवोन्मेषी भुगतान प्रणालियों का उपयोग - लेन-देनों में सुदृढ़ वृद्धि और संपर्क रहित भुगतान की अधिक स्वीकार्यता दर्शाती है (सारणी IV.20)। रिज़र्व बैंक ने डिजिटलीकरण की प्रगति को मापने और डिजिटल भुगतान की गहनता और पहुँच का आंकलन करने के लिए, जनवरी 2021 में



एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का सूत्रपात किया, जिसमें पांच व्यापक मापदंड शामिल हैं - (i) भुगतान सहायक (25 प्रतिशत भार); (ii) भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर - मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत); (iii) भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर - आपूर्ति पक्ष कारक (15 प्रतिशत); (iv) भुगतान निष्पादन (45 प्रतिशत); और (v) उपभोक्ता केन्द्रीयता (5 प्रतिशत)। सूचकांक की गणना छमाही रूप से मार्च 2018 को आधार अवधि मान कर की जाती है (चार्ट IV.35)।

10.2 एटीएम

IV.70 वर्ष 2020-21 के दौरान एससीबी द्वारा संचालित स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) (शाखा स्थित और शाखेतर) की कुल संख्या में 2018-19 में गिरावट के बाद लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि हुई। हालांकि, अधिक लागत दक्षता को प्राप्त करने के लिए नेटवर्क बाह्यताओं के माध्यम से लाभ उठाने हेतु पीएसबी एटीएम की संख्या में कमी आयी (सारणी IV.21)।

²⁴ इनमें पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) परिचालक शामिल हैं।

सारणी IV.21: एटीएम की संख्या
(मार्च के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	शाखा स्थित एटीएम		शाखेतर एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
I	पीएसबी	80,691	78,007	57,855	59,106	1,38,546	1,37,113
II	पीवीबी	30,483	34,828	38,886	37,566	69,369	72,394
III	एफबी	225	690	678	1,135	903	1,825
IV	एसएफबी*	1,870	2,079	56	52	1,926	2,131
V	पीबी#	2	1	14	111	16	112
VI	डब्ल्यूएलए	-	-	-	-	23,597	25,013
VII	सभी एससीबी (I से V)	1,13,271	1,15,605	97,489	97,970	2,10,760	2,13,575
VIII	कुल (VI+VII)	-	-	-	-	2,34,357	2,38,588

टिप्पणियां: 1. *: मार्च 2020 के अंत और मार्च 2021 के अंत तक 10 अनुसूचित एसएफबी।
2. #: मार्च 2020 के अंत और मार्च 2021 के अंत तक 1 अनुसूचित पीबी (पेटीएम पेमेंट्स बैंक)
स्रोत: आरबीआई।

IV.71 मार्च 2021 के अंत में एससीबी की कुल एटीएम संख्या में घनी आबादी वाले शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 56 प्रतिशत की अधिकांश हिस्सेदारी थी। जबकि पीएसबी के एटीएम

भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक समान रूप से संवितरित थे, अन्य बैंक-समूहों के एटीएम शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित थे। इसके विपरीत, अधिकांश व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) (लगभग 85 प्रतिशत) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित थे (सारणी IV.22)।

सारणी IV.22: बैंक समूह वार एटीएम का भौगोलिक वितरण
(मार्च 2021 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगर	कुल
		3	4	5	6	7
I	पीएसबी	28,255 (20.6)	39,349 (28.7)	39,725 (29.0)	29,784 (21.7)	1,37,113 (100.0)
II	पीवीबी	6,140 (8.5)	18,197 (25.1)	18,918 (26.1)	29,139 (40.3)	72,394 (100.0)
III	एफबी	96 (5.3)	365 (20.0)	413 (22.6)	951 (52.1)	1,825 (100.0)
IV	एसएफबी *	241 (11.3)	665 (31.2)	651 (30.5)	574 (26.9)	2,131 (100.0)
V	पीबी#	21 (18.8)	28 (25.0)	28 (25.0)	35 (31.3)	112 (100.0)
VI	सभी एससीबी (I से V)	34,753 (16.3)	58,604 (27.4)	59,735 (28.0)	60,483 (28.3)	2,13,575 (100.0)
VII	सभी एससीबी (पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)	3.0	1.3	2.2	-0.4	1.3
VIII	डब्ल्यूएलए	13,187 (52.7)	8,162 (32.6)	2,296 (9.2)	1,368 (5.5)	25,013 (100.0)
IX	डब्ल्यूएलए (पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)	14.3	3.8	-7.8	-19.8	6.0

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. *: मार्च 2020 के अंत और मार्च 2021 के अंत तक 10 अनुसूचित एसएफबी।
3. #: मार्च 2020 के अंत और मार्च 2021 के अंत तक 1 अनुसूचित पीबी (पेटीएम पेमेंट्स बैंक)
स्रोत: आरबीआई

11. उपभोक्ता संरक्षण

IV.72 रिजर्व बैंक का प्रयास है कि एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से बैंक ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रौद्योगिकी-आधारित बैंकिंग उत्पादों के आगमन और समाज के असुरक्षित वर्गों द्वारा इन उत्पादों के बढ़ते उपयोग के साथ वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता काफी महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर, 2021 को रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के आरंभ का उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए एक झंझट-रहित शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना है। यह योजना प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के अधिकार-क्षेत्र को समाप्त करते हुए, योजना में परिभाषित सेवाओं (बहिष्करण सूची में उल्लिखित को छोड़कर) और आरई द्वारा प्रदान की गई 'सेवाओं में कमी' पर आधारित सभी प्रकार की ग्राहक शिकायतों को शामिल करती है।

सारणी IV.23: बैंकिंग लोकपाल (बीओ) में शिकायतों का स्वरूप

संवर्ग	2018-19	2019-20	2020-21
एटीएम/ डेबिट कार्ड	29,603	69,205	60,203
मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	12,051	39,627	44,385
क्रेडिट कार्ड	13,172	26,616	40,721
प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में असफलता	11,948	22,758	35,999
उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करना	39,188	40,124	33,898
बिना पूर्व सूचना के प्रभार लगाना	7,518	17,268	20,949
ऋण और अग्रिम	6,380	14,731	20,218
बीसीएसबीआई संहिता का अनुपालन नहीं करना	5,921	11,758	14,490
जमा खाता	8,520	10,188	8,580
पेंशन का भुगतान	7,331	6,884	4,966
विप्रेषण	3,277	4,130	3,394
सीधी बिक्री एजेंट (डीएसए) और वसूली एजेंट	602	1,474	2,440
पैरा-बैंकिंग	1,127	1,134	1,236
नोट और सिक्के	799	551	332
अन्य	31,339	30,844	39,686
बीओ योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर	5,956	9,412	10,250
कुल	1,84,732	3,06,704	3,41,747

टिप्पणी: अप्रैल से मार्च से संबंधित आंकड़े।

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

IV.73 वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के पास शिकायतों की संख्या में कमी आयी और इस दौरान कुल शिकायतों में से एटीएम/ डेबिट कार्ड, मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत 42.5 था (सारणी IV.23)।

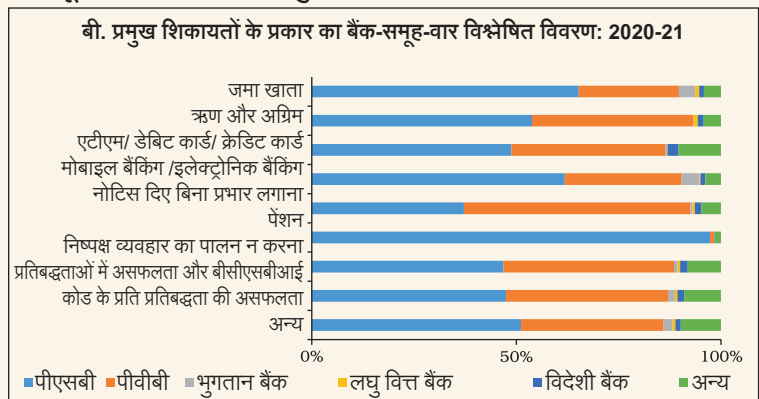
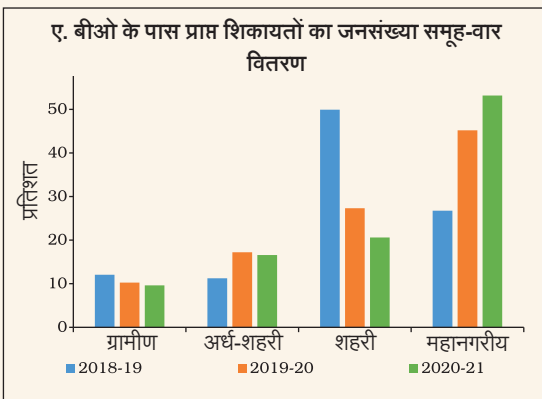
IV.74 शहरी और महानगरीय क्षेत्रों से आने वाली शिकायतों का हिस्सा 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों के 73

प्रतिशत से अधिक पाया गया। इसके अलावा, महानगरीय ग्राहकों की शिकायतों का हिस्सा 2020-21 में 2018-19 के स्तर से लगभग दोगुना हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी ग्राहकों की शिकायतों का हिस्सा काफी कम हो गया (चार्ट IV.36ए)।

IV.75 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से के लिए पीएसबी और पीवीबी उत्तरदायी हैं। पेंशन संबंधी लगभग सभी शिकायतें पीएसबी, जो कि पेंशनभोगियों की पारंपरिक प्राथमिकता है, के खिलाफ दर्ज की गईं। दूसरी ओर, पीवीबी के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभार लगाने से संबंधित शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा (55 प्रतिशत) दर्ज किया गया था (चार्ट IV.36बी, परिशिष्ट सारणी IV.8)।

IV.76 छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और इस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने में निक्षेप बीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को निक्षेप बीमा प्रदान करता है। मार्च 2021 के अंत तक 98.1 प्रतिशत जमाकर्ता ₹5 लाख के कवर के तहत बीमा-संरक्षित थे, और कुल राशि की लगभग 51 प्रतिशत जमा राशि बीमा द्वारा

चार्ट IV.36: शिकायतों का जनसंख्या समूह-वार वितरण और प्रमुख शिकायतों के प्रकार



टिप्पणियां: 1. अप्रैल से मार्च से संबंधित आंकड़े

2. 2020-21 के दौरान 1,20,671 शिकायतों अर्थात् 35% शिकायतों के लिए जनसंख्या समूह-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुपात को बनाए रखते हुए ऐसी सभी शिकायतों के लिए उपलब्ध आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है।

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

सारणी IV.24: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमा राशियां
(31 मार्च, 2021 की स्थिति में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	कुल कर निर्धारणीय जमा राशियां (एडी)*	कुल बीमाकृत जमा राशियां (आईडी)*	एडी के प्रतिशत के रूप में आईडी
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	85,23,813	47,91,132	56.2
निजी क्षेत्र के बैंक**	37	42,77,955	17,01,193	39.8
विदेशी बैंक	45	7,06,141	47,970	6.8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,66,478	3,91,451	83.9
सहकारी बैंक	1,919	9,92,491	6,88,790	69.4
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	892	714	80.1
कुल	2,058	1,49,67,770	76,21,251	50.9

टिप्पणियां: 1. *: सितंबर 2020 के जमा राशि आधार पर आधारित, अर्थात् संदर्भगत दिनांक से छह माह पूर्व।

2. **: निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों में दस लघु वित्त बैंकों और छह भुगतान बैंकों के आंकड़े शामिल हैं।

स्रोत: निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम।

रक्षित थी (सारणी IV.24)।

IV.77 जमा बीमा निधि (डीआईएफ) का उपयोग ऐसे बैंकों, जिनका परिसमापन/समामेलन हो चुका है, के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है, उसका आकार 31 मार्च, 2021 की स्थिति में ₹1,29,904 करोड़ था, जिससे आरक्षित निधि अनुपात एक साल पहले के 1.61 प्रतिशत से बढ़कर 1.70 प्रतिशत हो गया²⁵। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान ₹993 करोड़ राशि के दावों को प्रसंस्कृत और संस्वीकृत किया गया, जिसमें से ₹564 करोड़ के दावे नौ सहकारी बैंकों से संबंधित थे। हालांकि 2020-21 के दौरान दावों के निपटान के लिए निधियों के निवल व्यय की तुलना में ₹ 569 करोड़ की कम वसूली हुई।

12. वित्तीय समावेशन

IV.78 वित्तीय समावेशन संतुलित आर्थिक वृद्धि के चालक के रूप में कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)²⁶ का नवीनतम वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण (एफएस) वित्तीय समावेशन

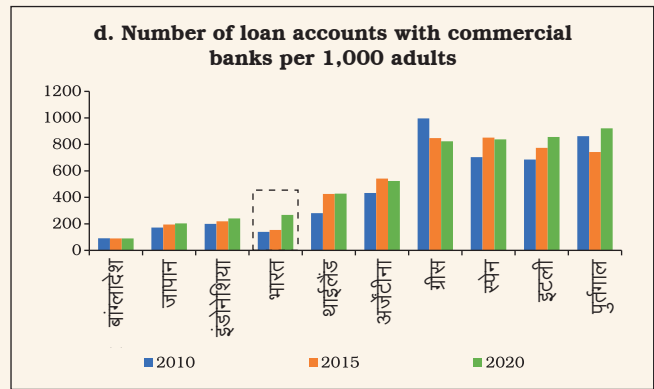
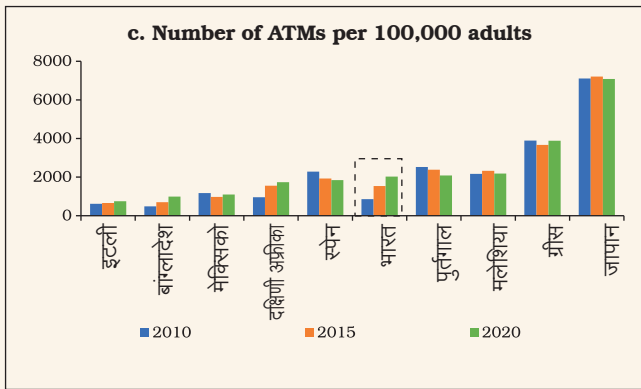
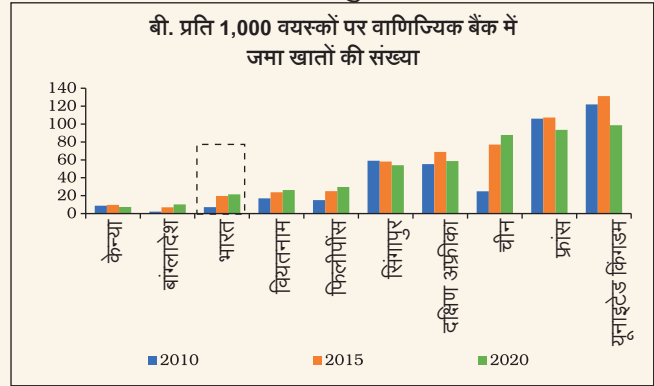
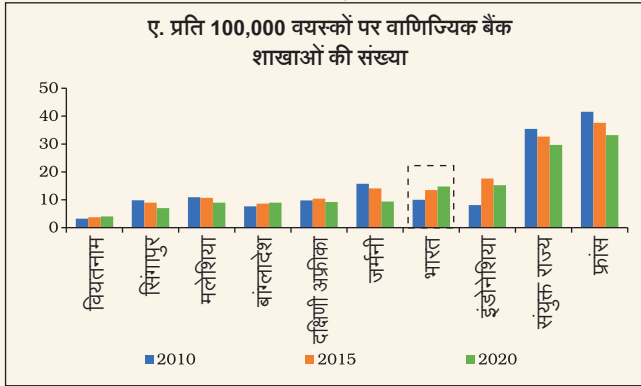
की अंतिम समस्या से निपटने और पिछले दशक में वित्तीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने में भारत द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है। प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और आधार और मोबाइल फोन के साथ इसकी सहबद्धता ने जेएम ट्रिनिटी का निर्माण किया, जो न केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)के अंतरण कल्याणकारी योजनाओं के लिए बल्कि वित्तीय समावेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पिछले दशक में भारत ने वाणिज्यिक बैंक शाखाओं और जमा खातों की संख्या को अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में विस्तारित करने में काफी प्रगति की है, हालांकि यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) द्वारा प्राप्त स्तरों से नीचे है (चार्ट IV.37ए और बी)। बैंकिंग लोकसंपर्क में वृद्धि के साथ, प्रति 100,000 वयस्कों पर एटीएम की संख्या में भी वृद्धि हुई है, हालांकि, अंतरराष्ट्रीय तुलना में व्यापन कम रहा (चार्ट IV.37सी)। प्रति 1,000 वयस्कों पर वाणिज्यिक बैंकों के ऋण खातों की संख्या भी देश के समकक्षों की तुलना में कम रही (चार्ट IV.37डी)।

IV.79 रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-2024 (एनएसएफआई) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 (एनएसएफई) को क्रमशः जनवरी 2020 और अगस्त 2020 में जारी किया गया था, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ता संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए अगस्त 2021 में वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई सूचकांक) की शुरुआत की (बॉक्स IV.4)।

²⁵ बीमाकृत जमा राशियों के प्रतिशत के रूप में निक्षेप बीमा निधि के रूप में परिभाषित।

²⁶ <https://data.imf.org/?sk=ESDCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C> पर उपलब्ध है।

चार्ट IV.37: चुनिंदा उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति



स्रोत: फ्राइनेशियल एक्सेस सर्वे, आईएमएफ।

IV.80 भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति के दो अलग-अलग स्तंभ हैं (ए) डिजिटल प्रौद्योगिकी (फिनटेक) में

उन्नति; और (बी) महिलाओं की अधिक भागीदारी। वित्तीय समावेशन, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए एक प्रमुख

बॉक्स IV.4: वित्तीय समावेशन सूचकांक

रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2021 में जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई सूचकांक) देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति का चित्रण करने के लिए प्रासंगिक संकेतकों को एक समग्र सूचकांक में समाहित करता है। यह सूचकांक औपचारिक वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है और पहुंच की सहजता, उपलब्धता, उपयोग की सीमा और सेवाओं की गुणवत्ता, सेवाओं में असमानता और कमी, वित्तीय साक्षरता के विस्तार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई) की गणना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के समान, एफआई सूचकांक तीन उप-सूचकांकों (कोष्ठक में भार दर्शाए गए हैं) पर आधारित है, अर्थात् अभिगम (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) (चार्ट 1)। 97 संकेतकों में

से 90 प्राथमिक संकेतक हैं और शेष 7 संकेतक असमानता के पैमाने हैं, जिनकी गणना लॉरेंज वक्र विश्लेषण के आधार पर जीआईएनआई गुणांक के रूप में की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का प्रयोग करके मुद्रास्फीति के लिए संकेतकों को समायोजित किया जाता है। चूंकि चयनित संकेतकों को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है, उन्हें निम्न सूत्र के आधार पर एकत्रीकरण से पहले सामान्यीकृत किया जाता है:

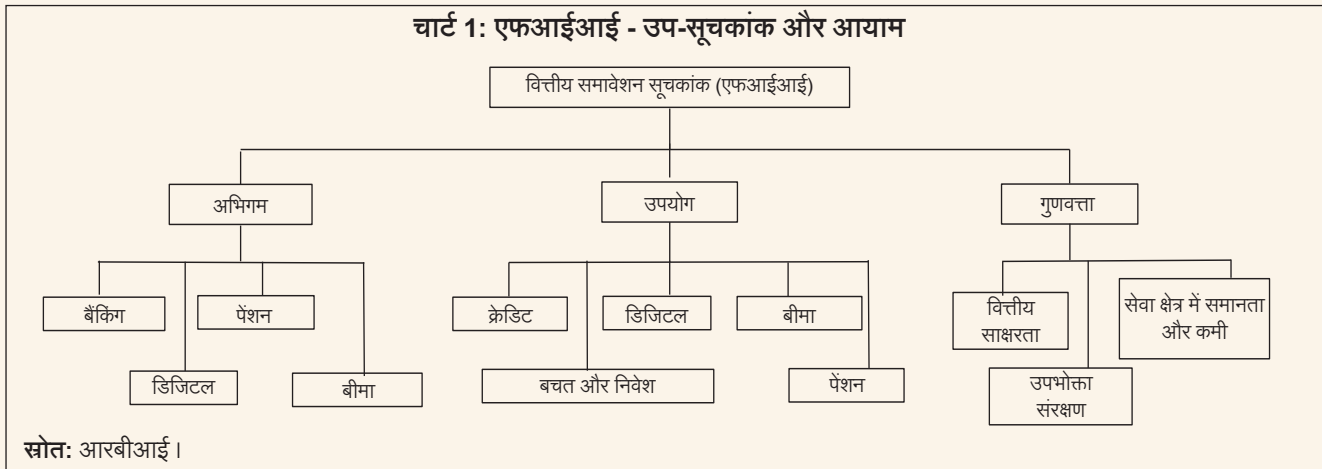
$$\text{Normalised value } (N_i) = \frac{Y_i - \text{state when no financial services were available}}{\text{Desired goal based on policy thrust and resources } (t_i)}$$

$$N_i = \frac{Y_i - 0}{t_i} = \frac{Y_i}{t_i}$$

जहां, संकेतक और संकेतक के वांछित लक्ष्य को घोषित करते हैं। चूंकि वित्तीय समावेशन की पूर्ण अनुपस्थिति के संबंध में संकेतक सामान्यीकृत हैं,

(Contd...)

चार्ट 1: एफआईआई - उप-सूचकांक और आयाम



स्रोत: आरबीआई।

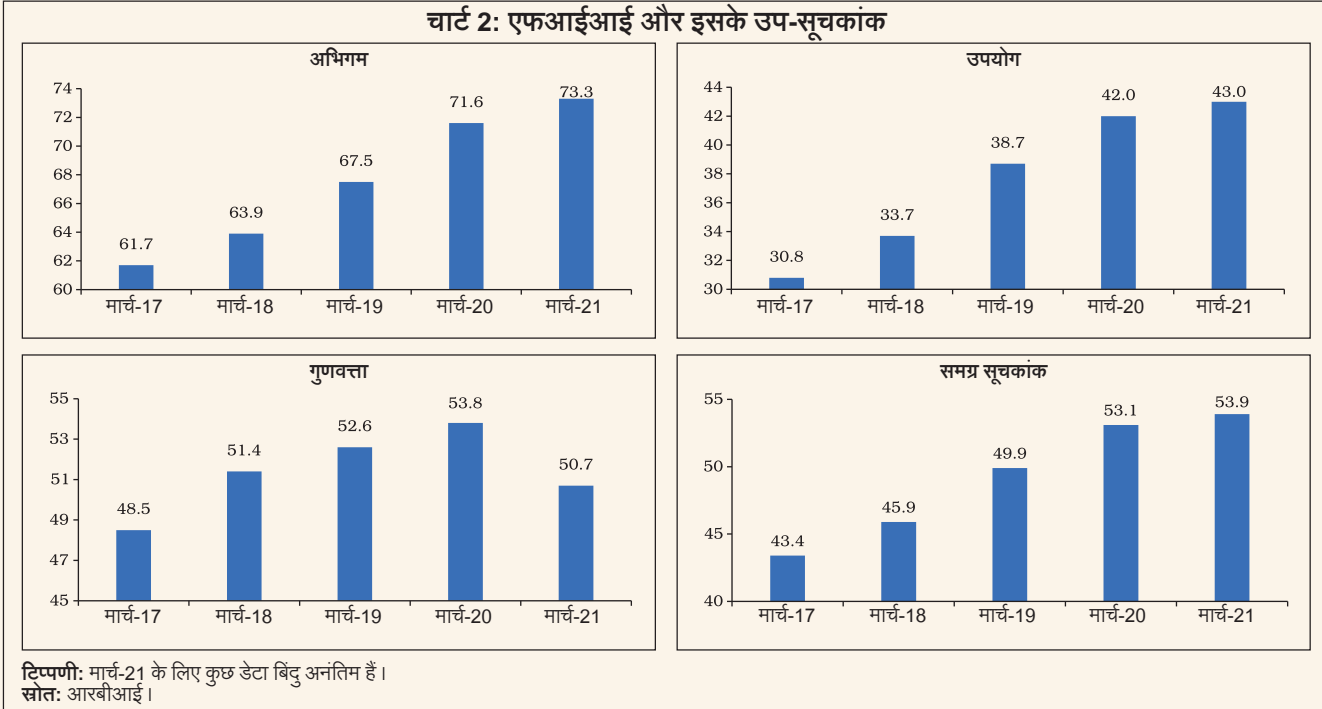
इसलिए सूचकांक के लिए कोई आधार वर्ष निर्धारित नहीं है (अर्थात्, प्रत्येक घटक संकेतक का मूल्य अब तक की अपनी ऐतिहासिक प्रगति पर निर्भर करता है)। फलस्वरूप, प्रत्येक सामान्यीकृत संकेतक का न्यूनतम मान '0' है और उच्चतम मान '100' है।

वित्तीय समावेशन के एकल पैमाने पर पहुंचने के लिए प्रत्येक आयाम के लिए बहिर्जात रूप से निर्धारित भार के आधार पर सामान्यीकृत संकेतक एकत्र किए जाते हैं। इन परिकल्पित आयामों का उपयोग तीन उप-सूचकांकों के निर्माण के

लिए किया जाता है, जिन्हें बाद में एकत्र कर समग्र एफआई सूचकांक बनाई जाती है।

अब तक उपलब्ध सूचकांक के आंकड़े बताते हैं कि एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता की तुलना में एफआई-अभिगम काफी अधिक है। वित्तीय पहुंच प्रदान करने में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए, यह उस आधार पर भी प्रकाश डालता है जिसे बेहतर उपयोग और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता के लिए शामिल करने की आवश्यकता है (चार्ट 2)।

चार्ट 2: एफआईआई और इसके उप-सूचकांक

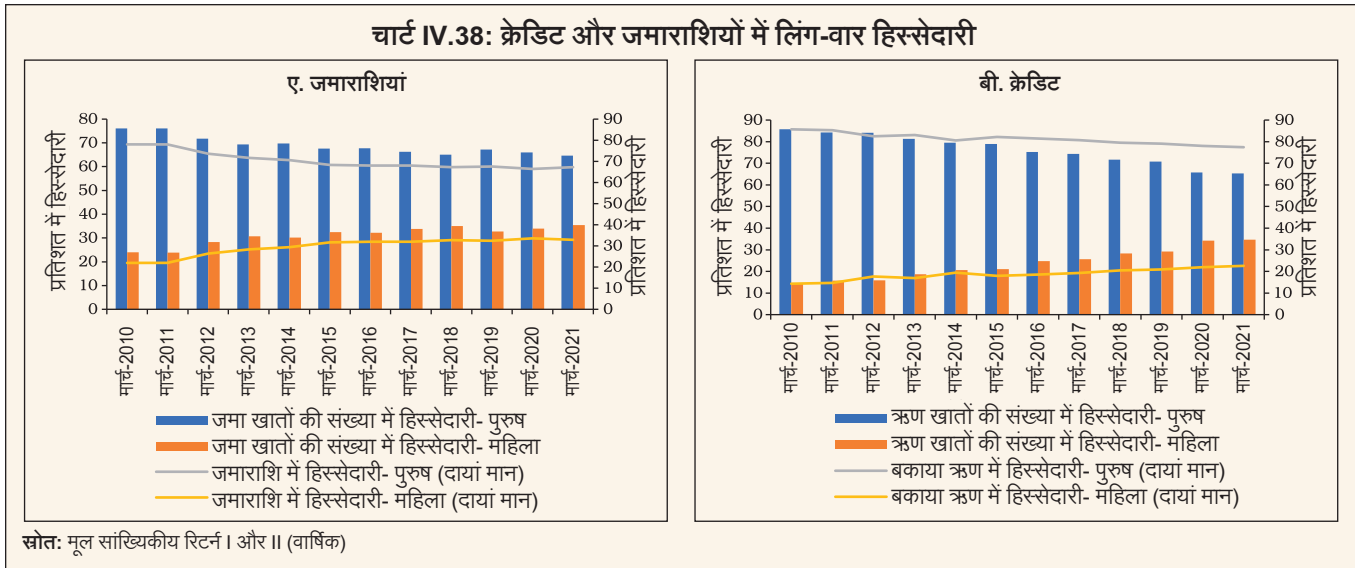


टिप्पणी: मार्च-21 के लिए कुछ डेटा बिंदु अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई।

संदर्भ: शर्मा ए. के., सेनगुप्ता एस., रॉय आई., और फुकन एस. (2021), आरबीआई बुलेटिन, वॉल्यूम एलएक्सएक्सवी, नंबर 9, पीपी 89-95, सितंबर 2021।

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx पर उपलब्ध है।

चार्ट IV.38: क्रेडिट और जमाराशियों में लिंग-वार हिस्सेदारी



सूत्रधार के रूप में कार्य करता है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करता है। पीएमजेडीवाई के तहत 15 दिसंबर 2021 तक महिला लाभार्थियों के लिए 24.54 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो योजना के तहत कुल खाताधारकों का 55.6 प्रतिशत है। पिछले दशक में महिला उधारकर्ताओं के ऋण खातों और बकाया ऋणों की संख्या क्रमशः 43.2 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ी, जबकि पुरुष उधारकर्ताओं के लिए यह क्रमशः 29.0 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत थी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जमा खातों की संख्या और जमा राशियों में भी तीव्र दर से वृद्धि हुई, जो औपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग में लैंगिक असमानता में कमी को दर्शाता है (चार्ट IV.38)। महिला-केंद्रित वित्तीय उत्पाद और वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल जैसे कि महिला कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने इस दिशा में मदद की। इन विकासों के बावजूद, अधिक-से-अधिक वित्तीय समानता प्राप्त करने और महिलाओं को शामिल करने के लिए और प्रगति करने की आवश्यकता है।

12.1 वित्तीय समावेशन योजनाएं

IV.81 वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) को रिजर्व बैंक द्वारा 2010 में वित्तीय समावेशन के लिए एक नियोजित

और संरचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी रिटर्न यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान में प्रगति हुई है और समय के साथ उनका उपयोग भी बढ़ा है। हालांकि, पारंपरिक भौतिक बैंकिंग शाखाओं की वृद्धि धीमी रही है, जबकि बीसी के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्व बढ़ा है। मार्च 2021 के अंत में 2,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बीसी की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट में से बीसी आउटलेट का हिस्सा 95 प्रतिशत से अधिक था। उपयोग के क्षेत्र में, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित लेनदेनों में बीसी के माध्यम से 2020-21 के दौरान मजबूत वृद्धि देखी गई (सारणी IV.25)।

12.2 प्रधान मंत्री जन धन योजना

IV.82 अगस्त 2014 में अपनी स्थापना के बाद से पीएमजेडीवाई देश की वंचित और कम-सेवा प्राप्त आबादी के वित्तीय समावेशन में योगदान दे रही है। सात वर्षों की अवधि में पीएमजेडीवाई के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 44.12 करोड़ हो गई, जिनके खातों में 15 दिसंबर 2021 की

सारणी IV.25: वित्तीय समावेशन योजना में हुई प्रगति

क्र. सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंत में	मार्च 2015 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	मार्च 2020 के अंत में	मार्च 2021* के अंत में
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- शाखाएं	33,378	49,571	52,489	54,561	55,112
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट>2000-बीसी	8,390	90,877	1,30,687	1,49,106	8,50,406 ^
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट<2000- बीसी	25,784	4,08,713	4,10,442	3,92,069	3,40,019
4	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – बीसी	34,174	4,99,590	5,41,129	5,41,175	11,90,425 ^
5	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – अन्य पद्धतियां	142	4,552	3,537	3,481	2,542
6	गांवों में बैंकिंग आउटलेट-कुल	67,694	5,53,713	5,97,155	5,99,217	12,48,079
7	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	96,847	4,47,170	6,35,046	4,26,745 ^
8	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,103	2,547	2,616	2,659
9	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	36,498	87,765	95,831	1,18,392
10	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	1,878	3,195	3,388	3,796
11	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	7,457	53,195	72,581	87,623
12	बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	735	3,981	5,742	6,004	6,455
13	बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	5,500	43,955	1,40,960	1,68,412	2,06,015
14	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (संख्या लाख में)	2	76	59	64	60
15	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (राशि करोड़ में)	10	1,991	443	529	534
16	केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	240	426	491	475	466
17	केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,68,044	6,39,069	6,72,624
18	जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	10	92	120	202	202
19	जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,30,160	1,74,514	1,94,048	1,55,826
20	आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में) #	270	4,770	21,019	32,318	47,668
21	आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ रुपये में) #	700	85,980	5,91,347	8,70,643	11,48,237

टिप्पणियां: 1. *: अनंतिम

2. ^: बैंक द्वारा किए गए पुनर्वर्गीकरण के कारण आंकड़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

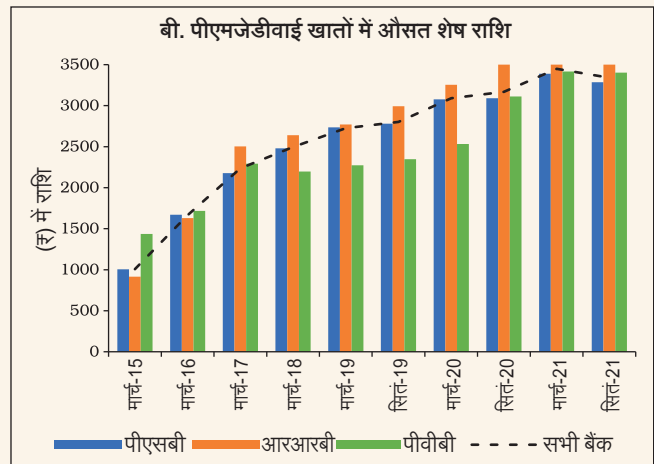
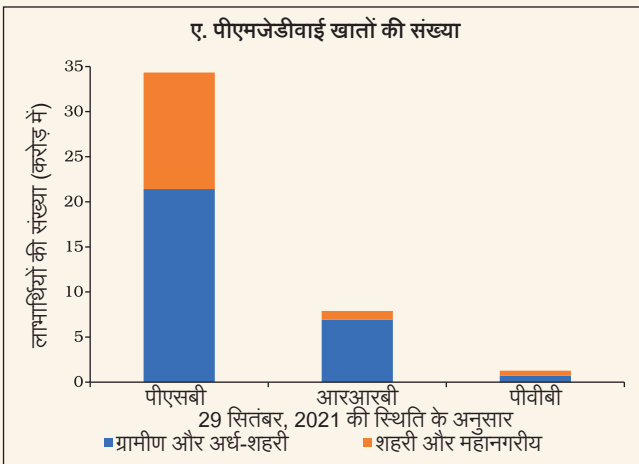
3. #: वर्ष के दौरान लेनदेन।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां।

स्थिति में ₹1.49 लाख करोड़ जमा थे²⁷। इनमें से अधिकांश खाते पीएसबी और आरआरबी (97 प्रतिशत) में हैं, जिसमें कुल खातों में से लगभग दो-तिहाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिचालनगत हैं (चार्ट IV.39ए)। हालांकि, सितंबर 2021 के

लिए सभी बैंक समूहों में इन खातों के उपयोग में औसत शेष राशि में मामूली गिरावट से कमी स्पष्ट है (चार्ट IV.39बी)। पीएसबी और आरआरबी, दोनों द्वारा जारी किए गए रुपये डेबिट कार्ड की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

चार्ट IV.39: पीएमजेडीवाई खाते: संवितरण और औसत शेष राशि



स्रोत: प्रधान मंत्री जन धन योजना, भारत सरकार

²⁷ <https://pmjdy.gov.in/account> पर उपलब्ध है।

12.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नई बैंक शाखाएँ

IV.83 बीसी मॉडल का लाभ उठाने तथा स्वचालन और डेटा वैश्लेषिकी द्वारा समर्थित बैंकिंग परिचालनों के डिजिटलीकरण के लिए बैंकों के केंद्र बिन्दु के साथ, लगातार दूसरे वर्ष नई बैंक शाखाओं के खुलने में कमी आयी। 2020-21 के दौरान एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं में पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत के संकुचन के अलावा 29.2 प्रतिशत की गिरावट आयी है। पीएसबी को छोड़कर सभी जनसंख्या समूहों के साथ-साथ बैंक समूहों में गिरावट आयी, वहीं पीएसबी में एक साल पहले की तुलना में उनकी भौतिक शाखा बैंकिंग के अभिगम में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट IV.40)।

IV.84 हालांकि सभी टिअर केंद्रों में कम शाखाएं खोली गईं, जिनमें से 2020-21 में आधे से भी अधिक नई शाखाएं टिअर 1 और टिअर 2 केंद्रों में खोली गईं (सारणी IV.26)।

12.4 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.85 सूक्ष्म वित्त में कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों के लिए छोटे ऋणों और अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार शामिल

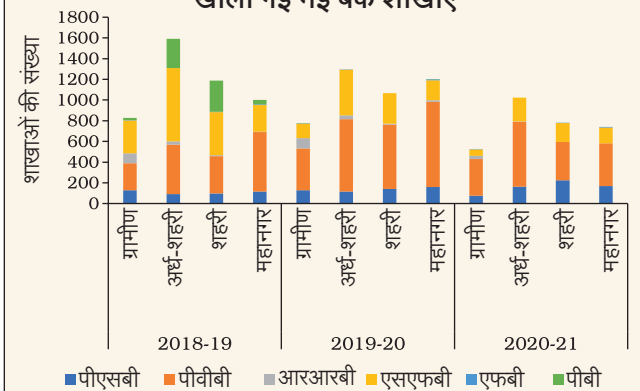
सारणी IV.26: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं का टिअर-वार विवरण

केंद्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
टिअर 1	1694 (40.2)	2191 (47.5)	2266 (52.3)	1520 (49.6)
टिअर 2	359 (8.5)	520 (11.3)	371 (8.6)	280 (9.1)
टिअर 3	620 (14.7)	709 (15.4)	568 (13.1)	481 (15.7)
टिअर 4	374 (8.9)	361 (7.8)	354 (8.2)	262 (8.5)
टिअर 5	472 (11.2)	373 (8.1)	282 (6.5)	177 (5.8)
टिअर 6	693 (16.5)	454 (9.9)	492 (11.4)	346 (11.3)
कुल	4212 (100.0)	4608 (100.0)	4333 (100.0)	3066 (100.0)

टिप्पणियाँ: 1. केंद्रों का टिअर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है: 'टिअर 1' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 1,00,000 और उससे अधिक है, 'टिअर 2' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 50,000 से 99,999 है, 'टिअर 3' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 20,000 से 49,999 तक, 'टिअर 4' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 10,000 से 19,999 है 'टिअर 5' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 5,000 से 9,999 है और 'टिअर 6' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 5,000 से कम है।
2. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
3. जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार हैं।
4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में खोली गई शाखाओं के अनुपात को दर्शाते हैं।

स्रोत: सीआईएसबीआई (पूर्ववर्ती मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) डेटाबेस, आरबीआई (01 दिसंबर, 2021 की स्थिति में)। सीआईएसबीआई डेटा प्रकृति में गतिशील हैं और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं और हमारी ओर से संसाधित होते हैं।

चार्ट IV.40: बैंक और जनसंख्या समूह वार एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाएँ



टिप्पणियाँ: 1. जनसंख्या-समूह वार केंद्रों का वर्गीकरण इस प्रकार है: 'ग्रामीण' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 9,999 से कम है, 'अर्ध-शहरी' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 10,000 से 99,999 है, 'शहरी' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 1,00,000 से 9,99,999 है और 'महानगर' में ऐसे केंद्र शामिल हैं जिनकी आबादी 10,00,000 और उससे अधिक है।
2. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
3. जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार हैं।
स्रोत: सीआईएसबीआई (पूर्ववर्ती मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) डेटाबेस, आरबीआई (01 दिसंबर, 2021 की स्थिति में)। सीआईएसबीआई डेटा प्रकृति में गतिशील हैं और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं और हमारी ओर से संसाधित होते हैं।

है, जो अन्यथा औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित हैं। इन वर्षों में, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से जनसंख्या के बैंक रहित और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के बीच लाभार्थियों की संख्या और विस्तारित सूक्ष्म ऋण के मामले में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) दुनिया के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है।

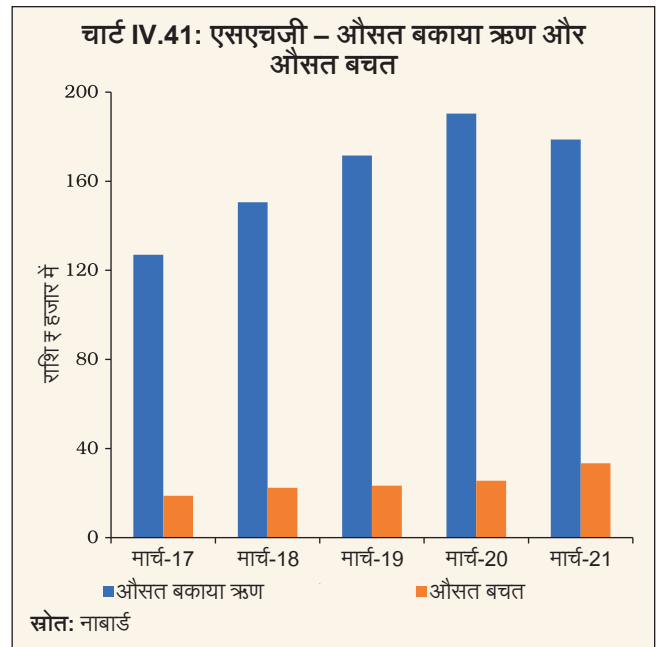
IV.86 मार्च-2021 की समाप्ति पर, जबकि बैंकों के साथ एसएचजी की बचत में 43.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बैंकों के पास उनके बकाया ऋण में मार्च-2020 की समाप्ति के स्तर में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई। 2020-21 के दौरान वितरित ऋणों में एक वर्ष पहले 33.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 25.2 प्रतिशत की गिरावट हुई। संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सूक्ष्म ऋण वितरण भी क्रमशः 30 प्रतिशत और 37 प्रतिशत तक सीमित हुआ, जो महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की वजह से है (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

IV.87 औसतन, प्रति एसएचजी बचत की राशि 2019-20 में ₹25,531 से 2020-21 में ₹33,392 तक, 30.8 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति एसएचजी बकाया ऋण ₹1.90 लाख से 5.8 प्रतिशत घटकर ₹1.79 लाख तक कम हो गया है (चार्ट IV.41)। हालांकि, एसएचजी के एनपीए अनुपात में सुधार जारी रहा, जो 2018-19 में 5.2 प्रतिशत (2019-20 में 4.9 प्रतिशत) से 2020-21 में 4.7 प्रतिशत रहा।²⁸

12.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण

IV.88 एमएसएमई खातों की संख्या 2020-21 के दौरान सभी एससीबी के लिए कम हुई, जो मुख्य रूप से पीवीबी और एफबी द्वारा प्रेरित थी। कुल एमएसएमई बकाया ऋण में पीएसबी की हिस्सेदारी में 2017-18 के बाद से निरपेक्ष रूप में गिरावट देखी गई है, जिसमें पीवीबी के हिस्से में तदनुरूप वृद्धि हुई है। हालांकि, पीवीबी द्वारा वितरित ऋण की औसत राशि पीएसबी की तुलना में बहुत कम थी (सारणी IV.27)।



12.6 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

IV.89 एमएसएमई के वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 2017 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) शुरू किया गया था। यह प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों/एनबीएफसी के साथ बड़े

सारणी IV.27: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पीएसबी	खातों की संख्या	111.01 (-0.86)	112.96 (1.76)	110.82 (-1.89)	150.77 (36.05)
	बकाया राशि	8,64,597.79 (4.30)	8,80,032.90 (1.79)	8,93,314.83 (1.51)	9,08,659.06 (1.72)
पीवीबी	खातों की संख्या	148.33 (24.03)	205.30 (38.41)	270.62 (31.82)	266.81 (-1.41)
	बकाया राशि	4,10,760.21 (-4.69)	5,63,678.47 (37.23)	6,46,988.27 (14.78)	7,92,041.95 (22.42)
एफबी	खातों की संख्या	2.20 (6.28)	2.40 (9.09)	2.74 (14.17)	2.60 (-5.11)
	बकाया राशि	48,881.34 (33.91)	66,939.13 (36.94)	73,279.06 (9.47)	83,223.79 (13.57)
सभी एससीबी	खातों की संख्या	261.54 (11.95)	320.68 (22.61)	384.18 (19.80)	420.19 (9.37)
	बकाया राशि	13,24,239.35 (2.15)	15,10,650.52 (14.08)	6,13,582.17 (6.81)	17,83,924.80 (10.56)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, आरबीआई।।

²⁸ नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2020-21।

कारपोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों से देय एमएसएमई के वित्तपोषण/ डिस्काउंटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। पिछले चार वर्षों में, ट्रेड्स प्लेटफार्म के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2020-21 के दौरान, मंच के माध्यम से अपलोड और वित्तपोषित चालानों की संख्या में 62 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें सफलता दर²⁹ में सुधार हुआ जो पिछले वर्ष में 90.2 प्रतिशत से बढ़कर 91.3 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.28)। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, केंद्र सरकार द्वारा गैर-कारक एनबीएफसी और अन्य संस्थाओं को फैक्ट्रिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने के साथ, प्लेटफार्म के माध्यम से एमएसएमई को ऋण आपूर्ति में और वृद्धि होने की उम्मीद है। ट्रेड्स पर अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शामिल होने से इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित हो सकता है।

सारणी IV.28 टीआरडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

(चालान संख्या में, राशि ₹ करोड़ में)

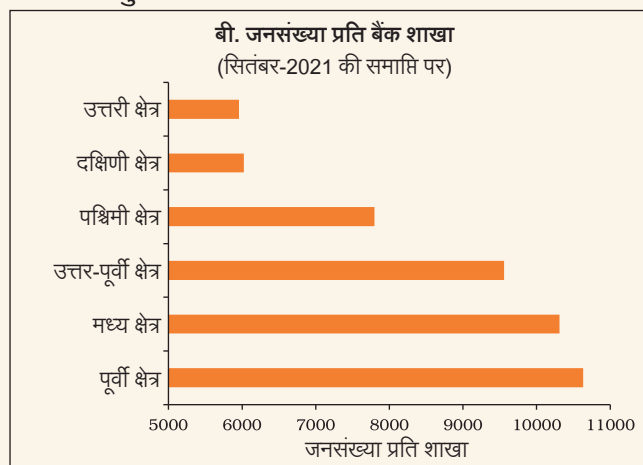
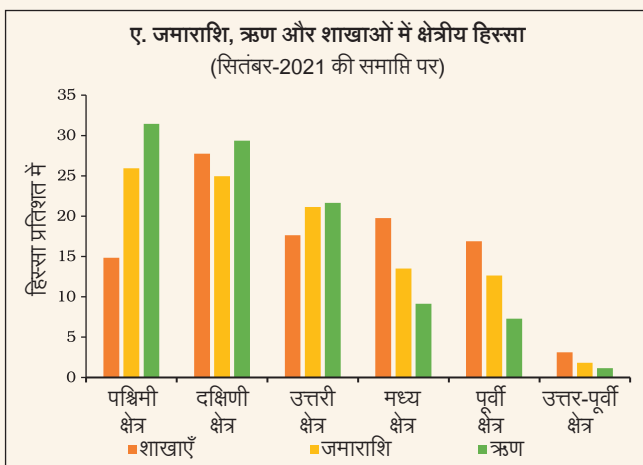
वित्तीय वर्ष	अपलोड किए गए चालान		वित्तपोषित चालान	
	चालान	राशि	चालान	राशि
2017-18	22,704	1,094.82	19,890	814.54
2018-19	2,51,695	6,699.57	2,32,098	5,854.48
2019-20	5,30,077	13,088.27	4,77,969	11,165.86
2020-21	8,61,560	19,669.84	7,86,555	17,080.14

स्रोत: आरबीआई।

12.7 क्षेत्रीय बैंकिंग की पहुंच

IV.90 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच में सुधार के लिए ठोस प्रयासों के बावजूद, पर ऋण, जमा और शाखाओं की संख्या में हिस्सेदारी उप-राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में बैंकिंग आउटरीच पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में अधिक है (चार्ट IV.42ए)। तदनुसार, प्रति बैंक शाखा सेवा प्रदान किए जाने वाली औसत जनसंख्या देश के अन्य भागों के सापेक्ष पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में काफी अधिक रहती है (चार्ट IV.42बी)।

चार्ट IV.42 बैंकों की क्षेत्रीय पहुंच



स्रोत: आरबीआई और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

²⁹ ऐसे इन्वाइस जो अपलोड किए गए और जिन्हें वित्तपोषित किया गया, उनके प्रतिशत के रूप में परिभाषित।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.91 क्रेडिट को-ओपरेटिव समितियों की पहुंच, अपनेपन और ग्रामीण अभिविन्यास और वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिकता के संयोजन से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों और अन्य ग्रामीण गरीबों की आधारभूत बैंकिंग और ऋण आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। आरआरबी का स्वामित्व संयुक्त रूप से भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक के पास है। स्वामित्व का स्वरूप सहकारी संघवाद की भावना का समर्थन

करता है और यथासंभव सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है।

IV.92 अपने समेकन कार्यक्रम के तीसरे चरण के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश में 3 आरआरबी के समामेलन के कारण 2020-21 के दौरान आरआरबी की संख्या 45 से घटकर 43 हो गई। आरआरबी में समामेलन मुहिम ने उनकी लाभप्रदता को बढ़ावा देने में मदद की है और उनके पूंजी आधार को मजबूत करते हुए उनकी आस्ति गुणवत्ता में सुधार किया है (बॉक्स IV.5)।

बॉक्स IV.5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का प्रभाव

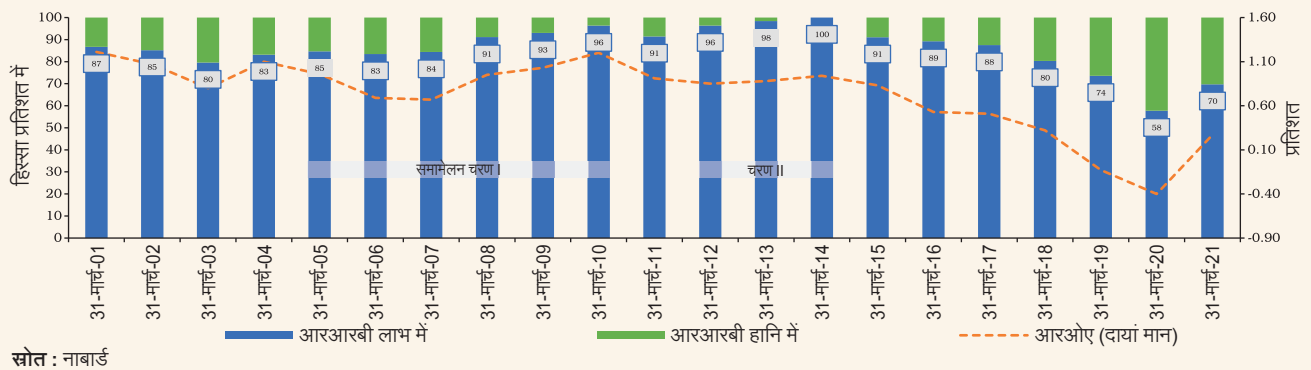
1975 में अपनी स्थापना के बाद से, आरआरबी लगभग दो दशकों तक लाभहीन रहे, सीमित परिचालनगत लचीलापन, विस्तार या विविधीकरण के लिए अपर्याप्त गुंजाइश और छोटे आकार लेकिन उच्च जोखिम वाले ऋण प्रोफाइल से उनकी पहचान सीमित रही। 1994-95 में सरकार ने सुधार किया, जिससे पूंजी निवेश के साथ-साथ उन्हें लाभदायक होने में मदद मिली। हालांकि, मार्च-2005 की समाप्ति तक, 42 प्रतिशत आरआरबी अभी भी घाटे में हैं। उनकी परिचालन व्यवहार्यता में सुधार लाने और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार ने 2005-06 में एक समेकन कार्यक्रम शुरू किया।³⁰

पहले चरण (2005-2010) में, एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक से संबंधित आरआरबी का समामेलन किया गया; दूसरे चरण (2012-2014) में,

एक राज्य के भीतर प्रायोजक बैंकों में आरआरबी का एकीकरण किया गया था। समामेलन का तीसरा चरण 2018-19 में छोटे राज्यों में 'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत पर शुरू किया गया था और बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या में कमी आई थी। नतीजतन, आरआरबी की संख्या 2005 में 196 से घटकर मार्च 2021 के अंत में 43 हो गई, जबकि स्टैंडअलोन आरआरबी की संख्या जो उनकी स्थापना के बाद से कभी भी कोई समामेलन नहीं आया है, घटकर 9 हो गई।

लाभप्रदता पर प्रभाव: लाभकारी और संवहनीय रूप से व्यवहार्य³¹ आरआरबी की हिस्सेदारी में समामेलन के पहले दो चरणों के दौरान लगातार सुधार हुआ (चार्ट 1)।³² कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में संचित हानि की मात्रा में

चार्ट 1 : लाभप्रदता पर समामेलन का प्रभाव



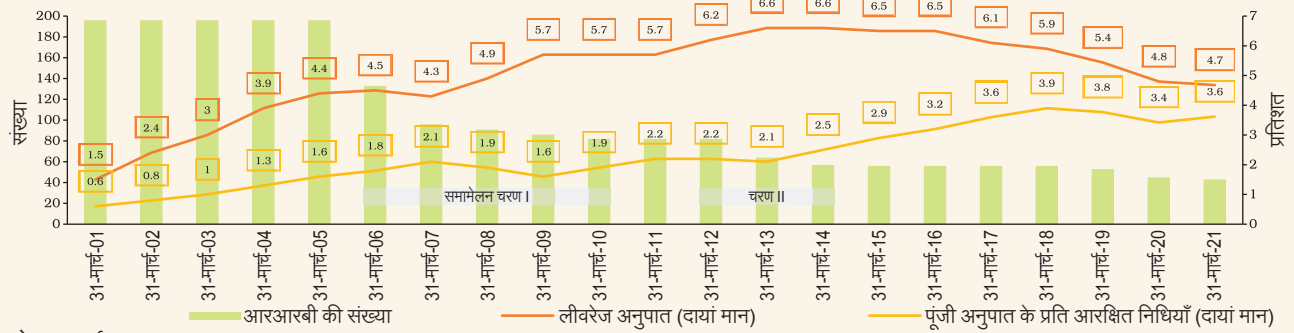
(Contd...)

³⁰ "कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह पर सलाहकार समिति" (डॉ व्यास समिति, 2004) की सिफारिशों और, श्री ए.वी. सरदेसाई की अध्यक्षता में आरआरबी पर आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर समामेलन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

³¹ आरआरबी जिनके पास संचित हानि नहीं है और जिन्होंने चालू वर्ष में निवल लाभ दर्ज किया है।

³² बैंकों की वित्तीय पर समामेलन के तीसरे चरण के प्रभाव का स्वतंत्र रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अप्रैल 2018 से लागू पेंशन योजना का भी एक साथ प्रभाव पड़ा है।

चार्ट 2 : पूंजी तथा लीवरेज पर समामेलन का प्रभाव



स्रोत : नाबार्ड

दो चरणों में गिरावट आई। पहले चरण के दौरान आरओए में तेजी से वृद्धि हुई लेकिन उन्हें दी गई आयकर रियायतों को वापस लेने और आस्ति गुणवत्ता की अधिक मान्यता के कारण 2009-10 के बाद इसमें गिरावट आई।

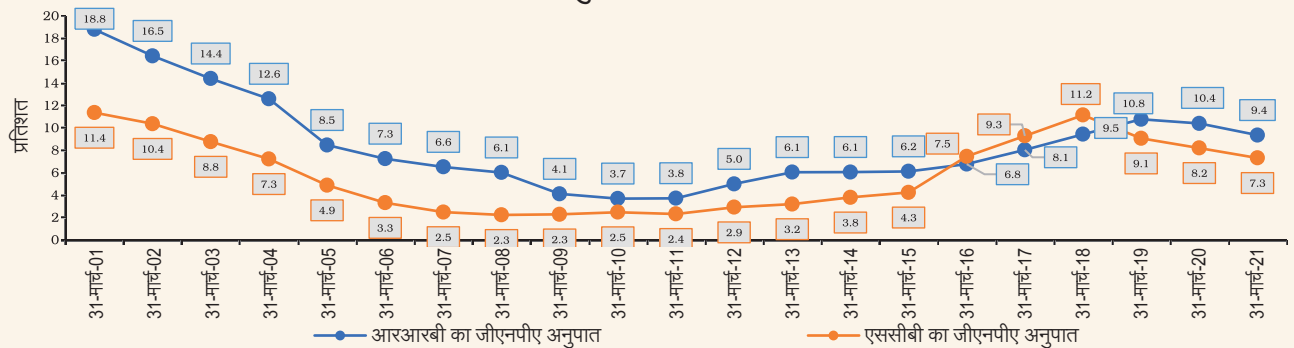
पूंजीगत स्थिति पर प्रभाव: समामेलन के बाद कमजोर बैंकों में पूंजी लगाने से आरआरबी की बेहतर लाभप्रदता ने उनके लीवरेज अनुपात और साथ ही पूंजी के प्रति आरक्षित निधि अनुपात³⁴ को भी बढ़ाया (चार्ट 2)। 9 प्रतिशत सीआरएआर के विनियामक मानक को प्राप्त करने के लिए पुनःपूंजीकरण की आवश्यकता वाले आरआरबी के प्रतिशत में समामेलन के बाद के चरणों में कमी आई है।

आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव: आरआरबी में ऐतिहासिक रूप से एससीबी की तुलना में जीएनपीए अनुपात अधिक है। समामेलन प्रक्रिया के आरंभ से, दोनों के बीच अंतर में कमी आई है और यह आंशिक रूप से आरआरबी में बढ़ती हुई

व्यावसायिक अभिवृत्ति और कार्यक्षेत्र के पैमाने पर प्रभावशीलता को दर्शाती है। एएक्यूआर (आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा) के बाद, जबकि दोनों एससीबी और आरआरबी के जीएनपीए में वृद्धि हुई, बाद में वृद्धि पूर्व की तुलना में कम तेज थी। आरआरबी की यह आस्ति गुणवत्ता में गिरावट एनपीए की अधिक पारदर्शी मान्यता के कारण हुई जो आर्थिक रूप से आकांक्षी क्षेत्रों में केंद्रित थी (चार्ट 3)।

कारोबार मानदंडों पर प्रभाव : समामेलन के प्रथम चरण के दौरान प्रमुख कारोबारी मानदंडों पर औसत बढ़ोतरी दर जैसे ऋण और जमा काफी बढ़ गए। हालांकि ऋण-जमा अनुपात में सुधार सतत रूप से जारी रहा, लेकिन ऋण और जमा में बढ़ोतरी कम उत्साहपरक थी। विमुद्रीकरण के पश्चात जमाओं में जबरदस्त वृद्धि के कारण समामेलन के दूसरे चरण के बाद, ऋण-जमा अनुपात, 2016-17 में गिर गया (चार्ट 4)।

चार्ट 3 : आस्ति गुणवत्ता पर समामेलन का प्रभाव

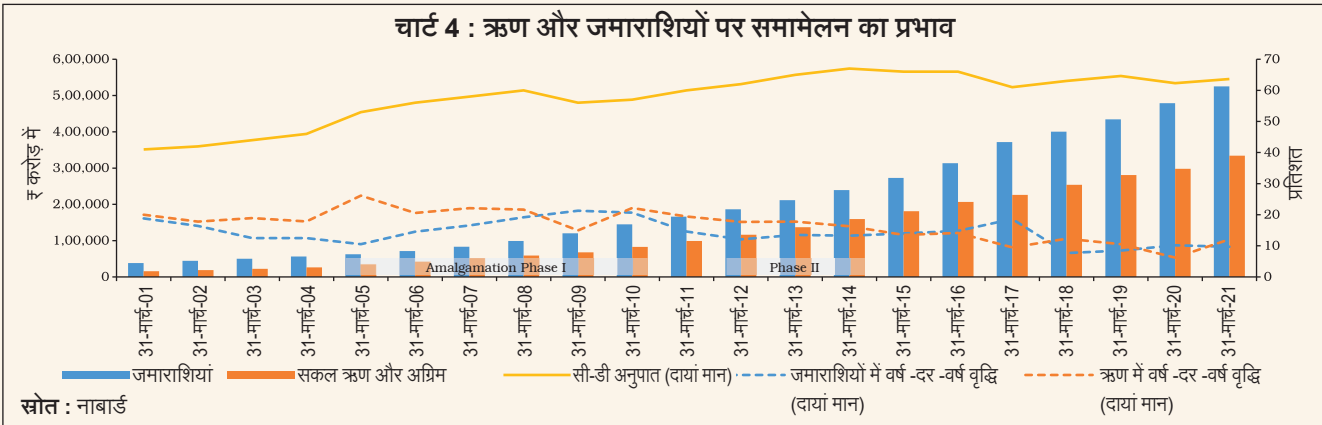


स्रोत : नाबार्ड और डीबीआई, आरबीआई।

(Contd...)

³³ सीआरएआर की अवधारणा केवल 2007 में आरआरबी के लिए शुरू की गई थी, और इसके परिणामस्वरूप, सीआरएआर के आंकड़े समामेलन के पहले की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, आरआरबी की पूंजीगत स्थिति पर समामेलन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, लीवरेज अनुपात और पूंजी के प्रति आरक्षित निधि के अनुपात का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 4 : ऋण और जमाराशियों पर समामेलन का प्रभाव



समामेलन अभियान का एक अतिरिक्त लाभ यह था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिए जाने के संदर्भ में नये रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। सकल ऋण और अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण का हिस्सा समामेलन के पूर्व के चरण के दौरान के 76 प्रतिशत के औसत से बढ़कर, समामेलन पश्चात चरण

के बाद 88 प्रतिशत हो गया। समेकन कार्यक्रम के तीसरे चरण से आरआरबी की लाभप्रदता, पूंजीगत स्थिति और आस्ति गुणवत्ता में आगे और सुधार होने की संभावना है।

13.1 तुलन-पत्र विश्लेषण

IV.93 वर्ष 2020-21 के दौरान, ऐसे 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए ₹400 करोड़ (जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा ₹200 करोड़ था) मंजूर किए गए थे जिनका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत से कम था। पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ आरआरबी ने पुनर्पूजीकरण के लिए राज्य सरकार का अनुमोदित हिस्सा भी प्राप्त किया था। पूंजीकरण और उधार तथा जमाराशियों में बढ़ोतरी के प्रभाव से, आरआरबी की देयताएं वर्ष 2020-21 के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गईं। ऋण ज्यादातर नाबार्ड से प्राप्त किया गया था, और इसके लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) का समर्थन और पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी गई थी।

IV.94 निधियन की उपलब्धता होने से, आरआरबी को एससीबी की दरों से अधिक दर पर, साथ ही उन्हें अपने 10.5 प्रतिशत की 5-वर्षीय औसत वृद्धि की तुलना में अधिक दरों पर उनके क्रेडिट में बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप आरआरबी का सीडी अनुपात मार्च 2020 के अंत में 62.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 63.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि के होने की वजह से भी आरआरबी अपनी अधिक निधियां रिजर्व बैंक के पास नियोजित करने के लिए तत्पर हुए (सारणी IV.29)।

IV.95 कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना आरआरबी के परिचालनों का

सारणी IV.29: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	मार्च की समाप्ति पर		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में	
		2020	2021 ¹	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	7,849	8,393	16.5	6.9
2	आरक्षित निधियाँ	26,814	30,348	5.6	13.2
3	जमाराशियाँ	4,78,737	5,25,226	10.2	9.7
	3.1 चालू	10,750	11,499	-3.4	7.0
	3.2 बचत	2,44,414	2,71,516	9.1	11.1
	3.3 मीयादी	2,23,573	2,42,211	12.2	8.3
4	उधार	54,393	67,864	1.6	24.8
	4.1 नाबार्ड से	46,120	61,588	-1.6	33.5
	4.2 प्रायोजक बैंक	4,519	3,444	20.6	-23.8
	4.3 अन्य	3,754	2,832	28.7	-24.6
5	अन्य देयताएँ	20,227	19,754	13.2	-2.3
	कुल देयताएँ/आस्तियाँ	5,88,021	6,51,585	9.3	10.8
6	उपलब्ध नकदी	2,860	2,954	-1.8	3.3
7	भा.रि. बैंक में उपलब्ध जमाशेष	16,744	18,947	-6.4	13.2
8	चालू खाता के जमाशेष	7,613	5,987	39.2	-21.4
9	निवेश	2,50,859	2,75,658	10.9	9.9
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	2,80,220	3,15,181	7.0	12.5
11	अचल संपत्ति	1,235	1,229	-3.0	-0.5
12	अन्य आस्तियाँ#	28,490	31,629	27.7	11.0
	12.1 संचित हानि	6,467	8,264	124.0	27.8

टिप्पणियाँ: 1. #: इसमें संचित हानि भी शामिल है।

2. पी - अनंतिम

3. ₹ करोड़ के आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है। निरपेक्ष अंकों को रकरोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।

स्रोत : नाबार्ड

**सारणी IV.30: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा
दिए गए उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्देश्य	2020	2021 ^{पी}
1	2	3	4
I	प्राथमिकता (i से v)	2,70,182	3,00,962
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	90.6	90.1
	i कृषि	2,08,762	2,33,145
	ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	35,240	39,543
	iii शिक्षा	2,358	2,132
	vi आवास	19,814	21,127
	v अन्य	4,008	5,016
II	गैर-प्राथमिकता (i से vi)	28,032	33,209
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	9.4	9.9
	i कृषि	9	29
	ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	495	434
	iii शिक्षा	74	92
	iv आवास	3,538	4,347
	v वैयक्तिक ऋण	7,069	8,311
	vi अन्य	16,847	19,996
	कुल (I+II)	2,98,214	3,34,171

टिप्पणियाँ: 1. अ : अनंतिम
2. ₹ करोड़ के आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ भिन्न हो सकता है।
स्रोत : नाबार्ड

आधारभूत कार्य है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आरआरबी के कुल ऋण और अग्रिमों में से कृषि क्षेत्र को ऋण 70 प्रतिशत था (सारणी IV.30)। यद्यपि उनकी कुल ऋण आस्तियों का आकार एससीबी के संदर्भ में केवल 3.3 प्रतिशत ही है लेकिन इस क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए उनके ऋण एससीबी के अग्रिमों का 16.8 प्रतिशत है। 3 आरआरबी को छोड़कर, सभी आरआरबी ने पूर्ववर्ती वर्ष के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एएनबीसी (समायोजित निवल बैंक ऋण) के 75 प्रतिशत से अधिक उधारियों के साथ, वर्ष 2020-21 के दौरान अपने लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक का स्तर हासिल किया (परिशिष्ट सारणी IV.15)।

13.2 आरआरबी का कार्य-निष्पादन

IV.96 वर्ष 2020-21 के दौरान, आरआरबी ने समग्र रूप से पूर्ववर्ती दो वर्षों में हानि उठाने के बाद सकारात्मक परिवर्तन के साथ, निवल लाभ रिपोर्ट किया हालांकि जो ब्याज से होने वाली आय में कमी होने के बावजूद, उनके ब्याज व्यय में कमी आने के प्रभाव से हुई (सारणी IV.31)। साथ ही पीएसएलसी की बिक्री के जरिए उनके आय को बढ़ाने के लिए, आरआरबी ने अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संविभाग (विशेषकर कृषि) के उच्च स्तर को प्रभावी रूप से उपयोग में लाया। वर्ष 2020-21

**सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का
वित्तीय कार्यनिष्पादन**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	राशि	वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में परिवर्तन		
1	2	2019-20	2020-21 ^{पी}	2019-20	2020-21
ए	आय (i + ii)	49,452	53,858	15.0	8.9
	i ब्याज से होने वाली आय	43,698	46,803	12.2	7.1
	ii अन्य आय	5,754	7,055	41.8	22.6
बी	व्यय (i+ii+iii)	51,660	52,176	18.4	1.0
	i व्यय की गई ब्याज की राशि	25,985	25,588	9.6	-1.5
	ii परिचालनगत व्यय	20,076	19,768	45.4	-1.5
	जिसमें से, वेतन बिल	14,654	15,101	56.2	3.0
	iii प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	5,599	6,819	-8.5	21.8
	जिसमें से, आयकर	931	1,279	12.3	37.5
सी	लाभ				
	i परिचालनगत लाभ	2,972	8,304	-45.6	179.5
	ii निवल लाभ	-2,208	1,682	-	-
डी	कुल औसत आस्तियाँ	5,55,660	6,17,305	7.2	11.1
ई	वित्तीय अनुपात#				
	i परिचालन लाभ	0.5	1.3		
	ii निवल लाभ	-0.4	0.3		
	iii आय (ए + बी)	8.9	8.7		
	(ए) ब्याज से होने वाली आय	7.9	7.6		
	(बी) अन्य आय	1.0	1.1		
	iv व्यय (ए+बी+सी)	9.3	8.5		
	(ए) खर्च की गई ब्याज राशि	4.7	4.1		
	(बी) परिचालनगत व्यय	3.6	3.2		
	जिसमें से, वेतन बिल	2.6	2.4		
	(सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	1.0	1.1		
एफ	विश्लेषणात्मक अनुपात (%)				
	सकल अनर्जक अस्तित्व अनुपात	10.4	9.4		
	सीआरएआर	10.3	10.2		

टिप्पणियाँ: 1. पी- अनंतिम.
2. # औसत कुल आस्तियों के संबंध में वित्तीय अनुपात प्रतिशत को दर्शाता है।
3. संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण कुल जोड़ भिन्न हो सकता है और प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है।
4. प्रावधान और आकस्मिक व्यय में आयकर के लिए प्रावधान / अदा किया गया आयकर शामिल है।
स्रोत : नाबार्ड।

के दौरान, आरआरबी के द्वारा पीएसएलसी की ट्रेड की गई कुल प्रमात्रा 26 प्रतिशत तक बढ़ गई और यह सभी बैंकों द्वारा पीएसएलसी की ट्रेड की गई कुल प्रमात्रा का 33 प्रतिशत थी।

IV.97 हालांकि वर्ष 2020-21 के दौरान, 43 में से 30 आरआरबी ने निवल लाभ दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी IV.14), लेकिन 17 आरआरबी ने यथा मार्च 2021 के अंत में ₹8264 करोड़ की संचित हानि दर्ज की, और उनमें से 16 आरआरबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से कम था।

IV.98 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए ₹1200 करोड़ आवंटित किए हैं और इससे उनकी पूंजी के सुरक्षित भंडार को आगे मजबूती मिलने के आसार हैं और इससे उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्गों को ऋण संवितरण में वृद्धि होगी।

IV.99 धोखाधड़ी संवेदनशीलता सूचकांक (वीआईएनएफआरए) जो धोखाधड़ी प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करता है, के अनुसार 42 आरआरबी में से (जिनका 2020-21 के लिए डाटा उपलब्ध है) 41 आरआरबी श्रेणी ए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जो न्यूनतम असुरक्षितता को दर्शाते हैं। यद्यपि यह एक स्व-आकलन का साधन है, इसलिए यह श्रेणीकरण किसी धोखाधड़ी के प्रति बैंक की असुरक्षितता की संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं सकता। दूसरी ओर वर्ष 2020-21 के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के स्व-आकलन के साधन, संवेदनशीलता सूचकांक (वीआईसीएस) के अनुसार 43 आरआरबी में से केवल 21 आरआरबी श्रेणी ए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जबकि 6 आरआरबी श्रेणी सी के तहत शामिल किए गए हैं, यह साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क (सीएसएफ) को मजबूत करने की आवश्यकता दर्शाता है।

14. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.100 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के तौर पर स्थापना की गई थी और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बचतों को एकत्रित करने के लिए स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाना था और स्थानीय क्षेत्रों में (3 निकटस्थ जिला शहर तक) संस्थागत ऋण प्रणाली को मजबूत करना था। वर्ष 2020-21 के दौरान रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा स्थानीय क्षेत्र बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए और इसके परिणामस्वरूप देश में कार्यशील एलएबी की संख्या घटकर दो रह गई जो यथा मार्च 2021 के अंत में एससीबी की कुल आस्तियों का केवल 0.006 प्रतिशत है।

IV.101 एलएबी का समेकित तुलन-पत्र वर्ष 2020-21 के दौरान विस्तारित हुआ, हालांकि उनका ऋण-जमा अनुपात 81 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा (सारणी IV.32)।

सारणी IV.32: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफाइल (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21
1. आस्तियां	1026.0 (10.8)	1170.8 (14.1)
2. जमाराशियाँ	813.8 (9.0)	952.5 (17.0)
3. सकल अग्रिम	660.5 (18.0)	769.2 (16.5)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, आरबीआई।

14.1 स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

IV.102 वर्ष 2020-21 के दौरान एलएबी की लाभप्रदता में सुधार हुआ, परिचालनगत व्यय में कमी आई, विशेषकर वेतन बिल के संदर्भ में जो ब्याजेतर आय से अधिक मात्रा में रहे, के कारण लाभप्रदता अनुपात में बढ़ोतरी हुई (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन (मार्च के अंत में)

	राशि (₹ करोड़ में)		वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत में	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1. आय (i+ii)	135	148	14.9	9.5
i. ब्याज से होने वाली आय	107	123	10.6	14.8
ii. अन्य आय	28	25	35.0	-10.4
2. व्यय (i+ii+iii)	121	122	13.9	0.2
i. व्यय की गई ब्याज राशि	52	55	14.8	6.5
ii. प्रावधान एवं आकरिमिक निधियाँ	13	20	53.8	47.1
iii. परिचालनगत व्यय जिसमें से, वेतन बिल	56 26	47 22	6.7 8.1	-16.7 -15.9
3. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ/हानि	27	46	37.3	69.7
ii. निवल लाभ/हानि	14	27	24.6	91.3
4. निवल ब्याज आय	55	68	6.9	22.7
5. कुल आस्तियाँ	1026	1171	10.8	14.1
6. वित्तीय अनुपात @				
i. परिचालन लाभ	2.7	3.9		
ii. निवल लाभ	1.4	2.3		
iii. आय	13.2	12.7		
iv. ब्याज से होने वाली आय	10.4	10.5		
v. अन्य आय	2.8	2.2		
vi. व्यय	11.8	10.4		
vii. खर्च की गई ब्याज राशि	5.0	4.7		
viii. परिचालनगत व्यय	5.5	4.0		
ix. वेतन बिल	2.6	1.9		
x. प्रावधान एवं आकरिमिक निधियाँ	1.3	1.7		
xi. निवल ब्याज आय	5.4	5.8		

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वित्तीय अनुपात की गणना केवल संबंधित वर्ष की आस्तियों के आधार पर की गई है।
2. 'वेतन बिल' कर्मचारियों को किए गए भुगतान और उनके लिए किए गए प्रावधानों के रूप में लिए गए हैं।
3. @ पिछले दो वर्षों की औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुपात
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, आरबीआई।

15. लघु वित्त बैंक

IV.103 लघु वित्त बैंक (एसएफबी) 2016 से अल्पसेवा वाले वर्गों को बचत के साधन के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं और साथ ही उच्च प्रौद्योगिकी वाली कम लागत के परिचालनों के जरिए छोटे उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन बैंकों द्वारा उनके एनबीसी (समायोजित निवल बैंक ऋण) का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करने की संभावना है, साथ जिनमें से ₹25 लाख से कम की राशिवाले ऋण की मात्रा कम से कम 50 प्रतिशत होगी। देश में नवंबर 2021 के दौरान बारह एसएफडब्ल्यू कार्यशील थे जिनमें शिवालिक स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड और यूनिटी स्माल फाईनेंस बैंक शामिल हैं जिन्हें हाल ही में लाईसेंस जारी किया गया है।

15.1 एसएफबी का तुलन-पत्र

IV.104 उद्भव के बाद से ही एसएफबी का समेकित तुलन-पत्र एससीबी की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ रहा है, जो उनके परिचालनों में अस्वाभाविक संवृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान इसे देयताओं के संदर्भ में उच्चतर जमाओं से समर्थन मिला। एसएफबी द्वारा बचत खातों में आकर्षक ब्याज दर प्रस्तावित किया गया और उनकी कुल जमाओं में कासा जमा राशियों का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 15.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 23.9 प्रतिशत हो गया। निवेशों में अधिक अनुवृद्धि से आस्तियों में बढ़ोतरी हुई। यद्यपि ऋण और अग्रिम इसका प्रमुख घटक था, - कुल आस्तियों का 66 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ - उनकी बढ़ोतरी मंद रही जो समग्र रूप से प्रणालीगत क्रेडिट वृद्धि में कमी को इंगित करती है (सारणी IV.34)।

15.2 लघु वित्त बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

IV.105 वर्ष 2021 के दौरान एसएफबी के कुल उधार की अंश धारिता में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई है। मार्च 2021 के अंत में कुल ऋणों में से गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र हिस्सा 28 प्रतिशत से अधिक था। एसएफबी ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्र में रहे, यद्यपि उनकी अंशधारिता में कमी आई है (सारणी IV.35)।

सारणी IV.34: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	2020	2021	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) 2020-21
1 शेयर पूंजी	5,150.9	5,375.4	4.4
2 आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	11,046.9	14,800.3	34.0
3 टिअर II बॉण्ड	3,795.4	2,468.0	-35.0
4 जमाराशियाँ	82,487.8	1,09,472.5	32.7
4.1 चालू मांग जमाराशियाँ	2,381.2	3,964.2	66.5
4.2 बचत	10,283.5	22,198.3	115.9
4.3 मीयादी	69,823.0	83,310.0	19.3
5 उधारियाँ (टिअर II बॉण्ड सहित)	30,004.2	27,828.2	-7.3
5.1 बैंक	3,783.8	1,366.4	-63.9
5.2 अन्य	26,220.5	26,461.8	0.9
6 अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	4,078.4	6,076.3	49.0
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	1,32,768.2	1,63,552.5	23.2
7 उपलब्ध नकद राशि	975.9	1,052.2	7.8
8 आरबीआई के पास शेष राशि	4,082.4	5,869.2	43.8
9 अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास शेष राशि	8,700.9	12,309.1	41.5
10 निवेश	24,203.1	30,659.8	26.7
11 ऋण एवं अग्रिम	90,576.1	1,08,612.6	19.9
12 स्थायी आस्तियाँ	1,649.3	1,676.3	1.6
13 अन्य आस्तियाँ	2,580.4	3,373.2	30.7

टिप्पणी: यह डेटा मार्च 2021 की समाप्ति पर परिचालनगत 10 एसएफबी से संबन्धित है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15.3 लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

IV.106 वर्ष 2020-21 में परिचालन लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद, अशोध्य और पुनर्चित ऋणों के उच्च प्रावधान

सारणी IV. 35: लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम (कुल अग्रिम में हिस्सेदारी)

उद्देश्य	31-मार्च -20	31-मार्च -21
I प्राथमिकता (i से v)	76.0	71.8
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत		
i. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	22.1	21.8
ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	34.4	25.9
iii. शिक्षा	0.1	0.1
iv. आवास	3.8	4.3
v. अन्य	15.7	19.7
II गैर-प्राथमिकता (i से vi)	24.0	28.2
कुल (I+II)	100.0	100.0

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.36: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)				
क्र. मद सं.	2020	2021	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) 2020-21	
1	2	3	4	5
ए आय (i + ii)	19,219.1	22,499.9	17.1	
i ब्याज से होने वाली आय	16,947.9	19,523.4	15.2	
ii अन्य आय	2,271.2	2,976.4	31.1	
बी व्यय (i+ii+iii)	17,251.1	20,462.2	18.6	
i खर्च की गई ब्याज की राशि	7,927.7	9,122.2	15.1	
ii परिचालनगत व्यय	7,152.0	7,549.0	5.6	
जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	3,811.2	4,301.8	12.9	
iii प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	2,171.5	3,791.0	74.6	
सी लाभ (कर से पहले)	2,678.6	2,580.9	-3.6	
i परिचालनगत लाभ (आईबीपीटी)	4,141.4	5,828.7	40.7	
ii निवल लाभ (पीएटी)	1,969.9	2,037.7	3.4	
डी कुल आस्तियाँ	1,32,768.2	1,63,552.5	23.2	
ई वित्तीय अनुपात #				
i परिचालनगत लाभ	3.1	3.6		
ii निवल लाभ	1.5	1.2		
iii आय (ए + बी)	14.5	13.8		
ए. ब्याज से होने वाली आय	12.8	11.9		
बी. अन्य आय	1.7	1.8		
iv व्यय (ए+बी+सी)	13.0	12.5		
ए. खर्च की गई ब्याज की राशि	6.0	5.6		
बी. परिचालनगत व्यय	5.4	4.6		
जिसमें से स्टाफ पर व्यय	2.9	2.6		
सी. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	1.6	2.3		
एफ विशेषणात्मक अनुपात (%)				
सकल अनर्जक अस्तित्व अनुपात	1.9	5.4		
सीआरएआर	20.2	22.1		
मुख्य सीआरएआर	17.2	20.1		

टिप्पणी: # कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

के कारण एसएफबी के निवल लाभ में वृद्धि सामान्य रही। जीएनपीए अनुपात लगभग तीन गुना हो गया जो कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाता है। उच्च गुणवत्ता वाली टिअर-1 पूंजी के आधार से पूंजी की स्थिति (सीआरएआर) में सुधार आया (सारणी IV.36)।

16. भुगतान बैंक

IV.107 भुगतान बैंकों (पीबी) को विशिष्ट बैंकों के रूप में स्थापित किया गया था जो वित्तीय समावेशन के लिए तकनीकी की सेवाओं के द्वारा असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायों, कम आय वाले परिवारों और अन्य संस्थाओं को कम लागत वाले बैंकिंग समाधान उपलब्ध करा सकें। मार्च 2021 के अंत तक देश में छह पीबी परिचालन में थे। वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत पीबी को ऋण देने के कार्यकलापों की अनुमति नहीं है तथा प्रति ग्राहक जमा पर भी प्रतिबंध हैं। अप्रैल 2021 में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रति ग्राहक अधिकतम जमा सीमा को ₹1 लाख से ₹2 लाख बढ़ाने के कदम से अपेक्षा है कि इन बैंकों के परिचालन में अधिक लचीलापन आएगा।

16.1 भुगतान बैंकों (पीबी) के तुलनपत्र

IV.108 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र में स्थिर वृद्धि के विपरीत 2020-21 में पीबी के तुलन-पत्र में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2019-20 में अधिकतम 17.5 प्रतिशत थी। यह वृद्धि देयताओं के संदर्भ में जमा और आस्तियों के संदर्भ में निवेश से हुई (सारणी IV.37)। कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा एक वर्ष पूर्व के 27.4 प्रतिशत से बढ़कर

सारणी IV.37: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्र. मद सं.	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21
1. कुल पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	1,899	1,868	1,792
2. जमाराशियाँ	882	2,306	4,622
3. अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	4,392	4,254	6,133
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	7,172	8,429	12,547
1. आरबीआई के पास नकदी एवं शेष	712	785	1,255
2. बैंकों और मुद्रा बाज़ार में शेष राशि	1,375	2,101	2,413
3. निवेश	3,136	4,077	7,102
4. स्थायी आस्तियाँ	638	351	355
5. अन्य आस्तियाँ	1,311	1,115	1,421

टिप्पणी: मार्च 2019 के अंत, मार्च-2020 के अंत और मार्च-2021 के अंत के आंकड़ें क्रमशः 7,6 तथा 6 पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार किसी भी वर्ष में आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

36.8 प्रतिशत हो गया और जमा अधिशेष सीमा में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से जमा आधार में और अधिक विस्तार होने की उम्मीद है।

16.2 पीबी का वित्तीय प्रदर्शन

IV.109 पीबी अभी भी विकास के प्रारम्भिक चरण में हैं तथा आधारभूत ढांचा विकसित करने में बड़ा निवेश कर रहे हैं। साथ ही उनके ग्राहकों का आधार अभी भी पूरी तरह से विकसित किया जाना है जिससे संतुलन बिंदु की स्थिति में पहुंचने में चुनौतियाँ आ रही हैं। परिणामस्वरूप शुरुआत से ही उन्हें घाटा हो रहा है। वर्ष 2020-21 में भी उनकी ब्याजेतर आय में सुधार होने के बावजूद भी यही स्थिति परिलक्षित हो रही है (सारणी IV.38)।

IV.110 वर्ष 2020-21 में पीबी की दक्षता का आकलन किया गया जिसके अनुसार लागत-आय अनुपात में सुधार हुआ जबकि उनके एनआईएम में कमी आई। अन्य निष्पादन मानकों जैसे लाभ मार्जिन, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और कार्यशील

सारणी IV.38: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्र. मद सं.	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21
ए आय (i+ii)			
i. ब्याज से होने वाली आय	291	348	360
ii. गैर-ब्याज से होने वाली आय	2,099	3,115	3,562
बी व्यय			
i. खर्च की गई ब्याज की राशि	35	62	100
ii. परिचालनगत व्यय	3,265	4,324	4,584
प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ जिसमें से,	26	-96	36
जोरिम प्रावधान	2	3	9
कर प्रावधान	16	-100	22
सी निवल ब्याज आय	255	286	260
डी लाभ			
i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	-911	-923	-762
ii. निवल लाभ/हानि	-937	-827	-798

टिप्पणी: मार्च 2019 के अंत, मार्च-2020 के अंत और मार्च-2021 के अंत के ये आंकड़े क्रमशः 7, 6 तथा 6 पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार यह आंकड़े वर्षवार तुलन योग्य नहीं हैं।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों के चयनित वित्तीय अनुपात

क्र. मद सं.	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21
1 आस्तियों पर प्रतिलाभ	-13.1	-9.8	-6.4
2 इक्विटी पर प्रतिलाभ	-49.4	-44.3	-44.5
3 कुल आस्तियों की तुलना में निवेश	43.7	48.4	56.6
4 निवल ब्याज मार्जिन	6.1	4.8	2.8
5 दक्षता (लागत-आय अनुपात)	136.6	124.8	116.9
6 कार्यशील पूंजी पर परिचालन लाभ	-12.7	-10.9	-6.1
7 लाभ मार्जिन	-39.2	-23.9	-20.3

टिप्पणी: मार्च 2019 के अंत, मार्च-2020 के अंत और मार्च-2021 के अंत के ये आंकड़े क्रमशः 7, 6 तथा 6 पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार यह आंकड़े वर्षवार तुलन योग्य नहीं हैं।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

पूंजी से परिचालन लाभ अनुपात ऋणात्मक रहा, यद्यपि हानि की प्रमात्रा कम रही (सारणी IV.39)।

16.3 पीबी के आवक और जावक विप्रेषण

IV.111 वर्ष 2020-21 में पीबी के कुल आवक और जावक विप्रेषणों में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में 20 प्रतिशत से अधिक गिरावट हुई। छोटे मूल्य एवं बड़ी मात्रा के लेनदेनों के परिचालन के उच्च स्तर को देखते हुए कुल विप्रेषण कारोबार में यूपीआई का अंश लगातार तीसरी बार सबसे अधिक रहा, इसके बाद आईएमपीएस और ई-वालेट रहे (सारणी IV.40)।

17. समग्र आकलन

IV.112 वैश्विक और देशी समष्टि आर्थिक स्थितियों में तीव्र गिरावट होने के बावजूद, भारत में बैंकिंग क्षेत्र मजबूत लाभप्रदता संकेतक और बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ आघात-सहनीय बना रहा। महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने, बैंकों के तुलनपत्र को सुरक्षित रखने, आवश्यक चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने और वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न विनियामक उपाय शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बैंकों के तुलनपत्र पर दबाव कम करने के लिए राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एनएआरसीएल) की

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण

(संख्या हजार में, राशि ₹ करोड़ में)

चैनल	2019-20				2020-21			
	आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण		आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. एनईएफटी	898 (0.4)	19,398 (5.3)	1,408 (0.6)	43,593 (10.1)	1,389 (0.9)	26,295 (9.8)	826 (0.5)	60,649 (19.8)
i) बिल भुगतान	63 (0.0)	6,103 (1.7)	421 (0.2)	8,151 (1.9)	9 (0.0)	17 (0.0)	23 (0.0)	28 (0.0)
ii) बिल भुगतान को छोड़कर अन्य	835 (0.4)	13,295 (3.6)	987 (0.4)	35,442 (8.2)	1,380 (0.8)	26,278 (9.8)	803 (0.5)	60,621 (19.8)
2. आरटीजीएस	20 (0.0)	81,411 (22.2)	7 (0.0)	56,794 (13.2)	19 (0.0)	56,460 (21.0)	2 (0.0)	35,107 (11.4)
3. आईएमपीएस	14,069 (6.8)	34,309 (9.3)	34,522 (15.0)	1,05,366 (24.5)	13,627 (8.3)	37,466 (14.0)	18,988 (11.1)	65,866 (21.5)
4. यूपीआई	1,44,227 (69.4)	1,70,998 (46.6)	1,45,370 (63.2)	1,60,976 (37.4)	1,17,270 (71.8)	1,13,289 (42.2)	1,20,069 (70.3)	1,03,908 (33.9)
5. ई-वॉलेट	33,960 (16.3)	23,427 (6.4)	40,316 (17.5)	41,274 (9.6)	23,162 (14.2)	20,406 (7.6)	30,150 (17.7)	38,317 (12.5)
6. माइक्रो एटीएम (पीओएस)	4,736 (2.3)	16,746 (4.6)	69 (0.0)	229 (0.1)	3 (0.0)	20 (0.0)	14 (0.0)	45 (0.0)
7. एटीएम	-	-	375 (0.2)	1,169 (0.3)	-	-	1 (0.0)	3 (0.0)
8. अन्य	10,045 (4.8)	20,740 (5.7)	7,840 (3.4)	21,515 (5.0)	7,821 (4.8)	14,384 (5.4)	719 (0.4)	2,866 (0.9)
कुल	2,07,955	3,67,030	2,29,908	4,30,916	1,63,292	2,68,321	1,70,768	3,06,761

टिप्पण : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल के प्रतिशत के रूप में हैं। शून्य / नगण्य

2. मार्च 2020 और मार्च-2021 के अंत के ये आंकड़ें क्रमशः 6 पीबी से संबंधित हैं।

स्रोत : ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

स्थापना की, जिससे वसूली की प्रक्रिया में सहायता मिलने की आशा है।

IV.113 जोखिमों से बचने एवं वर्ष 2020-21 के दौरान मांग संबंधी स्थितियों में शिथिलता के कारण बैंकों द्वारा ऋणों उठाव में गिरावट रही। कोविड-19 की दूसरी लहर की छाया से अर्थव्यवस्था के उबरने की प्रक्रिया में होने के बाद वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में उत्तरोत्तर वृद्धि शुरू हुई। इसके अलावा बैंकों के तुलनपत्र में पुनरुत्थान समग्र आर्थिक वृद्धि के इर्दगिर्द ही रही जो महामारी के समय की प्रगति से संबद्ध रहा। बैंकों को गिरावट को सहने और ऋण प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपनी पूंजी की स्थिति को और मजबूत बनाना होगा विशेषतः उस स्थिति में जब मौद्रिक और राजकोषीय उपाय तेज गति से

उपयोग में लाए जा रहे हों। यद्यपि अधिकांश विनियामक रियायती उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है तथापि बैंकों पर उनका पूरा असर दिखने में समय लगेगा।

IV.114 बैंकों को अपनी कार्पोरेट अभिशासन प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों को और मजबूत बनाना होगा जिससे बढ़ते हुए गतिशील और अनिश्चित आर्थिक वातावरण में आघात सहनीयता विकसित की जा सके। डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तीव्र तकनीकी उन्नयन और फिनटेक इकोसिस्टम के सभी स्तरों पर नए भागीदारों के उदय होने से बैंकों को अपने सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन करने और ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने को प्राथमिकता देनी होगी तथा साइबर सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा।